राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: **2** सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का चौदहवां दिवस संख्या: **7**

मंगलवार,
16 जुलाई 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: राम, राम, जय श्रीराम। प्रश्नकाल।

प्रश्न संख्या 86

श्री बहादुर सिंह।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री रोहित बोहरा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। मुख्य मंत्री जी के गृह जिले का और माननीय सदस्य ही नहीं आये।

श्री अध्यक्ष: कल भी दो-तीन नहीं थे, इधर के भी और उधर के भी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

माननीय अध्यक्ष महोदय की धर्मपत्नी के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सबकी तरफ से पूछना चाहूंगा कि आपकी धर्मपत्नी जी, हमारी भाभीजी की तबीयत कैसी है? उनको रात को हॉस्पिटल में रश कर दिया गया था। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी से स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हों।

श्री अध्यक्ष: इलाज चल रहा है। आपकी दुआओं से उम्मीद है कि जल्दी ठीक होंगी।

श्री रोहित बोहरा।

प्रदेश में स्टेट हाईवे की एमडीआर व बीआर सड़कों का नवीनीकरण

87. श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में स्टेट हाईवे की एमडीआर एवं बीआर सड़कों का नवीनीकरण कितने वर्षों में

कार्यवाही वृत्तान्त में प्रयुक्त संकेताक्षर

+++: शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

000: अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

करने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में विगत तीन वर्षों में उक्त सड़कों का नवीनीकरण किया गया है? यदि हां, तो कितनी सड़कों का तथा नहीं, तो क्यों? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) प्रदेश में स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर एवं वीआर सड़कों के नवीनीकरण के मापदण्ड राजस्थान राज्य सड़क विकास नीति 2013 के अनुसार निर्धारित हैं। राजस्थान राज्य सड़क विकास नीति 2013 की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां, विगत तीन वर्षों में उक्त सड़कों यथा स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर एवं वीआर सड़कों का किया गया नवीनीकरण का वर्षवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): I have gone through the details. मैंने आपकी सड़क नीति भी पढ़ ली है। I have now two questions to ask.

श्री अध्यक्ष: हिन्दी में बोलिये। ये आपसे सीधे पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैडम, मैं आपसे दो पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने आपका आंसर पढ़ लिया है। मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या आप सभी श्रेणी की सड़कों का जो नवीनीकरण कर रहे हैं, are you adhering to the norms? जो आपने नार्म्स अपनी सड़क नीति में दिये हैं, चार साल, छ साल, आठ साल, क्या आपने सभी सड़कों पर ये **एडहर** किये हैं? चार साल, पांच साल, छ साल और आठ साल, यह मेरा पहना प्रश्न है।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि आपने पिछले तीन सालों की नवीनीकरण की पूरी लिस्ट मांग है, प्रदेश में कितना नवीनीकरण हुआ है, प्रदेश में सड़कों का। माननीय अध्यक्ष जी, तीन साल से तो आपकी ही सरकार थी, हम लोग तो अभी आये हैं। मैं सदन को पूरा आश्वस्त करती हूं..।

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न गया।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): Madam, I am asking a question. I am not asking any political question. मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: जो उत्तर मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, उसको पूरा सुन लीजिये। फिर आप प्रश्न करना। जो मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, उसको चुपचाप सुनना है। माननीय, आप बोलिये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): सुनना तो पड़ेगा, अगर तीन साल की सूची मांगेंगे तो। ऐसा है, गत तीन वर्षों में जैसा मैंने बताया, आपकी सरकार थी और बहुत कम नवीनीकरण हुआ है, आपका प्रश्न बिलकुल सही था। हम सभी को चिन्ता है कि ऐसा क्यों हुआ लेकिन आपको आश्वस्त करना चाहूंगी कि इस बजट में लगभग 9 हजार करोड़ रुपये से सड़कों का निर्माण, नवीनीकरण एवं उन्नयन प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मैंने जो क्वेश्चन किया है। मैं सिर्फ उसका आंसर चाह रहा हूं। मैं यहां पर कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं चाह रहा हूं। मैं क्वेश्चन का आंसर चाहता हूं। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैंने इनसे यह पूछा जो नार्म्स हैं, जो आपकी सड़क नीति बनी हुई है। क्या आपके नार्म्स को एडहर कर रहे हो? Are you following those norms or not? मेरा सिम्पल-सा क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): बिलकुल हम लोग उसको फॉलो कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझसे मिलें। यदि आपकी ऐसी विशेष सड़कें हैं, जो आपको लगता है, तीन सालों में ध्यान नहीं दिया गया। वैसे तो यह समस्या पूरे प्रदेश की है और हमारी सरकार पूरी तरह से काम भी करेगी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैडम, मेरे यहां न तो सड़क की कोई प्रोब्लम है, ना आपसे मांग रहा हूं। आपने जो 9 हजार करोड़ का बजट दिया है, उसमें से 2 हजार करोड़ सेंट्रल सरकार के हैं, आपके नहीं हैं! यह भी आपको बता देता हूं।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): वहां भी राजग की ही सरकार है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये। पैसा किसका, कहां, कैसा इसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। यहां भी था, वहां भी है, यह भी आपका ही पैसा है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जब वे ऐसे जवाब दे रही हैं तो मैं भी वैसे ही जवाब दूंगा। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या आपने सभी सड़कों का जो नवीनीकरण किया है, जो एज पर सड़क नीति आपने सभी सड़कों का नवीनीकरण किया है। आपने मुझे अभी लम्बाई का आंसर दिया है। आपने न तो इसमें सड़क का नाम लिया कि कौन-कौन सी सड़कों का हमने नवीनीकरण किया है। आपने जिस्ट बनाकर भेज दी, पूरे राजस्थान की भाई इतने लम्बाई की सड़क, लम्बाई आपने मेरे ख्याल से 12 हजार 181 किलोमीटर की, ये जो हमने सड़कों का नवीनीकरण किया है, वो आप तीन साल में कर लीजियेगा तो बता दीजियेगा। मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दें कि कौन-कौन सी सड़कों का नवीनीकरण हुआ है? उसकी मुझे लिस्ट प्रोवाइड करवा दें।

श्री अध्यक्ष: आपने प्रश्न में केवल कितनी सड़कों का नम्बर पूछा है, कौन-कौन सी नहीं पूछा है। आप प्रश्न पढिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं पूरक प्रश्न में पूछ सकता हूं। मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करेंगे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): वे बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: वे बोल रहे हैं तो आप क्यों जवाब दे रहे हो? आप बैठें।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): बिलकुल, आपने पूरी लिस्ट मांगी है। वैसे तो

आपको विवरण भेज दिया गया है, लेकिन अगर आप उसकी भी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आपको वह जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगी।

श्री अध्यक्षः श्री घनश्याम।

टोडाभीम में फसल बीमा योजना से वंचितों को मुआवजा

88. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में विगत तीन वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पात्र किसानों को नहीं दिया गया है? यदि हां, तो उक्त अवधि में कितने किसानों का फसल बीमा किस कम्पनी के द्वारा किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में बीमा योजना के तहत मुआवजा समय पर नहीं मिलने से कितने किसान वंचित रहे? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण करते हुए ऑनलाईन प्रकिया की समयावधि बढ़ा कर वंचित किसानों को लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग) (कृषि मंत्री के स्थान पर): (1) जी नहीं, विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में विगत तीन वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पात्र किसानों को दिया गया है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2021 से रबी 2023-24 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत 312088 फसल बीमा पॉलिसी एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि., एस.बी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. तथा रिलायंस जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. के माध्यम से सृजित हुई हैं।

(2) उक्त विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2022 एवं रबी 2022-23 के लिए 207 फसल बीमा पॉलिसियों पर NEFT बाउंस, खाते एवं आधार से सत्यापित ना होने के कारण लम्बित हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी 2023-24 के लिए बीमा क्लेम आकलन पोर्टल के माध्यम से गणनाधीन है।

(3) जी हां, बकाया बीमा क्लेम वितरित कराये जाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित कराने हेतु बीमा कम्पनियों एवं जिलों को निर्दिष्ट किया गया है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर आ गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्षः आप खड़े होते ही कह दिया करो। माननीय, पूरक प्रश्न।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी इस सदन में नहीं आये, दूसरे मंत्री जी से जवाब दिलवाया जा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के जो पात्र किसान हैं, मैंने उनकी सूची मांगी थी। एक तो सूची नहीं दी है। दूसरा, यह है कि मंत्री जी किसानों का पैंडिंग भुगतान कब तक करा

देंगे? यह मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता है कि कब तक उनकी सूची दे देंगे और उनका कब तक पेमेंट करा देंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): आपने पहले सूची वाला प्रश्न किया था। आपने बाद में फिर से नया सवाल किया था। आपके पूर्ववर्ती सवाल के अन्दर सूची आपने मेज पर मांगी थी, लेकिन अभी आपने जो नया सवाल किया है, उसी का जवाब मैंने अध्यक्ष जी के मार्फत दिया है। जैसा कि अभी बताया गया है कि वैकल्पिक खाते में बीमा क्लेम, जो खाते बाउंस हो जाते हैं, उनका गांव में जाकर बीमा कम्पनियां कैम्प लगाती है और कैम्प लगाकर उनके नये वैकल्पिक खाते के मिलते ही उसका जल्दी से जल्दी क्लेम दिलवाया जायेगा। जैसा कि बताया है, 207 लोगों का 20 हजार 199 रुपये का क्लेम आपके विधान सभा क्षेत्र में बाकी है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, खाते तो कभी बाउंस होते ही नहीं हैं। मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं। चैक बाउंस होते हैं, खाते कभी बाउंस होते हैं क्या?

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): मैंने नेफ्ट का बोला है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नहीं, आपने कहा है कि खाते बाउंस होते हैं, खाते तो बाउंस होते ही नहीं हैं।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): मैंने नेफ्ट का बोला है, जो नेफ्ट बाउंस हो जाता है, जो उनके खाते के अन्दर नहीं पहुंचता।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप और कोई प्रश्न पूछिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): खाते कभी बाउंस नहीं होते हैं, चैक बाउंस होते हैं।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कह दिया। आप अगला प्रश्न पूछिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मेरा प्रश्न यह है कि उन किसानों की सूची दी जाये। इन्होंने जो गोलमोल जवाब दिया है यह गोलमोल जवाब नहीं चाहिए। कितने किसानों का प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम हुआ और भुगतान कब तक करा देंगे? एक निश्चित समय, महीने में, दो महीने में करा पायेंगे या नहीं करा पायेंगे।? यह जवाब मैं आपसे चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को आपके मार्फत बताना चाहता हूं कि इनकी टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में 3 लाख 12 हजार 88, यह मैं आपको जवाब दे चुका हूं। आपको सूची मिल जायेगी।

Bhs/Rtm/16.7.24/11.10/1b

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा चूंकि यह विषय कई माननीय सदस्य इधर के भी और उधर के भी लगातार लगा रहे

हैं कि प्रधान मंत्री फसल बीमा में किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है तो कोई सरकार की यह योजना है कि चरणबद्ध रूप से या तय समय-सीमा करके सभी किसानों को एक साथ या कोई कैम्प लगा करके आप सबका भुगतान करायेंगे? कब तक करायेंगे? एक तो आप यह बता दें। दूसरा, राजस्थान के अन्दर किसानों को खुद के लिए भी उनकी डेथ हो जाये तो दस लाख रुपये की सहायता सरकार देती है तो वह भी बीमा होता है तो वह बीमा भी सरकार ने करा रखा है कि नहीं करा रखा है? यह भी जानकारी मैं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत बताना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश के अन्दर कुल 11 करोड़ 31 लाख 47 हजार पॉलीसीज हुई हैं और सभी किसानों का जो भुगतान मैंने जैसा कि पूर्ववर्ती सदस्य को जस्ट अभी बताया था कि जिन-जिन खातों में नेफ्ट बाउंस हो जाते हैं उन खातों के लिए भारत सरकार द्वारा जो भी नियम बनाये गये हैं और यहां से राजस्थान सरकार उनको डिटेल भेजने के बाद वापस बीमा कम्पनियां यहां पर अपने कैम्प लगाती हैं और कैम्प लगाने के बाद में वैकल्पिक खातों की जैसे ही संख्या मिलती है उनको वापस पैसे देने की व्यवस्था हमेशा की जाती है। इसमें अलग-अलग साल के क्लेम चलते रहते हैं और क्लेम जो पीछे शेष बच जाते हैं वे आने वाले समय में लगातार क्रमबद्ध उनको दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप ये पूछ रहे हैं कि कैम्प लगायेंगे कि नहीं?

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): बिलकुल, मैं अभी पूर्व में जवाब दे चुका हूं कि जल्द से जल्द कैम्प लगाने के ऑलरेडी निर्देश कर चुके हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): किसानों का भी बीमा है कि नहीं दस लाख रुपये का आज की तारीख में?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। आ गया आपके प्रश्न का।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, यह भी जरूरी है कई किसानों की मौत हो गई उनको दस लाख रुपये क्लेम मिलता है वह नहीं मिल पा रहा है। कृपया सदन को अवगत करायें कि बीमा करा रखा है कि नहीं करा रखा है?

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, कुछ कहेंगे क्या?

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): करा देंगे, साहब।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आज की तारीख में है या नहीं है मैं तो यह पूछ रहा हूं?

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी के चिकित्सालयों में ट्रोमा सेन्टर की स्थापना

89. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप चिकित्सा संस्थानों में

ट्रोमा सेंटर (वार्ड) खोले जाते है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रदेश में उक्त सेंटर कहां-कहां खोले गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 एवं 113 के समीप जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़ में ट्रोमा सेंटर (वार्ड) खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप चिकित्सा संस्थानों में ट्रोमा सेंटर (वार्ड) खोले जाते हैं। विगत तीन वर्षो में प्रदेश में खोले गए ट्रोमा सेन्टर की सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दुर्घटना में घायल व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में 50 किमी से अधिक परिवहन की आवश्यकता ना पड़े इसी क्रम में प्रत्येक 100 किमी पर एक ट्रोमा सेंटर खोले जाने का प्रावधान है।

जिला चिकित्सालय चित्तौडगढ में वर्तमान में ट्रोमा सेंटर संचालित है जो जिला चिकित्सालय निम्बाहेडा से 32 किमी दूर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगरार (चित्तौडगढ) पर ट्रोमा सेंटर संचालित है, जिसकी भी निम्बाहेडा से दूरी 59 किमी है। नियमानुसार प्रत्येक 100 किमी पर एक ट्रोमा सेंटर खोले जाने के प्रावधान अनुसार जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा की दूरी पूर्व में संचालित ट्रोमा सेंटरों से कम होने के कारण ट्रोमा सेन्टर खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

सामान्य चिकित्सालय प्रतापगढ में वर्तमान में ट्रोमा सेंटर संचालित है जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटी सादडी से 57 किमी दूर है। नियमानुसार प्रत्येक 100 किमी पर एक ट्रोमा सेंटर खोले जाने के प्रावधान अनुसार सामान्य चिकित्सालय प्रतापगढ से दूरी कम होने व वर्तमान में प्राईमरी ट्रोमा सेंटर संचालित होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटी सादडी में ट्रोमा सेन्टर खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न का जवाब तो पढ़ लिया है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा जवाब पढ़ लिया है। आप पूरक प्रश्न पूछ लें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मंत्री महोदय, मैंने जवाब देख लिया है। अब मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय को यही निवेदन है कि नोर्म्स तो मैंने इसमें देख लिये लेकिन निम्बाहेड़ा और छोटी सादड़ी और निम्बाहेड़ा से प्रतापगढ़ का रोड़ जो 85 किलोमीटर दूर है। इधर निम्बाहेड़ा से मंगलवाड़ रोड़ जो 55 किलोमीटर दूर है। चित्तौड़-निम्बाहेड़ा रोड़, नीमच रोड़, बड़ी सादड़ी रोड़ उसके सेन्टर में है छोटी सादड़ी और निम्बाहेड़ा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच वर्षों में चार सौ लोग मर चुके हैं वहां पर।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): और इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि चूंकि

निम्बाहेड़ा होस्पिटल जिला चिकित्सालय बने अभी उसको चार साल हो गये हैं, क्या सरकार वहां ट्रोमा सेन्टर खोलने का विचार रखती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: ठीक है। माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जो प्रोग्रेस हो रही है, हाईवेज बढ़ रहे हैं, ट्रेफिक बढ़ रहा है उसे देखते हुए ट्रोमा सेन्टर्स ज्यादा बनना बहुत आवश्यक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइड लाइंस है उसके तहत कहीं भी एक्सीडेंट हो तो पचास किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रोमा सेन्टर होना चाहिये। कहने का मतलब है कि हर सौ किलोमीटर के अन्दर एक ट्रोमा सेन्टर होना चाहिये ताकि पचास-पचास किलोमीटर यों कवर कर सकें। आपने जो अभी बोला था, दो ट्रोमा सेन्टर्स की मांग की थी एक निम्बाहेड़ा के अन्दर और दूसरा आपने बोला था छोटी सादड़ी के अन्दर। अभी भौगोलिक दृष्टि से देखा जाये तो आपके चित्तौड़गढ़ के अन्दर ट्रोमा सेन्टर है वह आपके निम्बाहेड़ा से खाली 32 किलोमीटर है। गंगरार के अन्दर ट्रोमा सेन्टर है जो आपके निम्बाहेड़ा से 59 किलोमीटर है। कटून्दा ट्रोमा सेन्टर है जो 91 किलोमीटर है आपके निम्बाहेड़ा से। छोटी सादड़ी केवल 57 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल प्रतापगढ़ से। इसमें ऐसा है कि कटून्दा और चित्तौड़ से जो ट्रोमा सेन्टर है जो पहले के बने हुए हैं उसके अन्दर खाली आपके पास 6 स्टाफ में से एक ही है और जो दूसरे हैं गंगरार और रावतभाटा जो भी आपके नजदीक पड़ते हैं वो ट्रोमा सेन्टर के अन्दर 6 में से 6 पद रिक्त हैं, which means the trauma center is not existed.

मैं माननीय सदस्य को यही बोलना चाहूंगा कि अभी जितने भी नये डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल्स बन रहे हैं जिनका कार्य शुरू हो गया है और जो प्रस्तावित हैं, उनके अन्दर ट्रोमा सेन्टर इन बिल्ट रहेगा। It will be part and parcel of the district hospital, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ट्रोमा सेन्टर्स हाईवेज पर सौ बना चुके हैं राजस्थान में। बेसिकली मेरा यह कहना है कि यह प्रस्तावित है हमारी फाइनेंस पोजिशन देख कर कि जो भी जिला अस्पताल हैं जहां ट्रोमा सेन्टर नहीं बने हैं पहले हमें उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि सब जितने भी जिला अस्पताल जो छूट गये हैं जो यह नयी नीति नहीं बनी थी अब आगे तो ट्रोमा सेन्टर्स डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल के साथ ही बनेगा। उनकी सूची लेकर उसका बजट लेकर उनको प्राथमिकता से करेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने विश्वास दिलाया है कि जो जिला चिकित्सालय बने हैं नये उनमें ट्रोमा सेन्टर खोलेंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी को यह कहूंगा कि जितने भी ट्रोमा सेन्टर चित्तौड़ जिले के बताये हैं वो मापदंड से बने कि नहीं बने हैं, आप सौ किलोमीटर का मापदंड बता रहे हो उधर कोई तीस किलोमीटर पर कोई पच्चीस किलोमीटर पर है, लेकिन निम्बाहेड़ा और प्रतापगढ़ की दूरी 87 किलोमीटर की है और 87 किलोमीटर में कोई ट्रोमा सेन्टर नहीं है और इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं मैं, डोटासरा जी, आपको भी कहूंगा

कि आपके ही एक नेता ने रोड़ बनाया था वह। सारी रोड़ का सत्यानाश कर दिया। खड्डे पड़ रहे हैं रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं कांग्रेस के राज में रोड़ बनी थी। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि निम्बाहेड़ा या छोटी सादड़ी में ट्रोमा सेन्टर बनायेंगे तो लोगों को राहत मिलेगी।

श्री अध्यक्षः इस पर विचार करना।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मंत्री जी का बोलने दो न, साहब।

श्री अध्यक्षः निम्बाहेड़ा वालों की भी चिन्ता करना।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल बना दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्री नहीं बनाया तो ट्रोमा तो दे दो मैं सिफारिश करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री छगन सिंह।

आहोर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

90. श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आहोर के उच्च प्राथमिक विद्यालय, मिठडी, सुमेरगढ़, खेडा, सेलडी, बागुन्दा में छात्र संख्या निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होने के उपरान्त भी उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन दिलावर): अध्यक्ष महोदय, (1) जी, नहीं। विधान सभा क्षेत्र आहोर के उच्च प्राथमिक विद्यालय, मिठडी, सुमेरगढ़खेडा, सेलडी एवं बागुन्दा के क्रमोन्नति हेतु प्राप्त प्रस्तावानुसार इन विद्यालयों द्वारा विभागीय मानदण्डों को पूर्ण नहीं करने के कारण क्रमोन्नत नहीं किया जा सका।

पुनः प्रस्ताव प्राप्त होने पर मानदण्डानुसार आंकलन किया जाकर ही उक्त विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अभी तक शिक्षा मंत्री जी ने माफी नहीं मांगी है। ये सदन में माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम बोलने नहीं देंगे। इनको सदन से माफी मांगनी पड़ेगी। सदन से माफी मांगनी पड़ेगी मंत्री जी को। शिक्षा मंत्री जी को माफी मांगनी पड़ेगी। इस प्रकार का बयान दे रहे हैं रोजाना। एक प्रदेश का शिक्षा मंत्री इस प्रकार की भाषा का यूज करता है, किस प्रकार से दूसरे समाज के लिए शब्दों का प्रयोग करता है ऐसे शिक्षा मंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार को आप निर्देश दीजिये कि इनको सद्बुद्धि आये। इनको सद्बुद्धि आये कि ये जनता के हित की बात करे न कि आपस में एक दूसरे समाज पर छींटाकशी करें। आजकल ऐसा लग रहा है कि ...(व्यवधान)...

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्यालय क्रमोन्नत करने

की मानदंड क्या-क्या हैं? यह बतायें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठिये। शांति से बैठिये। सुनिये। अपनी सीट मत छोड़िये। आपको फिर बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मानदंड यह है जहां विद्यालय खोलने वाले हैं वहां छात्र संख्या ...(व्यवधान)... गांव की जनसंख्या 1500 होनी चाहिये और छात्रा विद्यालय खोलने हैं वहां 2000 होनी चाहिये। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, कल भी इनका बयान आया है, परसों भी मंत्री जी का बयान आया है उससे पहले भी रोज मंत्री का बयान आया है। चौदह-चौदह मुकदमे इन पर दर्ज हैं और ये दूसरे लोगों को शिक्षा देते हैं खुद शिक्षा नहीं लेते तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसा शिक्षा मंत्री जो हमेशा दूसरे के लिए अपशब्द यूज करता है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान)... स्कूल क्रमोन्नत करना है तो आठवीं में विद्यार्थियों की संख्या ...(व्यवधान)... छात्रों की संख्या ...(व्यवधान)... होनी चाहिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दूसरे लोगों की कोई हैसियत नहीं समझता है जो मर्जी आये वो बोलता है। शब्दों पर जिसका कंट्रोल नहीं है और वो इस देश के भविष्य का क्या ख्याल रखेंगे। राजस्थान के बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, क्या सिखायेंगे जिनका विजन, शिक्षा मंत्री बनने के बाद एक-दो लाइनें जिनकी शिक्षा पर नहीं आयी हों। दो लाइनें जो शिक्षा पर नहीं बोले हों। दो लाइनें जो शिक्षा को किस प्रकार से मजबूत किया जाये उस पर नहीं बोले हों।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान)... इसमें केवल 9 हैं और इसी प्रकार से सेलड़ी में छात्रों की संख्या 11 और छात्राओं की संख्या 18 है ...(व्यवधान)... इसी प्रकार से बागुन्दा में ...(व्यवधान)... इसलिये इनको क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान)... ऐसे शिक्षा मंत्री को तुरन्त हटाया जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह बहुत ही गम्भीर सवाल है राजस्थान के जो नौनिहाल बच्चे हैं ...(व्यवधान)...

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री हरिसिंह रावत।

भीम के ए.सी.जे.एम. न्यायालय का क्रमोन्नयन

91. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीम के ए.सी.जे.एम. न्यायालय को एडीजे न्यायालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

Kas/rtm/16.07.2024/11.20/1c

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री जोगाराम पटेल): किसी स्थान पर न्यायालय का क्रमोन्नयन माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उस क्षेत्र के अपर जिला न्यायालय स्तर के 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर मिल गया है, मेरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: पूरा उत्तर सुन लिया? शुरू करते ही पहले कह दें तो बात अलग है, अब पूरा पढ़ने दो। मैं जैसे ही पुकारू और आपने कह दिया कि पढ़ा हुआ है, इसमें मेरे को तो और आराम है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): वर्तमान में भीम मुख्यालय पर ए.सी.जे.एम. (वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) को ए.डी.जे. (अपर जिला न्यायालय) में क्रमोन्नत करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार भीम मुख्यालय पर वर्तमान में ए.सी.जे.एम. न्यायालय स्थापित है और इसे ए.डी.जे. न्यायालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है।

भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार भीम क्षेत्र के अपर जिला न्यायालय स्तर के 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह स्पष्ट करना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बैठ कर बात कीजिए। ...(व्यवधान)... आपस में बैठ कर तो कर सकते हैं। ...(व्यवधान)... बैठिए, बैठिए, हो गया।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, मेरी विधान सभा राजसमन्द जिले से 100 किलोमीटर दूर है और मेरे वहां दो ए.सी.जे.एम. कोर्ट हैं। अभी आये हुए नये कानून के अंतर्गत कई ऐसे छोटे-छोटे परिवाद हैं जिनके लिये भी उनको 100 किलोमीटर दूर राजसमन्द जाना पड़ेगा। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि या तो वहां एक ए.डी.जे. कोर्ट खोले, नहीं तो कम से कम हमारे वहां एक कैम्प कोर्ट की व्यवस्था करवा दें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य का यह कथन पूर्ण रूप से सही है कि इनके यहां जितने भी लिटिगेंट हैं, उनको करीब 100 किलोमीटर दूर राजसमन्द जाना पड़ता है। भीम क्षेत्र के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तर के सिर्फ 153 सिविल केसेज हैं और 213 फौजदारी केसेज हैं, कुल

366 केसेज ही हैं। फिर भी चूंकि 100 किलोमीटर की दूरी है और प्रकरण भी बढ़ रहे हैं, तो सरकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श कर इस सम्बन्ध में गंभीरता से विचार करेगी कि आपके यहां कैम्प कोर्ट खोला जाये और इस सम्बन्ध में गंभीरता से विचार कर जो भी उचित निर्णय होगा, उससे आपको अवगत करा दिया जायेगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंह।

जैसलमेर में गोवंश की मृत्यु पर पशु पालकों को देय आर्थिक सहायता

92. श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जैसलमेर में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक गोवंश में कितनी कमी आई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिला के गांवों में उक्त अवधि में 60 प्रतिशत से अधिक गोवंश की मृत्यु हुई है? यदि हां तो कितने गावो में? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त जिले में उक्त अवधि में गोवंश की मृत्यु होने पर पशुपालकों को आर्थिक सहायता दी गई है? यदि हां, तो कितनी आर्थिक सहायता कितने पशुपालकों को दी गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

पशुपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) प्रदेश में पशुगणना भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक पाँच वर्ष में करवाई जाती है। अंतिम पशुगणना वर्ष 2019 में आयोजित की गई थी, जिसमें जिला जैसलमेर में कुल गोवंश 4 लाख 7 हजार 48 रहा।

आगामी पशुगणना इस वर्ष माह सितम्बर से दिसम्बर 2024 के मध्य की जावेगी। जिसके आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात गोवंश की संख्या में अंतर की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

(2) जी नहीं। जिला जैसलमेर में वर्ष 2019 से 2023 के मध्य कर्रा रोग से कुल 432 गोवंश की मृत्यु हुई तथा वर्ष 2022 में फैले लम्पी रोग के कारण 982 गोवंश की मृत्यु हुई है।

आगामी पशुगणना इस वर्ष माह सितम्बर से दिसम्बर 2024 के मध्य की जावेगी। जिसके आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात ही वर्ष 2019 से 2023 के मध्य गोवंश की मृत्यु के वास्तविक प्रतिशत की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

(3) जी हॉ। जिला जैसलमेर में वर्ष 2022 में लम्पी रोग से मृत दुधारू गोवंश के लिए पशुपालकों को प्रति दुधारू गोवंश राशि रुपये 40 हजार की दर से 593 पशुपालकों को कुल राशि रुपये 2 करोड़ 66 लाख 40 हजार का भुगतान किया गया।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): आदरणीय मेरे प्रश्न का जवाब आ गया।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, पूरक प्रश्न पूछ लें।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर पशुपालक क्षेत्र है। मैंने प्रश्न पूछा है 2019 से लेकर 2023 तक कर्रा रोग व लम्पी बीमारी से कितने पशु मरे हैं?

इसमें आपका उत्तर है कि 593 पशु मरे हैं। पूर्व सरकार का यह नियम था कि प्रत्येक पशु का 40 हजार रुपये उसको अनुदान दिया जायेगा। माननीय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि 593 पशुओं को ही क्यों दिया गया, बाकी 921 क्यों नहीं दिया गया?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिला जैसलमेर में वर्ष 2019-23 के मध्य कर्रा रोग से कुल 432 गोवंश की मृत्यु हुई और लम्पी से 982 की मृत्यु हुई। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या दुकान लगा रखी है। मंत्री के समझ में ही नहीं आ रहा है कि हाउस कैसे चलता है, परम्पराएं क्या हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल चल रहा है। ...(व्यवधान)... आप विराजिए, यह मेरा काम है, आपका नहीं है। आप बैठिए, मेरा काम, मेरे को करने दें।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आपको ध्यान तो रहता नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपसे ज्यादा है। आप जब थे, उससे डबल ध्यान है।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्रा रोग से जो पशुओं की मृत्यु हुई, उसमें अनुदान का कोई प्रावधान नहीं था। लम्पी से जो मृत्यु हुई, उसमें प्रति पशु 40 हजार अनुदान का प्रावधान था, इसलिए लम्पी से जो मृत्यु हुई, उनको अनुदान दिया, बाकी को नहीं दिया।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, लम्पी रोग से भी 392 गायें मरी हैं, फिर उनका क्यों नहीं दिया गया? कर्रा रोग से मृत्यु पर नहीं देते हो, लेकिन लम्पी में तो आपने 593 का दिया, जबकि आपकी घोषणा 982 की थी, उसमें क्यों भाई-भतीजावाद हुआ? गाय थी, गाय मर गई, उन सभी को देना था, फिर पूर्ववर्ती सरकार में यह भिन्नता क्यों आई, मैं यह पूछना चाहता हूं, इसका जवाब दो मुझे।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कर्रा रोग 2022 में हुआ था और कर्रा रोग से गोवंश की मृत्यु ज्यादा संख्या में हुई थी। पूर्ववर्ती सरकार ने सही समय पर मुआवजे की घोषणा नहीं की और बाद में 6 महीने बाद घोषणा की, इस कारण से कम आंकड़े आये और जितने आंकड़े आये, उनको दिया गया, बाकी को नहीं दे पाये। ...(व्यवधान)... इसमें अभी कोई बाकी रहा होगा तो हम जांच करवा लेंगे और वंचित लोगों को दिला देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह।

उदयपुर संभाग के कारागृहों में कैदियों को रखने की क्षमता

93. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर संभाग में कितने कारागार हैं तथा उक्त में कैदियों को रखने की कितनी

क्षमता है? विगत तीन वर्षो में किन-किन कारागृहों में कितने-कितने कैदी रखे गये? जिलेवार, कारागारवार व क्षमतावार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संभाग के कारागारों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा जा रहा है? यदि हां, तो सरकार क्षमता से अधिक कैदियों को अन्य जेलों में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार चित्तौड़गढ़ जिला कारागार की क्षमता के विस्तार हेतु कक्ष निर्माण व जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) उदयपुर संभाग में कारागार, कैदियों को रखने की क्षमता एवं विगत तीन वर्ष में रखे गये कैदियों की जिलेवार, कारागारवार व क्षमतावार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। उदयपुर संभाग के कुछ कारागृहों में क्षमता से अधिक बंदी निरूद्ध रखे गये है। कारागृहों में जनाधिक्य की स्थिति होने पर अन्य कारागृहों पर बंदियों को स्थानान्तरित किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जिला कारागृह, चित्तौड़गढ में 80 बंदी क्षमता की नवीन बैरक बनाये जाने हेतु कार्यकारी एजेन्सी RPIDCL को महानिदेशालय कारागार द्वारा दिनांक 17.10.2022 को बैरक का नक्शा अनुमोदित कर शीघ्र निर्माण कराये जाने हेतु लिखा गया है। जिला कारागृह, चित्तौडगढ में 80 बंदी क्षमता की नवीन बैरक बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भविष्य में वित्तीय संसाधनों एवं भूमि की उपलब्धता तथा कैदियों की संख्या के आधार पर गुणावगुण का परीक्षण कर जिला कारागृह, चित्तौडगढ की क्षमता बढाने पर विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जेल में एन.डी.पी.एस. एक्ट के काफी कैदियों को एक-दो महीने की सज़ा होने पर भी दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाता है। मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना है कि वहां जमीन अलाटमेंट हो रखी है, लेकिन उस जमीन पर कब्जे हैं। आप दूसरी जमीन अलॉटमेंट करा कर, क्योंकि अगर जेल की कैपेसिटी नहीं होगी, एक-दो महीने की सज़ा होने पर भी हमारे कैदी को बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है, आप इतना आश्वस्त कर दें, हमे दूसरी जगह जमीन अलॉटमेंट करा दें, क्योंकि पिछले चार साल से बिना स्वीकृति के बिल्डिंग पड़ी है। आप दूसरी जगह जमीन दिलवा कर उसकी नई बिल्डिंग बनवा दें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): हमारे जो कैदी बाहर हैं, वे नहीं आ पायेंगे। जेल की कैपेसिटी से दो-तीन गुना वहां कैदी हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, सुझाव नहीं, प्रश्न पूछिए।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): उस जमीन को खाली नहीं करवा पायेंगे, दूसरी करवा दें। अध्यक्ष महोदय, मेरी इतनी सी विनती है कि दूसरी जगह शिफ्ट करवा दें।

msk/rtm/16.07.2024/1130/1d

श्री अध्यक्षः हो गया, सुझाव दे दिया, आपने मान लिया।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): नहीं माना कहां, सर पूरा बतायें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2023 में 430 कैदियों को चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल से आसपास की जेल में शिफ्ट किया। 2024 में 125 कैदियों को शिफ्ट किया। चित्तौड़गढ़ की अभी जो डिस्ट्रिक्ट जेल है, अभी उसकी क्षमता 338 है, 519 कैदी हैं तो ओवरफ्लोडेड तो है ही। ग्राम सेगवा, जो बिल्कुल शहर से जुड़ता हुआ है, वहां 2.6 हेक्टेयर जमीन आइडेंटीफाई की हुई है, लेकिन वहां पर अतिक्रमण की वजह से जनता उसको अपोज कर रही है। मैं माननीय विधायक महोदय से कहूंगा कि आप लोग जेल डिपार्टमेंट की मदद करें ताकि आपके जो दोस्त जेल में हैं, वोटर्स, वे दुख भी नहीं पाये और उनको दूर भी नहीं भेजा जाए।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): जेल में दोस्त, ऐसे कैसे बोल रहे हैं?

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): एक मिनट।

श्री अध्यक्षः आपका उत्तर दे दिया, अब नहीं। श्री धर्मपाल। माननीय धर्मपाल, नाम पुकार लिया, बोलिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इनके दोस्त जेल में हैं, यह रिकॉर्ड पर आ गया है।

खेतड़ी में आकाशीय बिजली से पशुओं की मृत्यु पर मुआवजा

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि आकाशीय बिजली गिरने या प्राकृतिक आपदा से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को मुआवजा देने का प्रावधान है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में विगत पांच वर्षों में उक्त योजना में कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितनों को मुआवजा दिया गया व कितने शेष हैं? आवेदनों की संख्या एवं मुआवजा राशि सहित संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता (श्री ओटा राम देवासी): जी हां। आकाशीय बिजली सहित अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.10.2022 को जारी एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार सहायता दिये जाने का प्रावधान है। एसडीआरएफ नॉर्म्स की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में विगत पांच वर्षों (1 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2023 तक) अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से पशु मृत्यु होने पर 16 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से

11 आवेदन पत्र एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार स्वीकृत कर राशि 2.97 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवायी गई है। वर्तमान में उक्त अवधि का कोई भी आवेदन पत्र एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार शेष नहीं है।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि मैं एक निवेदन कर रहा था कि विधान सभा क्षेत्र में बांसियाल खेतड़ी एक रिजर्व कंजर्वेशन है। उसमें आये दिन बड़ी संख्या में पशुपालकों की भेड़-बकरियों को जानवर खाते हैं। इसमें बघेरा, सियार, तेंदुआ है। यह रिजर्व कंजर्वेशन होने के कारण मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन मवेशियों को एसडीआरएफ में शामिल कर सकते हैं या नहीं? जब हम वन विभाग से सवाल करते हैं तो वन विभाग कहता है कि दो-तीन साल में एक बार बजट अलोट होता है और उस बजट के अभाव के कारण हम पशुपालकों की मदद नहीं कर पाते। मेरे पास ऐसे बहुत ज्यादा केस हैं। लगभग सात केस तो ऐसे हैं, जिसमें 22-22 भेड़ भी..

श्री अध्यक्ष: उत्तर आने दीजिये, माननीय मंत्री जी।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.10.2020 को एसडीआरएफ के नॉर्म्स के अनुसार प्राकृतिक आपदा में पशुओं की मृत्यु होने पर सीमान्त किसानों एवं भूमिहीन पशु पालकों को, जो दुधारू पशु हैं, उनमें भैंस, गाय, ऊंटनी, याक, मिथुन, उसके लिए 37500 रुपये का प्रावधान है। उसके बाद भेड़, बकरी, सुअर के लिए चार हजार रुपये। गैर दुधारू पशुओं के लिए 32 हजार रुपये, ऊँट, घोड़ा, बैल। 20 हजार रुपये बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर, हेपर, इसके लिए जो नॉर्म्स बने हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 12 ऐसी आपदाएं हैं और स्टेट की दो आपदाएं हैं, उसको इस सूची में इन्वॉल्व किया गया है। इसके लिए मैं सरकार की तरफ से जो भी नॉर्म्स में होगा, उसको कराने की कोशिश करेंगे।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): अध्यक्ष जी, मेरा एक और पूरक प्रश्न है। मैंने एक ही प्रश्न किया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अग्निकाण्ड के अन्दर जब कोई व्यक्ति या किसी के घर का सामान या फिर मवेशी मर जाते हैं, उसका कितने दिन में मुआवजा देने का प्रावधान है। समयावधि बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): अध्यक्ष महोदय, 2019 से लेकर 2023 जो 16 आवेदन प्राप्त हुए थे, उनमें से हमने अभी तक 6 आवेदन स्वीकार किये, उसमें से सबसे पहले खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में नन्द लाल, भागीरथ जी, कालोटा निवासी खेतड़ी, उसको तीस हजार की सहायता दी गयी। हिम्मत सिंह जी, जगनाराम जी, निवासी ताल, उनकी तीन बकरी थी, 9 हजार की सहायता..

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): अध्यक्ष जी, मैं समयावधि की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: ये समयावधि पूछ रहे हैं। किसको दिया है, यह नहीं पूछ रहे हैं।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): मैं समझता हूं कि जल्दी ही, जो भी

नॉर्म्स में आयेगा, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्षः श्री कंवरलाल।

बारां में मेडिकल कॉलेज का निर्माण

95. श्री कंवरलाल (अंता): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला बारां में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कब से तथा किस फर्म द्वारा किया जा रहा है? क्या उक्त का निर्माण कार्य 31 मई, 2024 तक पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): मेडिकल कॉलेज बारां एवं सम्बद्ध चिकित्सालय के निर्माण कार्य की कार्यकारी एजेंसी राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आर.एस.आर.डी.सी) है। कार्यकारी एजेंसी आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा मुख्य कार्य, संवेदक मैसर्स, रमेश कुमार बंसल को कार्यादेश दिनांक 22.07.2022 के द्वारा दिया गया है एवं कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 22.07.2022 है। कार्य दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।

31 मई, 2024 तक मेडिकल कॉलेज का स्ट्रक्चर कार्य पूर्ण किया जाकर, फिनिशिंग एवं कैम्पस विकास का कार्य प्रगति पर है।

मेडिकल कॉलेज बारां में एन.एम.सी के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार एल.ओ.पी. (लेटर आफ परमिशन) स्तर का कार्य 31 जुलाई, 2024 तक पूर्ण कर, वर्ष 2024-25 में शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ किया जाना प्रक्रियाधीन है।

श्री कंवरलाल (अंता): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा पूरक प्रश्न है कि क्या एनएमसी के लिए रेटिंग बोर्ड में क्यों पिछड़े या फिर एनएमसी में एलवाई के लिए आवेदन करेंगे? नहीं तो किस स्तर पर गलती हुई, कब और क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर झुन्झुनू और बारां, 2024-25 में कम्पलीशन का प्रोग्राम था। इसमें मैसर्स रमेश कुमार बंसल की वजह से देरी जरूर हुई, उससे सरकार को नुकसान भी हो रहा है। आरएसआरडीसी इसका नियंत्रण कर रही है। जो पैनल्टी क्लोजेज हैं, 10 परसेंट ऑफ कांट्रेक्ट अमाउंट और जो बैलेंस ओवर रन होगा, that will be borne by the company. उसकी तरफ से यह भी अपील आयी है कि साहब, मुझे टाइमली पेमेंट नहीं दिया गया है। आरएसआरडीसी इसकी छानबीन करके, जो पैनल्टी इम्पोज करनी है, वह पैनल्टी इम्पोज की जायेगी। 31.07.2024 को हम एलओपी, एनएमसी से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ताकि जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई हैं, क्लास रूम्स बने हुए हैं, जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी स्टेज पर हैं, हम कम से कम पहले चरण में इस कॉलेज को जुलाई, 2024 में शुरू कर सकें। दिसम्बर तक इसका कार्य पूरा होने की संभावना है।

श्री कंवरलाल (अंता): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या प्राइवेट, उस

कॉलेज की जमीन पर, वन-प्लाट पर मेडिकल कॉलेज की एलवाई जारी होती है। क्या प्राइवेट मालिक की समर्पणशुदा 7.6 बीघा जमीन का मुआवजा या मालिक द्वारा खुद व्यावसाय करने की अनुमति देंगे तो एक प्लाट कैसे रहेगा और फिर एलओपी कैसे मिलेगी?

श्री अध्यक्ष: बैठिये, माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम आरएसआरडीसी से पूरी डिटेल मंगा लेंगे और उसके बाद माननीय सदस्य इसके बारे में पूरी जानकारी दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कल्पना देवी।

कोटा में पंचायती राज संस्थाओं में अग्रिम राशि का समायोजन

96. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 215(2) के अनुसार संकर्मों या विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले अग्रिमों का अधिकतम तीन माह में समायोजन किया जाना अनिवार्य है? यदि हां, तो कोटा जिले की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों तथा जिला परिषद् द्वारा उक्त नियमों की अवहेलना की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अग्रिम राशि के समय पर समायोजन नहीं किये जाने पर 18 प्रतिशत ब्याज की शास्ति वसूल किये जाने का प्रावधान हैं? यदि हां, तो कोटा जिले की कौन- कौनसी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में समय पर अग्रिम राशि के समायोजन के कितने प्रकरण वित्तीय वर्ष 2019-20 से माह दिसंबर 2023 तक दर्ज किये गये एवं उनके विरूद्ध कितनी राशि शास्ति के रूप में वसूल की गई है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) जी हां। राजस्थान पंचायती राज नियम 215(2) के अनुसार संकर्मों या विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्रिमों का अधिकतम 03 माह के अन्दर समायोजन किया जाना आवश्यक है।

कोटा जिले के अधीन ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषद् द्वारा उक्त नियमों की अवहेलना नही की गई हैं।

(2) जी हां, अग्रिम राशि के समय पर समायोजन नहीं किये जाने पर 18 प्रतिशत ब्याज की शास्ति वसूल किये जाने का प्रावधान हैं।

कोटा जिला परिषद एवं अधीनस्थ समस्त पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में अग्रिम राशि नहीं दिये जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 से दिसंबर 2023 तक ब्याज वसूली का कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): मैं पूरक क्वेश्चन पूछ सकती हूं?

श्री अध्यक्ष: पूछिये।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे प्रश्न में स्पेसिफिक केवल नियम 215(2) के तहत यह सवाल पूछा है। मैं यह नहीं पूछ रही, मैं कर्मचारी की

अग्रिम राशि की जानकारी नहीं जानना चाहती हूं। वह नियम 215(1) के तहत कर्मचारी को लेकर है। मैंने नियम 215(2) के तहत यह प्रश्न किया है, जिसका मुझे जवाब चाहिए था। इसके तहत मैंने यह पूछा है कि कोटा जिले में किसी भी पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के तहत किसी भी विनिर्दिष्ट कार्य व सुकर्मों के लिए क्या एडवांस नहीं लिया गया? पंचायतवाइज विवरण सदन की मेज रखें। यह मेरे को जवाब नहीं मिला है।

mdp/rtm/16.07.2024/11:40/1e

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... 215(2) के तहत।

श्री अध्यक्षः माननीय, आप उत्तर दीजिए। उत्तर देना उनका अधिकार है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): 215(2) के तहत ...(व्यवधान)... संकर्मों या अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए कर्मचारियों ...(व्यवधान)... को दिये जाने वाले अग्रिमों का अधिकतम 03 मास के भीतर-भीतर समायोजित किया जायेगा। ऐसा न होने पर ...(व्यवधान)... गबन की श्रेणी में आयेगा।

श्री अध्यक्षः लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास रखते हैं तो मंत्री जी का उत्तर देना अधिकार है।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... अभी तक 2015 के तहत किसी भी प्रकार का एडवांस नहीं दिया गया है। ...(व्यवधान)... परंतु फिर भी यदि माननीय सदस्या को ऐसा लगता है कि एडवांस दिया गया है तो मैं सारे मामले की जांच करवा लूंगा और जो अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूं कि ...(व्यवधान)... अगर आप इसके लिए जांच करायेंगे तो कब तक जांच करायेंगे, इसका मुझे जवाब दीजिए?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)... इस पूरे मामले की जांच 20 दिन में करवा लेंगे और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 97

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्री मोतीराम। श्री मोतीराम। श्री मोतीराम।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न अपने स्थान से नहीं पुकारा गया)

अगला प्रश्न श्री अर्जुन लाल जीनगर। ...(व्यवधान)... मैंने कहा लाइन में आ जाओ, सीट से नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल जीनगर। अब नहीं, वह तो हो गया। माननीय मंत्री जी। तीन बार पुकारा, आप सीट पर नहीं रहते हैं ...(व्यवधान)... मैंने

पुकार लिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... सदस्य यही पर हैं।

श्री अध्यक्ष: इस तरह नहीं चलेगा। आप विरोध भी करते रहे और अगला प्रश्न भी मत पूछो। बैठिए। अर्जुन लाल जीनगर, बोलिए। मैंने पुकार लिया। ...(व्यवधान)... आपका गया। यहां नहीं था। ऐसा थोड़ी होगा, आप चाहे जो करें। नो, नहीं थे, यहां नहीं थे। मैंने तीन बार पुकारा, अब हो गया। आप यहां आकर प्रश्न कैसे कर सकते हैं, नो, अब अगला प्रश्न आ गया। ...(व्यवधान)... अब लास्ट में बचेगा तो करूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... सदन चलाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: जब प्रश्न हो जायेगा, समय बचेगा तो लास्ट में लूंगा। ...(व्यवधान)... लास्ट में। जब समय बचेगा लास्ट में।

बेसहारा गौवंश को पालने पर अनुदान देने की योजना

98. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बेसहारा गौवंश पालकों को प्रत्येक गाय पर एक हजार रूपये अनुदान देकर गौवंश को बचाने हेतु नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार गौशालाओं को नरेगा के साथ जोड़कर गौवंश को बचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा नन्दी को बचाने की कोई नीति तैयार की गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) जी नहीं। वर्तमान में इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गौशाला/कांजी हाऊस में संधारित निराश्रित गौवंश को भरण-पोषण हेतु वर्तमान में एक वर्ष पूर्व का पंजीयन तथा न्यूनतम 100 गौवंश होने पर वित्तीय वर्ष 2019-20 से बड़े गौवंश हेतु 40 रुपये तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रुपये की दर से तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 270 दिवस की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

नन्दीशालाओं में नर गौवंश तथा गौशालाओं में अपाहिज व अंधे गौवंश के भरण-पोषण हेतु सहायता राशि 12 माह दिये जाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा एक्ट, 2005 के तहत न्यूनतम रोजगार की गारंटी दी जाती है तथा यह व्यक्तिगत लाभार्थियों की योजना है जबकि गौशालाओं का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं/ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है।

(3) जी हां। नन्दीयों को बचाने के लिए ग्राम पंचायत गौशाला/पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजना एवं पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला जनसहभागिता योजना संचालित की जा रही है। उक्त दोनों योजनान्तर्गत आवेदन प्राप्त करने एवं पात्र संस्था का चयन करने

के लिए जिला स्तर पर निविदा आमंत्रित की जाती है। चयनित संस्था के साथ अनुबंध किया जाता है। योजना अन्तर्गत प्रावधित राशि क्रमशः 01 करोड़ एवं 1.57 करोड़ (10 : 90) का तकमीना प्राप्त किया जाता है। तकमीना अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग के स्तर पर जारी की जाती है। चयनित संस्था द्वारा योजना में प्रावधित राशि रुपये 01 करोड़ एवं 1.57 करोड़ का 10 प्रतिशत राशि का संस्था के हिस्से का कार्य संस्था द्वारा करवाया जाता है। 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के उपरान्त राज्यांश की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त जारी किये जाने का प्रावधान है। (40:40:10)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सरकार बड़े गौवंश को अनुदान के रूप में 40 रुपया और छोटे गौवंश को 20 रुपये देती है। क्या यह अनुदान बढ़ाकर 50 रुपये और 30 रुपये करना चाहती है?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गायों के अनुदान के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है और अच्छे निर्णय लेने की मंशा रखती है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अनुदान बढ़ाया जाता है तो भविष्य में जैसी वित्तीय संसाधनों की हमारे पास उपलब्धता होगी, उसी अनुसार हम निर्णय भी लेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री अजय सिंह। दो हो गये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): नहीं, दूसरा प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: चलिए, पूछिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस के राज में फर्जी गौशालाएं बताकर जो गायों का अनुदान खाने वाले, चारा खाने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही करने पर मंशा रखती है क्या?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पिछले सरकार के कार्यकाल में कई गौशालाएं ऐसी थी, जो फर्जी अनुदान उठा रही थी। जैसलमेर जिले में हमने जांच करवाई और उसमें 12 गौशालाएं ऐसी हुईं जिनमें फर्जी अनुदान का मामला आया जांच में। उन 12 गौशालाओं का हमने लाइसेंस रद्द कर दिया है और वहां पशुपालन विभाग के जो कर्मचारी थे, उनको निलंबित भी कर दिया है। अब पूरे जिले की गौशालाओं की जांच के लिए और दूसरे विभाग के कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी उसमें लिप्त हैं, उसकी उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए हमने मुख्य मंत्री जी को लिखा है। उच्च स्तरीय जांच की मांग हमने की है। शीघ्र ही इस पर निर्णय हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री अजय सिंह।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): धन्यवाद।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं कि ये जांच आप पूरे राजस्थान में कराएंगे? पूरे राजस्थान में जांच कराने की मंशा रखते है क्या? गंभीर विषय है। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। मंत्री जी, जवाब दे रहे हैं।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे पास जैसलमेर जिले की गौशालाओं की शिकायतें आयी थीं, इसलिए जैसलमेर का हमने निर्णय लिया। ...(व्यवधान)... पूरे राजस्थान में कहीं से भी शिकायतें आयेगी तो निश्चित रूप से जांच कराएंगे और दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। ...(व्यवधान)... यह निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: हो गया आपका । आपने राजस्थान का बोला, कह दिया। माननीय मंत्री जी। ...(व्यवधान)... माननीय मंत्री जी, अजय सिंह जी का जवाब।

नागौर के लाभान्वित कार्डधारक श्रमिक

99. श्री अजय सिंह (डेगाना): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार की विभिन्न योजनाओं का श्रमिक कार्ड धारक एवं उनके परिजन किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकते है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला नागौर में सरकार द्वारा वर्ष 2020 से दिनांक 31 मई 2024 तक कितने पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कर कितनी राशि व्यय की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिला में उक्त अवधि में कितने पात्र व्यक्तियों को बजट के अभाव में लाभान्वित नहीं किया जा सका है? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) (1) भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के आयु वर्ग के नियोजित श्रमिक जिन्होंने गत् 12 माह में, कम से कम 90 दिवस निर्माण कार्य किया है, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल मे पंजीयन के पात्र है। पंजीकृत श्रमिक जिन्होंने नियमित अंशदान जमा कराया हैं तथा लागू विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं मे उल्लेखित पात्रता एवं शर्तों को पूर्ण करते हैं, को सहायता राशि दी जाती हैं। मंडल द्वारा लागू योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) दिनांक 01.04.2020 से 31.05.2024 की अवधि मे नागौर जिले में 44,225 योजनाओं के आवेदन स्वीकृत किये गये तथा रुपये 66.81 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।

(3) उक्त अवधि के नागौर जिले में योजनाओं के कुल 8661 आवेदन लम्बित हैं। मण्डल की केवल दो योजनाओं क्रमशः शुभशक्ति योजना के 1244 आवेदन तथा निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के 133 आवेदन जो उक्त अवधि के हैं, को बजट के अभाव में लम्बित हैं। शेष अन्य योजनाओं में लम्बित आवेदनों का वरीयतानुसार निस्तारण किया जा रहा है। उक्त दोनों योजनाओं के आवेदनों का भी चरणबद्व रूप से पर्याप्त बजट उपलब्ध होने पर पात्र श्रमिकों को लाभान्वित कर दिया जायेगा।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में यह मुझे बताया है कि श्रम विभाग की शुभशक्ति योजना एवं निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के आवेदन बजट के अभाव में लंबित है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह पूछना है कि आपके पास में लगभग ढ़ाई हजार करोड़ से ज्यादा श्रमिक उपकर आया था, जबकि आपने उस पर

खर्च लगभग 53 प्रतिशत ही किया है। इसका क्या कारण रहा है कि बजट होते हुए भी आपने कम खर्च किया है? जिसके कारण से हजारों आवेदनकर्ता उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह बात इनकी सही है कि पिछले पांच वर्षों में 2019-20 से 2024 तक 2536.94 करोड़ रुपये की उपकर से आय प्राप्त हुई, जिसमें से 1356.24 लाख रुपये यानी 53 परसेंट ही योजनाओं में खर्च किये गये। इसमें वर्षवार विवरण भी है। जैसे वर्ष 2019-20 में 412 करोड़ आयी थी, 335 करोड़ खर्च किये। 2020-21 में 367 करोड़ आयी, 324 करोड़ व्यय किये। 2021-22 में 500 करोड़ की राशि जमा हुई, उसमें से 211 करोड़ ही खर्च किये। 2022-23 में 624 करोड़ की उपकर राशि संग्रहित हुई जिसमें 192 करोड़ ही खर्च हुए। वर्ष 2023-24 में 760 करोड़ आय हुई, 297 करोड़ खर्च हुए।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि नेता, प्रतिपक्ष हैं, जो माननीय इसी विभाग के रहे, परंतु विषय यह रहा कि उन्होंने योजनाओं में पैसा ही खर्च नहीं किया। बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि दो योजनाएं, जो श्रमिक विभाग की प्रमुख योजनाएं थीं, आम जन को लाभ देने के लिए, निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना, जिसमें कोई श्रमिक अपना आवास बना सकता है, जिसके लिए डेढ़ लाख की राशि मंजूर थी। दूसरी, शुभशक्ति योजना जिसमें श्रमिक अपनी अविवाहित बेटी के लिए 55 हजार रुपये की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना थी, वह पूर्ववर्ती सरकार ने आते ही दोनों योजना बंद कर दी। ...(व्यवधान)... विषय ये है कि राशि पड़ी होते हुए भी 53 परसेंट ही इन्होंने श्रमिकों के लिए खर्च किया। यह बताता है कि यह किस तरह की गंभीर सरकार थी।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जो आवेदन आए हैं, उसमें अगर हम उनका आंकड़ा देखें तो रिजेक्शन भी बहुत है।

Ans/rtm 11.50 1f 16.07.2024

शुभ शक्ति योजना के तहत 12 हजार 436 आवेदन प्राप्त हुए और 60 हजार 20 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया। 4 हजार 367 आवेदन अभी भी पेंडिंग हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री अजय सिंह (डेगाना): मेरा माननीय मंत्री जी से यह पूछना है कि आठ साल हो गए, आठ साल से ज्यादा समय से लगातार आवेदन पेंडिंग चल रहे हैं। पेंडिंग भी भौतिक सत्यापन के लिए चल रहे हैं। मेरे क्षेत्र थावला की एक छोटा देवी मेघवाल है, जिन्होंने 2016

में ऑनलाइन आवेदन किया था, अभी भी उनका आवेदन पेंडिंग है, भौतिक सत्यापन के लिए, यह बहुत गम्भीर बात है। इस तरह का कोई भी अधिकारी...

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछिए।

श्री अजय सिंह (डेगाना): इसमें आपको यह तय करना चाहिए कि एक महीने में कराओ या दो महीने में। ऐसे अधिकारी को आप आज ही तुरंत सस्पेंड करे जो इसका आठ-आठ साल से इसका निस्तारण नहीं कर रहे।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जो आपने बताया कि भौतिक सत्यापन छोटी देवी मेघवाल जी का नहीं किया गया, उस पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही यह भी बताना चाहूंगा कि आपने आठ साल का विषय रखा, पूर्ववर्ती पांच साल की सरकार थी, जो सोई हुई सरकार थी, जिसने कोई कार्य नहीं किए, जिसकी वजह से श्रमिकों को बहुत नुकसान हुआ। इस तरह की जो भी कमियां रही हैं, उसको हम दुरूस्त करके आम जन को, श्रमिकों को लाभ पहुंचाएंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न।

श्री अजय सिंह (डेगाना): जो रिजेक्शन हुआ है, उसको आप वापस दिखवाएं।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): जो रिजेक्शन है उस पर कठोर कार्यवाही कराई जाएगी जांच कराकर। ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्षः आप बीच में नहीं बोले। इनको अनुमति दी है, आपको नहीं दी है ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। 2013 से 2018 एवं 2018 से 2023 दोनों कार्यकाल में जो योजनाएं थी, उनमें कितना-कितना आपने खर्च किया, दोनों पांच-पांच साल का आ जाएगा, नम्बर एक। अब जिनका भुगतान पेंडिंग है वह आप कब तक कर देंगे। शुभ शक्ति योजना आज के समय बंद है तो किस तारीख से बंद है, यह भी आप बता दीजिए।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, यदि आप सक्रिया होते तो मेरे ख्याल से प्रश्न ...(व्यवधान)... आप जवाब सुनिये ना। गम्भीरता तो आज दिखा रहे हैं। आप खुद इस विभाग के मंत्री थे, अगर गम्भीर होते तो यह प्रश्न पूछने का औचित्य ही नहीं होता। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः प्रश्न बताइये।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने जो बात कही, आपकी बात का हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपने राजस्थान की जनता, श्रमिकों के लिए प्रश्न उठाएं, उनका हम तुरंत समाधान कराएंगे, बिलकुल। ...(व्यवधान)... हम कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री जसवंत सिंह गुर्जर। श्री जसवंत सिंह गुर्जर ...(व्यवधान)... श्री जसवंत सिंह गुर्जर।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, यह प्रश्न नागौर का था और यदि आप पूरे राजस्थान का पूछेंगे तो पूरे राजस्थान का आंकड़ा लाकर देंगे आपके सामने। पूरे आंकडें के साथ देंगे, नागौर का प्रश्न था ...(व्यवधान)... बिलकुल, आपको लाकर देंगे।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। श्रीमती इन्द्रा ...(व्यवधान)...

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): प्रश्न संख्या 100

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पांच साल का पूछा, पांच साल का जवाब दिया मैंने। आप कहेंगे दस भी...(व्यवधान)... पूरे साल का लाकर देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती इन्द्रा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): प्रश्न संख 101 ...(व्यवधान)..

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): प्रश्न संख्या 100 ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी। श्रीमती इन्द्रा।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में...

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): 101 ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नो, खतम होने के बाद का था। श्रीमती इन्द्रा का प्रश्न है, उत्तर दीजिए। आपने प्रश्न पूछ लिया। मंत्री जी।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बोलने पर खड़े नहीं होते। यह हल्ला मचाएंगे तो मैं प्रश्न पूछूंगा, आगे बढ़ूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): मैं प्रश्न संख्या 100 बोल चुका हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: श्री जसवंत सिंह गुर्जर, पूछिए।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाडी में पर्यटन विकास हेतु पंचायत कुदिन्ना पंचायत समिति...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए। क्वेश्चन पूछो , 100 नम्बर।

बाड़ी के सूवा देवहंस किले के जीर्णोद्धार की योजना

100. श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाडी में पर्यटन विकास हेतु पंचायत कुदिन्ना पंचायत समिति बाडी में स्थित सूवा देवहंस के किले का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

पर्यटन मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बाडी के ग्राम- कुदिन्ना में स्थित सूवा देवहंस किले का जीर्णोद्धार करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

यह किला राज्य के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन संरक्षित स्मारकों की श्रेणी

में सम्मिलित नहीं है। यह किला वन भूमि में स्थित है, जो कि राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के अंतर्गत धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व के क्रिटीकल टाइगर हेबीटेट (सीटीएच) का भाग है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): मंत्री महोदया, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि बाड़ी में सैंक्शन घोषित हो गई है, पर्यटन की दृष्टि से भी इस किले का जीर्णेद्धार होना बहुत जरूरी है। स्वतंत्र सेनानी देवहंस सूवा, जिनकी वजह से इस देश को आजादी मिली, जिन्होंने कुर्बानी दी, उस व्यक्ति के लिए अगर किले की मरम्मत नहीं हो, ठीक नहीं हो तो सरकार की मंशा मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आप उसका सर्वे करवाए। लाखों की तादाद में लोगों की आस्था का केन्द्र भी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ...(व्यवधान)... नहीं है तो इसे योजना में शामिल करे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, निवेदन नहीं, प्रश्न पूछिए।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): इसको शामिल करने की मंशा रखते हैं क्या, मुझे यह बताए।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी, क्योंकि क्रिटिकल टाइगर हेबीटेट में यह आता है और आर्कियोलॉजी के मोन्यूमेंट्स में भी नहीं है। जैसा कि हम सब समझते हैं और मुझे भी लगता है कि बिलकुल इसमें जीर्णोद्धार का काम होना चाहिए। आपने आज जो बात रखी है प्रयास रहेगा कि इस पर कार्यवाही हो। हम लोग जो भी कर सकते हैं, आप भी जानते हैं फॉरेस्ट एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है। पूरा प्रयास रहेगा कि यहां इसमें कैसे काम करवाया जा सकता है, जीर्णोद्धार करवाया जा सकता है।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): मैडम, सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिग कमेटी से ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आपको अनुमति नहीं है। माननीय सदस्य।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिग कमेटी से अनुमति लेकर करवा सकते हैं आप चाहे तो। अगर आपकी मंशा ही नहीं है तो वह अलग बात है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। प्रश्न पूछिए।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर (बाड़ी): आपकी नीयत ही अगर साफ नहीं है तो वह अलग बात है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नये हैं, प्रश्न पूछने का तरीका सीखें।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी को कहना चाहूंगी कि मंशा तो बिलकुल है। यह जरूर है कि पांच साल से, पहले सरकार थी उसकी मंशा तो नहीं थी, क्योंकि कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। हमारी सरकार पूरी मंशा भी रखती है और काम भी दिखाई देगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती इन्द्रा।

बामनवास में नरेगा में अनियमितता की शिकायतें

101. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही हैं कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास में नरेगा कार्य में कार्यरत श्रमिकों से पैसा वसूलने व जेसीबी द्वारा कार्य करा कर फर्जी मस्टररोल भरने की शिकायते प्राप्त हो रही हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास (श्री ओटा राम देवासी): जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बामनवास में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत श्रमिको से पैसा वसूलने की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संचालित कार्यों पर जेसीबी द्वारा कार्य कर फर्जी मस्टररोल भरने से संबंधित कुल 6 शिकायतें प्राप्त हुई है। उक्त शिकायतों में से 2 शिकायतें सही नहीं पायी गयी है तथा 4 शिकायतें सही पाई गयी है। सही पाई गई शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): मेरे पास जवाब आ गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: पूछिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूंगी कि मंत्री महोदय यह डिसाइड करे कि अधिकारी गलत जवाब पेश करते है या तथ्य छिपाते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? दूसरा, मैं रिकार्ड के साथ आई हूं। मेरे पास सारा रिकार्ड है। जिस तरीके से नरेगा का फर्जी काम हुआ, जिस तरीके से पैसे वसूले जाते हैं, मेरे पास सबके कागज है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि क्या सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अभी चल रहा है कि पंचायत समिति प्रधान का, प्रत्येक व्यक्ति के 100 रुपये उगाहे जाते हैं, जब उसकी टॉस्क लगाई जाती है, किसी भी नरेगा के कार्य की टॉस्क, मज़दूरों की एक महत्वपूर्ण योजना है केन्द्र सरकार की, जो कि हमारी सरकार ने पिछले टाइम की थी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): उस नरेगा के कार्य के अन्दर अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये खाता है तो वह कितना बड़ा अपराध है। मंत्री महोदय, इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर, क्या इसकी जांच कराने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो। एक-एक करके प्रश्न पूछो।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह अवगत करानाचाहता हूं कि बामनवास में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यरत श्रमिकों से पैसा वसूलने की, उसमें हमारे पास 6 शिकायतें आई, उसमें से 2 शिकायतें सही पाई गईं।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, यह मेरा पहले वाला जवाब आ चुका है।

इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे हैं। यह जवाब तो मेरे पास आ चुका। मैंने यह कहा है कि आपने जो जवाब दिया है उसके अन्दर आपने कहा कि जी नहीं। मंत्री महोदय, एक बार बिराज जाए, तो मैं बोलू। मैं क्वेश्चन समझने के लिए बोल रही हूं। यह जवाब आ गया, उसके उपरान्त मैंने यह पूछा है कि आपने मना किया है कि ऐसा नहीं होता है लेकिन मैं तथ्यों व प्रूफ के साथ आपको बताऊंगी। मैं यह चाहती हूं कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इस पूरे प्रकरण की जांच कराने की मंशा रखते हैं या नहीं?

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि राज्य स्तरीय टीम कराकर, शिकयतें सही पाये जाने पर सरपंचों, अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ जरूर कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री मोतीराम। पीछे वाला प्रश्न है।

रेवदर के मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय का क्रमोन्नयन

97. श्री मोतीराम (रेवदर): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रेवदर में स्थापित मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय के स्थान पर अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न्यायालय अथवा कैम्प कोर्ट स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री जोगाराम पटेल): किसी स्थान पर न्यायालय का क्रमोन्नयन/स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उस क्षेत्र के अपर जिला न्यायालय स्तर के 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्तर के 1200-1500 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है।

वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार रेवदर मुख्यालय पर वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय न्यायालय स्थापित है व रेवदर में किसी भी प्रकार के न्यायालय/शिविर न्यायालय के सृजन /क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय में विचारार्थ लंबित नहीं है।

भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार रेवदर क्षेत्र के अपर जिला न्यायालय स्तर के 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्तर के 1200-1500 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

श्री मोतीराम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उत्तर आ गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उत्तर देने से पहले, रेवदर मुंसिफ कोर्ट में कितने मुक़दमे दर्ज हैं, कृपया यह सदन को बताएं।

VPS-RTM-16.07.2024-12.00-1g

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? आपके क्षेत्र रेवदर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय स्तर के 57 प्रकरण हैं सिविल के और 56 प्रकरण है फौजदारी के, इस तरह से कुल 113 प्रकरण है, वर्तमान में जिसकी सुनवाई जिला एवं सेशन न्यायालय, सिरोही कर रहा है और सिविल प्रकरणों की सुनवाई भी अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सिरोही कर रहा है। मेरा विनम्रता से एक निवेदन है हालांकि मैंने इसका जवाब नहीं दिया है। वर्तमान में हिंदुस्तान में, आप कहें तो एक मिनट और बोल जाऊं? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से टी.एस.पी. क्षेत्र में तृतीय श्रेणी गणित-विज्ञान अध्यापकों की 2020-21 की डीपीसी में चयन उपरान्त काउन्सलिंग से वंचित आशार्थियों की पुन: काउन्सलिंग करवाये जाने के संबंध में।

(2) श्री अभिमन्यु, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र संगरिया में जमाबन्दी ऑनलाइन किये जाने से काश्तकारों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(3) डॉ. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से पूर्व सरकार द्वारा बिना कार्य-योजना बनाए हिन्दी माध्यम के विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

(4) श्री मोतीराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर के रेवदर कस्बे से गुजरने वाले हाईवे पर बाईपास न होने से होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री रफीक खान, सदस्य की ओर से जयपुर शहर में बारिश के मौसम में आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री मोतीराम एवं श्री रफीक खान को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ के देवाणी फांटा से छापर तक की शेष सड़क का निर्माण शीघ्र पूर्ण करवाये जाने के संबंध में।

(2) डॉ. शिखा मील बराला, सदस्य की ओर से प्रदेश में भूमि का सर्वे डिजिटल के स्थान

पर मैनुअल करवाये जाने के संबंध में।

(3)श्री शंकरसिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर जिले की ग्राम पंचायत सेन्दडा के राजस्व ग्राम कोटडी के खसरा नम्बर 273, किस्म गैर मुमकिन दांती को गौशाला हेतु आवंटित किये जाने के संबंध में।

(4)श्रीमती शिमला देवी, सदस्य की ओर से प्रदेश में जनता जल योजना में 1994 से कार्यरत सहायक पम्प चालकों का मानदेय बढ़ाये जाने के संबंध में।

(5)श्री महेन्द्र पाल मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में रामगढ़ से आंधी एवं रायसर को जाने वाले स्टेट हाईवे की मरम्मत हेतु वन विभाग से एन.ओ.सी. जारी करवाये जाने के संबंध में।

(6)श्री रमेश खींची, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर के उपखण्ड लक्ष्मणगढ़ में विद्युत केबल को खुर्द-बुर्द करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही एवं नवीन केबल उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(7)श्री भगवाना राम सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की काटली नदी में अवैध बजरी खनन रोकने हेतु बोली लगाकर आवंटन करवाये जाने के संबंध में।

(8)श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), सदस्य की ओर से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटि सुविधा लागू करवाये जाने के संबंध में।

(9) श्री चुन्नीलाल सी.एल.प्रेमी बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में सहकारी शुगर मिल का पुनर्संचालन करवाये जाने के संबंध में।

(10) श्री अतुल भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के बरसाती नालों का समुचित निकास न होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(11) श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में अमानक दवाइयों के विक्रय एवं दवाइयों के अनियंत्रित विक्रय मूल्य अंकित किए जाने पर रोक लगाये जाने के संबंध में।

(12) श्री विनोद कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में सुनवाई हेतु समयावधि निर्धारित किये जाने के संबंध में।

(13) श्री छगनसिंह राजपुरोहित, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर की भाद्राजुन तहसील में बांकली सिंचाई परियोजना का कार्य प्रारम्भ नहीं होने के जिम्मेदार संवेदक एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

(14) श्री पब्बाराम विश्नोई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फलौदी के चिकित्सालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के संबंध में।

(15) श्री ललित मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के ग्राम कलोनी में प्रस्तावित हाइड्रो-पॉवर प्लांट के स्थान निर्धारण हेतु पुनः सर्वे कराये जाने के संबंध में।

आज क्योंकि बजट का रिप्लाई भी होना है और बजट पर विपक्ष के नेता भी बोलेंगे और अन्य माननीय सदस्य भी बोलेंगे इसलिए आज 295 पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया

परिशिष्ट देखें।)

पर्ची

आज दिनांक 16.07.2024 को शून्यकाल में बोलने हेतु 50 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं जो निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	पर्ची सं.	मा. सदस्य का नाम	विषय
1.	13	श्री कंवरलाल	अवैध खनन तथा बजरी की महंगी दरों के सम्बन्ध में।
2.	49	श्री उदयलाल भडाणा	यूआईटी, भीलवाड़ा में हुए घोटालों के सम्बन्ध में।
3.	18	श्री कालूराम	चौमहला क्षेत्र में चाचूर्णी नदी व काली सिंध पर बांध बनाने व चम्बल नदी पर एनिकट बनाकर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में।
4.	11	श्री हमीर सिंह भायल	सिवाना विधान सभा क्षेत्र के उप जिला अस्पताल सिवाना और सी.एच.सी. सिणधरी में डायलिसिस मशीन की मांग और समदड़ी अस्पताल के नवीन भवन के लिए चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध करवाने की मांग पर चर्चा के लिए।

सदस्य की गिरफ्तारी

अभिमन्यु, श्री, सदस्य का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 148 के तहत डिटेंशन एवं रिहाई

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री अभिमन्यु पूनिया, सदस्य, राजस्थान विधान सभा को दिनांक 04.07.2024 को नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं एवं पेपर लीक प्रकरण की घटनाओं को लेकर रेलवे स्टेशन, गांधीनगर, जयपुर पर 'रेल रोको' आंदोलन के दौरान नारेबाजी करने एवं प्लेटफार्म पर बैठ जाने पर उक्त प्रदर्शन के दौरान लोक शांति विक्षुब्ध होने को दृष्टिगत रखते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-148 के तहत जीआरपी थाना, जयपुर पर समय करीब 12.30 पीएम पर लेकर आये एवं समझाइश कर शांतिपूर्वक डिस्पर्सल की कार्यवाही सम्पादित की गई।

दिनांक 16 जुलाई, 2024 को सदन में सूचना को पढ़ा गया।

स्थगन प्रस्ताव। श्री मोतीराम।

आप सब एक साथ नहीं उठें। धीरे-धीर जाएं। सदन को खाली नहीं करना है। 1.00 बजे

से 2.00 बजे तक लंच होगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

रेवदर कस्बे में बाईपास के अभाव में कारित दुर्घटनाएं

श्री मोतीराम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो हाईवे रोड चल रहा है, वह पूरी आबादी क्षेत्रों से गुजरता है। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको कहें कि मंत्रियों से उनके चैम्बरों में मिला करें। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सदन में गरिमामय व्यवहार की वांछनीयता व

माननीय सदस्यों से अपेक्षित नियमानुकूल आचरण

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्रीजी, खड़े न हो। यह सदन है। एक सैकण्ड। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि यह सदन है। माननीय सदस्य इधर देखें। माननीय सरदारजी, मैं कुछ कह रहा हूं।

माननीय सदस्यों से मेरा यह निवेदन है कि हम जनता के द्वारा चुनकर इस पवित्र सदन में आये हैं, यहां की कुछ मर्यादाएं हैं, यहां के कुछ नियम है। जैसे ही प्रश्नकाल खतम होता है तो सब उठकर इधर से उधर जाने लगते हैं। अगर आपको मंत्रियों से मिलना है तो उनके कमरों में जाकर मिलें, उनके आवास पर जाकर मिलें, यहां आप न मिलें। विपक्ष के लोगों को भी यही कहना है कि यहां आपस में बातचीत एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर करते हैं, उस पर भी आप रोक लगायें।

हम सभी सदन के अन्दर कहां से आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आप नियमों का पालन करें। कल एक सदस्य यूं बैठे थे अपनी सीट पर तो यह सदन की मर्यादा नहीं है। कैसे बैठें, कैसे जायें, कैसे उठें, किसी के आगे से होकर नहीं जाना, वैल में से नहीं जाना, वैल में नहीं आना, अपनी सीट पर खड़े होकर अपनी बात को कहनी है और जब आपको कहा जाए कि बैठ जाओ तो उसमें बैठने का जो नियम है, उसका पालन करें।

सभी माननीय सदस्य कल यहां आने से पहले नियम 269 पढ़कर आएं। जो किताब आपको दी गयी है, उसको पढ़कर आएंगे तो सदन को चलाने में सुविधा रहेगी और सदन की गरिमा बनी रहेगी।

आगे चलिये। माननीय मोतीरामजी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

रेवदर कस्बे में बाईपास के अभाव में कारित दुर्घटनाएं

श्री मोतीराम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पूरा हाईवे आबादी से गुजरता है। जैसे शहर में होकर करूटी, रेवदर और मंडार ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी, मैंने सबके लिए कहा पर आप यहां चलकर आ गये। 1.00 से 2.00 बजे तक लंच इसीलिए ही किया है कि आप सबसे मिल ले।

श्री मोतीराम (रेवदर): वहां पर हाईवे के कारण से कई लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, डोटासराजी हर बात पर खड़े हो जाते हैं क्या उनको अनुमति है?

श्री अध्यक्षः नहीं, इनको भी अनुमति नहीं है। इनको भी नहीं है और आपको भी नहीं है, दोनों को नहीं है। आप दो मिनट में बोलिये।

श्री मोतीराम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि हाईवे की वजह से कई लोगों के एक्सीडेंट वहां पर होते हैं। दो-तीन दिन में वहां पर हादसा होता रहता है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बाईपास निकाला जाये ताकि एक्सीडेंट से लोग बच सकें।

SSY/RTM/16.07.2024/12.10/1h

वास्तविक स्थिति यह है कि मेरी विधान सभा में ना तो एक भी ट्रोमा सेंटर है, चिकित्सकों की कमी भी है। जब वहां पर एक्सीडेंट होता है तो उन लोगों को पालमपुर गुजरात स्टेट में ले जाना पड़ता है। वहां गरीब जनता बर्बाद होती है। वहां के डॉक्टरों ने धंधा बना रखा है। अगर छोटा सा एक्सीडेंट होता है तो ऑपरेशन करके गरीब आदमी को बर्बाद किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरी विनती है कि मेरी विधान सभा को बाई पास दिया जाये ताकि लोगों को इससे मुक्ति मिल सके।

श्री अध्यक्षः चलिये, धन्यवाद। श्री रफीक खान।

जयपुर में बारिश से आमजन को अनुभूत कठिनाइयां

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस सीजन में बारिश से पूरे जयपुर शहर के अन्दर बुरे हालात हैं। जगह-जगह खड्डे बन चुके हैं, खास तौर से जो जयपुर शहर के आउटस्कट्र्स में जो हिल एरिया हैं, कच्ची बस्तियां हैं। अभी कुछ दिन पूर्व की बात है कि आजाद नगर कच्ची बस्ती है, वहां एक फोरेस्ट और स्कूल की दीवार गिर गयी, उससे बहुत सारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गयी। वहां ना तो कलेक्टर की तरफ से कोई कंपनसेशन है, ना कोई सर्वे है, ना कोई सरकार ने संज्ञान लिया है।

मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे मामले जो जयपुर शहर के अन्दर अतिवृष्टि की वजह से उत्पन्न हो गये हैं, उन सब पर कार्यवाही करें। जहां आमजन का नुकसान हुआ है, उनको फायदा देने की कोशिश करें। उनको मुआवजा मिले, कंपनसेशन मिले।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि पूरे शहर में जब पानी बहकर के आता है तो वह

गंदे पानी में तबदील हो जाता है। कल मेरी विधान सभा आदर्श नगर में बहुत सी जगह गंदा पानी, नालों का पानी पीने के पीने के साथ मिल गया। उससे उत्पन्न स्थिति यह है, यह सबके सुनने की बात है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, धीरे बोलिये। माननीय श्रीचन्द जी, रफीक खान कुछ सुनाना चाह रहे हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, खास तौर से पीएचईडी मंत्री को मैं सुनाना चाहता हूं कि गंदा पानी पीने के पानी के साथ आ रहा है। एसएमएस अस्पताल में बहुत सारे मरीज भर्ती हैं। जब लू का प्रकोप चल रहा था तब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बहुत सारे लोग लू से मर गये। गंदे पानी से, बीमारी से आदमी नहीं मरें, इस बात का ख्याल और संज्ञान ले लिया जाये। आम आदमी को फायदा दिया जाये। जगह-जगह गड्ढे हो रहे हैं, उनका सर्वे कराकर के अभी से उनको ठीक किया जाये। कोई ऐसी स्थिति ना आ जाये कि बाढ़ आ जाये, अतिवृष्टि हो जाये, उसके पुख्ता इंतजाम किये जायें।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि तमाम पैरामीटर्स पहले ही संज्ञान में ले लिये जायें और उन पर कार्यवाही की जाये। जहां नुकसान हुआ है उनमें सम्बन्धित विभाग को मार्गदर्शन देकर कंपनसेशन दिलाया जाये। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः जयपुर के साथ-साथ सभी शहरों का इसमें संज्ञान लिया जाये। श्री कंवरलाल। आपकी बात मैं कह रहा हूं।

पर्ची। ध्यानाकर्षित कर लो।

श्री कंवरलाल (अंता): अध्यक्ष महोदय, अवैध खनन एवं बजरी महंगी होने के सम्बन्ध में आज मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्षः ध्यानाकर्षित करता हूं, इतना ही एक वाक्य बोलना है। आप केवल ध्यानाकर्षित करता हूं, उतना बोलिये।

श्री कंवरलाल (अंता): पर्ची है।

श्री अध्यक्षः नये लोग जब ध्यानाकर्षण लगाते हैं, जरा पद्धति पढ़कर के आयें। पहली बात, सदस्य केवल खड़े होकर, विषय पढ़कर मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करता है। मंत्री जी अपना जवाब देंगे उसके बाद आपको कुछ बोलना है तो बोलिये।

श्री कंवरलाल (अंता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी। हो गया, बैठिये। आपने ध्यानाकर्षित कर लिया। मंत्री जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कौनसे मंत्री जी जवाब देंगे? मंत्री नहीं है। अध्यक्ष जी, कौनसे मंत्री जवाब देंगे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री है ही नहीं। मंत्री ही नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हद हो गयी।

श्री अध्यक्ष: कौन है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बताओ कौनसे मंत्री हैं?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): पर्ची है। बोलिये।

श्री अध्यक्ष: हां, कंवरलाल बोलिये। इस पर जवाब नहीं आता है। पर्ची पर जवाब नहीं आता।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अवैध खनन व बजरी की महंगी दरें

श्री कंवरलाल (अंता): अध्यक्ष महोदय, अवैध खनन और बजरी में सभी माननीय सदस्यों के मन की बात, दिल की बात, पूरी जनता की बात है।

पहले बजरी को कोई नहीं जानता था। नदियां पहले भी थीं, बजरी पहले भी थी, मकान पहले भी बनते थे, लेकिन जब से कांग्रेस सरकार, गहलोत जी आये और इन्होंने भ्रष्ट मंत्री +++ को बनाया, वह ब्रांड एम्बेसेडर बने। उसी दिन से बजरी और अवैध खनन का बोलबाला चालू हुआ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप सर्टिफिकेट देते हो?

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बीच में डिस्टर्ब नहीं। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य ...(व्यवधान)...

श्री कंवरलाल (अंता): बार-बार मत खड़े हुआ करो।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर अनुमति दी है। मैंने पर्ची पर अनुमति दी है। नो, नॉट एट ऑल। आप बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री कंवरलाल (अंता): पहले 1200 रुपये लिये जाते थे ...(व्यवधान)...

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: पर्ची लगायेंगे नहीं क्या ...(व्यवधान)...

श्री कंवरलाल (अंता): आपको पता होना चाहिए। थोड़ी शर्म आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर बोलो।

श्री कंवरलाल (अंता): यह एम.जे. गुडियाल कौन है? यह +++ का पार्टनर है। उसको 28 हजार करोड़ का ठेका बीसलपुर बांध का दिया हुआ है। आप लोग बार-बार खड़े हो जाते हो। यह बात गलत है ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: नाम बोला होगा तो देखूंगा। किसी के नाम से नहीं होगा ...(व्यवधान)...

श्री कंवरलाल (अंता): आपकी पार्टी का जो विधायक था सांगोद से, वह बार-बार मांग उठाता आया है। सिर मुंडवा लिया है। गंजा होकर आ गये।

श्री अध्यक्षः आप पर्ची पर बोलें जो कुछ बोलना है। श्रीमती इन्द्रा, मैं नाम पुकार रहा हूं। जब देखो तब खड़ी होकर आ जाती हो। यह अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी।

श्री कंवरलाल (अंता): माननीय मोदी जी जब अंता में आये तब उन्होंने भी उठाया था, अरे +++ खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। उनको बचाने के लिए आप खड़े हो जाते हो बार-बार में डोटासरा जी। यह बात गलत है।

श्री अध्यक्षः अपनी सीट से बोलो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री कंवरलाल (अंता): आपके कैबिनेट मंत्री ने किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र अंता में 2 नदियां बहती हैं।

श्री अध्यक्षः पर्ची पर बोलने का ...(व्यवधान)... माननीय डोटासरा जी, सुनने का माद्दा रखो। बैठिये, अब उनको बोलने दो। आप भी कल पर्ची डाल लेना। आप बैठिये, पर्ची डाल लेना। नो, शान्ती लाल धारीवाल का कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): 000

श्री कंवरलाल (अंता): विधान सभा क्षेत्र अंता में और पूरे बारां में बहुत महंगी बजरी है।

श्री अध्यक्षः यह क्या बात हुई? उनकी पर्ची है। आप पर्ची लगाओ। आपका नाम आयेगा तो आपको बुलवाऊंगा।

श्री कंवरलाल (अंता): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह 2013 से परमिशन रुकी हुई है, उसकी अनुमति दिलायी जाये ताकि गरीबों के घर बनें।

यह जो भ्रष्टाचार माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने, आपके चोरों के सरदार ने जो काम किया है, उनको सज़ा दी जाये।

श्री अध्यक्षः अगली पर्ची। श्री उदयलाल भड़ाणा।

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा में घटित घोटाले

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय, नगर विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा के अन्दर नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा जोनल डवलपमेंट प्लान जोन-सी का पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय रिवाइज प्लान अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी, जिसमें बिना आम जन की जरूरत के, केवल भू-माफियाओं को करोड़ों का लाभ दिलाने हेतु प्लान प्रस्तुत किया। जिस पर 12 से 15 आपत्तियां प्राप्त हुई थी।

तत्समय के सचिव श्री अभिषेक खन्ना द्वारा उक्त प्रस्तावित जोनल प्लान डवलपमेंट जोन-सी रिवाइज को निरस्त कर दिया था। उक्त प्रस्तावित प्लान में लगभग 200 बीघा भूमि मास्टर प्लान, 2035, जोनल डवलपमेंट प्लान जोन-सी में वेयरहाउस, गोदाम प्रयोजनार्थ को आवासीय व लगभग 600 बीघा भूमि को जो शैक्षणिक, हाई वे आदि परिधि नियंत्रण पट्टी

में औद्योगिक दर्शा कर भू-माफियाओं को लाभ पहुंचाने का पुनः प्रयास किया जा रहा है।

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को रिवाइज प्लान अनुमोदन की जरूरत क्यों पड़ गयी? उक्त प्रस्तावित जोनल डवलपमेंट प्लान जोन-सी निरस्त करने योग्य है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय नगर विकास न्यास द्वारा प्रस्तावित 200 फीट आउटर रोड, रिंग रोड जो कि सदर थाने से आगे होकर चित्तौड़ रोड पर समेला को मिलती है, उक्त रोड प्रस्तावित है। अभी डिमार्केशन भी नहीं हुआ। काश्तकारों को नोटिस भी नहीं दिया गया। लगभग 68 बीघा भूमि का मुआवजा नगर विकास न्यास द्वारा शहर के पॉश कॉलोनी तिलक नगर में कर दिया गया है। उस जमीन पर अभी भी फसल खड़ी है, लेकिन फिर भी पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं के इशारे पर तिलक नगर में उसका मुआवजा करोड़ों रुपयों का दे दिया गया है। जिसका नुकसान नगर परिषद को हुआ। भू-माफियाओं को करोड़ों रुपयों का फायदा हुआ।

न्यास को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? यहां रोड की डिमार्केशन भी नहीं है। काश्तकारों को नोटिस भी नहीं हैं। धारा 51 के तहत कर्मचारियों, तत्समय के अधिकारियों और भू-माफियाओं की सांठ-गांठ से मुआवजा का खेल चला।

Spp/Rtm/16.7.2024/12:201j

जिसकी फाइलें भी गायब हैं। राजस्व ग्राम भिन्न होने की शर्त पर राज्य सरकार से स्वीकृति अपेक्षित हैं, जोकि नहीं ली गयी। नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा चित्तौड़ रोड स्थित राजस्व ग्राम मण्डफिया की आराजी संख्या 587 रकबा पांच बीघा भूमि जो औद्योगिक 99 साल की लीज होल्ड पर दी है। एक बीघा भूमि का व्यावसायिक संपरिवर्तन कराकर उसको 160 फीट चौड़ी सरकार का मार्ग अधिकार में आना बताकर न्यास की पॉश कालोनी पटेल नगर योजना में व्यावसायिक छोटे-छोटे भूखण्ड 100 प्रतिशत मुआवजा देकर बिना DLC निर्धारित किये राजस्व ग्राम भिन्न होने पर भी राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक होने के बावजूद नहीं ली गयी। बिना स्वीकृति लगभग 25 करोड़ के भूखण्ड मुआवजा स्वरूप दे दिया गया। भूमाफिया और अधिकारियों की सांठ-गांठ से न्यास को लगभग 20 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा राजस्व ग्राम आटून की आराजी नंबर 380, 413, 415, 416, 423 व आराजी संख्या 373, 376, 377, 425, 379, 428, 429 तथा आराजी नंबर 417, 421, 422, 424 थी, जो कि नीमला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट के नाम से 90 ए किया गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह बोला जाता है, पढ़ा नहीं जाता।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): 95029, 95430, 02.01.2024, 95529 को प्रतिहारी किया गया, जिसकी सूचना समाचार पत्रों में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं अगला बोल रहा हूं, खत्म करिये। यह पढ़ा नहीं जाता, बोला जाता है। इसमें दो मिनट का टाइम होता है।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): नगर विकास न्यास ने 31 फाइलों को पूर्ववर्ती कांग्रेस

सरकार द्वारा उनको गायब कर दिया गया। नगर विकास न्यास की जो करोड़ों-अरबों रुपये की जमीन थी, उसको पूर्ववर्ती सरकार के अधिकारियों और नेताओं ने मिलीभगत करके गायब कर दिया। अभी जैसे ही अखबारों में छपा, राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री भजनलाल जी शर्मा ने ACD गठित की और ACD गठित करने के बाद वहां यू आई टी गयी, लेकिन वह फाइलें ही गायब हैं। मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि यह जितने भी घपले और घोटाले हुए हैं उनकी सी आई डी, सी.बी. से जांच कराकर हमारे भीलवाड़ा के लोगों को न्याय प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कालूराम।

चौमहला में बांध निर्माण व चम्बल नदी पर लिफ्ट सिंचाई परियोजना

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में तहसील गंगधार में चाचुर्णी नदी और काली सिंध नदी चम्बल की सहायक नदी है जिसमें राजस्थान का करीब 300 क्यूबिक मीटर पानी व मध्य प्रदेश से 2500 क्यूबिक मीटर पानी आता है, जिसका करीबन 500 मिलियन घन मीटर पानी व्यर्थ बहकर निकल जाता है। इसके संधारण के लिये यहां पर कोई बांध नहीं है। काली सिंध नदी पर बांध निर्मित हो जाता है तो इससे सिंचित क्षेत्र में वंचित व पेयजल क्षेत्र का उपयोग इससे हो सकेगा। इसमें यहां आने वाले इसी वर्ष में पानी की बड़ी किल्लत के कारण यहां पेयजल की स्थिति बड़ी खराब हो गयी थी तो यहां काली सिंध नदी पर बांध बनता है तो चौमहला और डग क्षेत्र को इसका फायदा मिलेगा।

साथ ही हमारी चंबल नदी हमारे क्षेत्र से बहकर निकलती है तो माननीय महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि चम्बल नदी मध्य प्रदेश मेरे विधान सभा क्षेत्र से बिलकुल सटीक है। मध्य प्रदेश में हजारों-लाखों बीघा भूमि पर मध्यम सिंचाई परियोजना लागू की गयी है और राजस्थान में इसमें गांधी सागर कैचमेंट एरिया की वजह से इसमें मेरे क्षेत्र में पानी नहीं लिया जा रहा है। अगर चम्बल नदी में एक एनिकट बनाकर या लिफ्ट परियोजना बनाकर सिंचाई सुविधा कर दी जाती है तो 15 हजार एकड़ भूमि यहां पर सिंचित हो सकती है, क्योंकि यहां काफी भूमि बंजर पड़ी हुई है और पानी के लिये इस सीजन में बहुत ही परेशानी आयी है। पेयजल के लिये भी हमने टैंकरों से सप्लाई की है। डग और आसपास के क्षेत्रों में पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत है और माननीय मंत्री महोदय को मैंने इसके लिये पत्र भी दिया हुआ है।

मैं माननीय मंत्री महोदय और हमारे उप मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आज ही रिप्लाई में इसकी डी.पी.आर. घोषित कराने के लिये कम से कम काली सिंध नदी में बांध बनाने की डी.पी.आर. सम्मिलित की जाये ताकि इस क्षेत्र की जनता को बहुत फायदा मिलेगा। आप इस पर ध्यान दें। मैंने आज मुख्य मंत्री महोदय को भी लैटर दिया है। माननीय सिंचाई मंत्रीजी को भी दे रखा है। आज ही इसको अपनी रिप्लाई में सम्मिलित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः आपका तो हो गया शायद, पुराने वाले का देना चाह रहे हो? पहले वाली पर्ची का। बाद में, लास्ट में। श्री हमीर सिंह भायल। लास्ट में चारों में से कोई देना चाहते हैं तो दे देना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसी परम्परा नहीं है।

श्री अध्यक्षः पर्ची का जवाब दिलाना, आप ही तो कहते हो पर्ची को जवाब दिलाओ। जब कोई मंत्री देना चाह रहा है तो क्या अनुमति है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप नियम कर दो कि सारी पर्चियों पर जवाब मंत्री देंगे।

श्री अध्यक्षः सारी नहीं, जो मंत्री देना चाहेगा तो उसको अनुमति है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अब आप थोड़ा विराज जाओ। ..(व्यवधान).. आप थोड़ा बिराज जाओ।

श्री अध्यक्षः आप बैठो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मनमर्जी थोड़े चलेगी।

श्री अध्यक्षः मनमर्जी चलेगी यहां तो। नियम बनाने से...(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नियम से ही चलेगा।

श्री अध्यक्षः नियम से चल रहे हैं। नियम कौन तय करेगा? नियम अध्यक्ष तय करेगा। नो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सदन में परम्परा से चलना चाहिये। ऐसा नहीं होता।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): आप विराजें। प्रतिपक्ष के नेता महोदय विराजिये।

श्री अध्यक्षः बैठिये। आप बैठिये। हर बात पर बोलना अच्छा नहीं है। आप दिन में एक बार, दो बार, मैं सुबह से गिन रहा हूं। एक बार, दो बार कभी मुद्दा आया, आपने खड़े होकर उठाया। विपक्ष के नेता हैं आपके। हर बात में आप खड़े हो जाओगे। यानी यह अनुमति किसी सदस्य को नहीं है। मैं, माननीय सदस्य, आपको स्पेशली कह रहा हूं। आप सुबह से प्रश्न काल से लेकर 10-11 बार आप खड़े हो। यह अनुमति नहीं है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): आपके हाथ में दर्द है इसलिये आप चाहते नहीं है। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप पर्ची पर बोलिये माननीय सदस्य।

सिवाना उप जिला अस्पताल और सिणधरी सी.एच.सी. में डायलिसिस मशीन व समदड़ी अस्पताल में चिकित्सीय उपकरणों की उपलब्धता

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद। विधान सभा क्षेत्र सिवाना, जिसके परिप्रेक्ष्य में 5 लाख की आबादी आती है, सरकार द्वारा सी एच सी लेवल के अस्पताल में भी डायलिसिस मशीनें दे रखी हैं, लेकिन सिवाना में आजकल किडनी की ज्यादा बीमारी होने की वजह से सिवाना जिला अस्पताल है इसमें डायलिसिस मशीन की अति आवश्यकता है। मैं आपके

माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह व्यवस्था करवायें। सी एच सी सिणधरी क्षेत्र में भी पांच बड़े हाईवे हैं और आबादी भी खूब है। वहां भी सी एच सी है पर डायलिसिस मशीन नहीं है, तो वहां पर भी मशीन उपलब्ध करवाकर जनता को राहत दिलवायें।

नवीन भवन समदड़ी और सिवाना में बनकर तैयार हैं, जिसमें चिकित्सा उपकरण 20 लाख के सात माह से लंबित पड़े हैं। इसको भी जल्दी करके उपकरण भिजवायें ताकि नये अस्पताल में मरीजों का इलाज आसानी से हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठकर बात करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): सिवाना में डायलिसिस मशीन, सिणधरी में डायलिसिस मशीन, सिणधरी और सिवाना में उपकरण और एक ट्रोमा सेंटर, महाराष्ट्र और गुजरात से लगाकर भटिण्डा तक यह राजस्थान से सांचौर, गुढामालानी और सिणधरी होती हुई बालोतरा, यह हाईवे रोड है तो वहां नजदीक में 100-125 किलोमीटर पर कोई ट्रोमा सेंटर नहीं है। एक्सीडेंट हो जाता है और कई दुर्घटनाएं होती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, में आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसी सत्र में घोषणा करके सिवाना की जनता और आमजन जो महाराष्ट्र से आने-जाने वाले हैं, उनको राहत दिलाने की कृपा करावें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब देना चाह रहे हैं?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन था। कार्य सूची के अनुसार स्थगन प्रस्ताव के बाद 295, उसके बाद पर्ची और उसके बाद ध्यानाकर्षण था। आपने बीच में ध्यानाकर्षण पुकार लिया। हमारे सभी मंत्री पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। मंत्री जवाब देने में सक्षम है पूरे मैटेरियल के साथ। इसीलिये मेरा निवेदन था।

श्री अध्यक्ष: ध्यान आ गया। माननीय मंत्रीजी ध्यान आ गया कि पर्ची के समय उनको बोलने का अधिकार था, मैंने दे दिया।

अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री मनीष यादव।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

शाहपुरा (जयपुर) में बढ़ती आपराधिक घटनाएं

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में कानून व्यवस्था की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के अन्तर्गत पुलिस थाना शाहपुरा, मनोहरपुर, अमरसर का पूर्ण क्षेत्र एवं पुलिस थाना सामोद गोविंदगढ़ का आंशिक क्षेत्र आता है। चोरी के सम्बन्ध में विधान क्षेत्र शाहपुर में आने वाले थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी के विगत पांच वर्षों में 558 प्रकरण दर्ज हुए। इनमें से 51 प्रकरणों में चालान, 506 प्रकरणों में एफ आर. व एक प्रकरण वर्तमान में पेंडिंग है। वाहन

चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु पूर्ण रूप से गश्त निगरानी की जा रही है। संदिग्धों से समय-समय पर पूछताछ की जा रही है। अपराधों की रोकथाम हेतु चिह्नित क्षेत्रों में पुलिस जाप्ता लगाया जाकर समय-समय पर नाकाबंदी की जा रही है।

लूट- विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले थानों में विगत पांच वर्षों में लूट के 21 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 15 में चालान व 6 में एफ.आर. पेश न्यायालय की जा चुकी है।

महिला अत्याचार- विगत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले पुलिस थानों में महिला अत्याचार के 705 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 356 में चालान व 346 में एफ.आर. तथा 3 प्रकरण वर्तमान में पेंडिंग हैं,जिनका शीघ्र निस्तारण किया जायेगा।

Jyg/rtm/16.07.24/12.30/1k

नकबजनी- विगत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले पुलिस थानों में नकबजनी के 151 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 36 में चालान व 115 में एफआर, नतीजा न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

डकैती- विगत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले पुलिस थानों में डकैती के 4 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 2 में चालान व 2 में एफआर, नतीजा न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

आर्म्स एक्ट: विगत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले पुलिस थानों में आर्म्स एक्ट के 33 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 32 में चालान व 1 में एफआर, नतीजा न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

एनडीपीएस एक्ट- विगत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले पुलिस थानों में एनडीपीएस एक्ट के 42 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 40 में चालान व 1 में एफआर, नतीजा न्यायालय में पेश किया जा चुका है। वर्तमान में 1 प्रकरण पेंडिंग है।

वर्तमान में मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु समय-समय पर अभियान चलाए जाकर कार्यवाही की जा रही है।

अन्य चोरी- विगत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले पुलिस थानों में अन्य चोरी के 390 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 54 में चालान व 335 में एफआर, व 1 प्रकरण वर्तमान में पेंडिंग है। इसका शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के पुलिस थानों में दर्ज मुकदमों में त्वरितअनुसंधान का वांछित मुजरिमों की धरपकड़ पर नतीजा पेश न्यायालय पेश किया जा रहा है।

उप जिला अस्पताल शाहपुरा की परिधि व पार्किंग क्षेत्र में वाहन चोरी की शिकायतों पर पुलिस थाना शाहपुरा से 1 वाहन मय जाब्ता समय-समय पर गश्त हेतु लगाया जाता है तथा पुलिस थानों की मोबाइल वैन से समय-समय पर गश्त निगरानी की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो आंकड़े हैं, जो होम डिपार्टमेंट से प्राप्त हैं, अगर इसका ट्रेंड देखा जाए, इसको मैं माननीय सदस्य को दूंगा, क्राइम लास्ट फ्यू महीनों में बढ़ा

नहीं है वो या तो स्टेगनेंट रहा है या डाउन गया है। तो भी हमने प्रशासन को, पुलिस को कह दिया है कि उस क्षेत्र में कड़ी निगरानी की जाए और सख्ती से जो भी ऐसे केसेज होते हैं उनको डील किया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्ष का आंकड़ा आपने भी बताया कि चोरी के 948 प्रकरण दर्ज होते हैं, 105 प्रकरणों में चालान होता है, 11 प्रतिशत पुलिस को सफलता अनुसंधान में मिलती है। आप देखिए, ऐसे 841 प्रकरण हैं जिनमें पुलिस ने एफआर लगा दी, 841 प्रकरण का मतलब है कि पुलिस प्रशासन ने न तो कोई चोरों को आइडेंटीफाई किया, न कोई माल बरामदगी की। वाहन चोरी की हमारे विधान सभा क्षेत्र में आए दिन हमारे उप जिला अस्पताल शाहपुरा, आए दिन आप जवाब में, माननीय मंत्रीजी, कह रहे हैं या गृह विभाग से जो जवाब आया है कि वाहन से मय जाब्ता वहां पर निगरानी कर रहे हैं,ऐसे हालात और परिस्थिति आज के समय में बने हुए हैं कि वहां पर आए दिन मोटरसाइकिल चोरी होना हमारे क्षेत्र में अन्य चोरियां, जैसे मवेशी- भेड़-बकरी आदि गरीब लोगों के चोरी हो जाते हैं, यह आए दिन की बात है। यह लगभग 1 जनवरी, 2024 से 11 अप्रेल, 2024 के चोरी, नकबजनी के 69 प्रकरण दर्ज हुए हैं और 18 में केवल चालान पेश हुआ है, 30 मामलों में एफआर लगा दी, 30 मामलों में पुलिस न तो अभी तक चोरों को पकड़ पाई न माल बरामदगी कर पाई।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार की संगठित अपराध की घटनाएं हैं, जिस प्रकार की चोरी की घटनाएं हैं और विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मादक पदार्थों की बिक्री खुलेआम एनएच 48, चंदवाजी के निम्स अस्पताल से लेकर, क्योंकि यह राजस्थान हरियाणा बोर्डर का क्षेत्र है, जिस तरीके से पुलिस की नाक के नीचे यह जो धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, आए दिन वहां पर मादक पदार्थों की बिक्री तेज हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे शाहपुरा जिला अस्पताल में दिनांक 10 मई, 2024 को नशे में लिप्त व्यक्ति ने सरेआम एक निर्दोष युवक, मोहनलाल जाट की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। 10 लोगों को गम्भीर घायल कर दिया और जो व्यक्ति, जो अपराधी है, वो एक दिन पूर्व 151 के मामले में जमानत पर आया था, ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति क्षेत्र में बनी हुई है।

चोरी, महिलाओं के प्रति अपराध, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में बिक्री हो रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा और माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में इन बढ़ी हुई घटनाओं के बारे में विशेष रूप से कोई टीम बनाकर, चाहे वाहन चोरी के मामले हों, विशेष एसआईटी बनाकर मादक पदार्थों की जो बिक्री का प्रकरण है उसको विशेष रूप से संज्ञान में लें क्योंकि

आए दिन इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं और पुलिस की नाक के नीचे, पुलिस नाकाम है, आपके सामने जो जवाब पेश किया गया है, ऐसे हालात बने हुए हैं कि पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही, पुलिस नाकामी से बैठी रहती है और केवल एफ.आर. लगाने तक सीमित हो गई है, केवल एफआईआर दर्ज करने और उस पर एफआर लगाने तक सीमित हो गई है। हमारे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बहाल किया जाए, हमारे क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को रोका जाए, मवेशियों की चोरी की घटनाएं आम बात हो गई है। मादक पदार्थों का धंधा चल रहा है, सरकार विशेष एसआईटी बनाकर इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, कोई कहेंगे?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां वाहन चोरियों का मामला है, यह बहुत टिपिकल चीज है क्योंकि वाहन चोरी पर एफआर लगती है, कई लोग क्या करते हैं, कई इंटर स्टेट गैंग ऐसी बनी हुई है कि वाहनों को वे डिसअसेंबल करते हैं, उसको बताते हैं कि गुम हैं, चोरी हो गई है और खुद ही जाकर कहते हैं पुलिस को कि, साहब, एफ.आर. लगा दो, ताकि उसके इंश्योरेंस का क्लेम मिले। वाहन चोरी में यह बहुत ज्यादा है। फिर भी माननीय सदस्य ने लॉ एण्ड डिसऑर्डर के बारे में चर्चा की है, आईजी साहब को निर्देश देंगे, एसपी साहब को निर्देश देंगे कि प्रशासन को थोड़ा और टाइट करके इस क्राइम रेट को थोड़ा और कम किया जाए।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): विशेष एसआईटी गठित की जाए।

श्री अध्यक्ष: हो गया जवाब। ..(व्यवधान)... आपको पूरा समय दिया गया।

अगला, श्री भागचन्द टांकड़ा। ..(व्यवधान)...

बांदीकुई में 15 वर्ष पूर्व विच्छेदित कुओं के बिलों का घरेलू बिलों के साथ प्रेषण

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसानों के 15 से 20 वर्ष पूर्व काटे गए कृषि कनेक्शनों एवं ट्रांसफार्मर जमा किए जाने के बाद भी विद्युत कनेक्शनों के बिल की राशि उनके घरेलू बिलों में जोड़कर भेजी जा रही है।

श्री अध्यक्ष: आप यह कहें, 'जोड़ी जा रही है, इस पर ध्यान आकर्षित करता हूं।' आपको यह कहना चाहिए।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त विषयान्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन है कि बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन बकाया राशि पर काटे गए थे तथा उनके ट्रांसफार्मर निगम में जमा करवा दिए गए थे। परंतु उपभोक्ताओं द्वारा बकाया बिल राशि का भुगतान नहीं किया गया इस कारण बिजली के बिलों की राशि बकाया रह गई।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में उपभोक्ताओं के वर्षों पूर्व काटे गए विद्युत कनेक्शनों की बकाया

राशि का उपभोक्ताओं को नियमानुसार नोटिस जारी करने के उपरांत भी जिन उपभोक्ताओं द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई उनके द्वारा निगम के नियमानुसार डीसी और पीडीसी उपभोक्ताओं के बिलों की बकाया वसूली हेतु वर्तमान में सम्बन्धित चालू विद्युत कनेक्शन खाता संख्या पर बकाया राशि जोड़कर बकायादारों से ही वसूली की जा रही है। इसके उपरांत भी यदि कोई उपभोक्ता असंतुष्ट होते हैं तो नियमानुसार उनकी बकाया राशि को समझौता समिति के अधीन आपसी सहमति पर नियमानुसार संशोधन कर प्रकरण का संतोषजनक निस्तारण किया जाता है।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जब 15 से 25 साल पहले कनेक्शन काट दिए गए और उनके बिलों में वो बकाया पैसे अब जोड़े जा रहे हैं, 20-25 साल से कर्मचारियों का, अधिकारियों का कोई ऐसा नोटिस उनके पिछले समय में नहीं दिया गया तो पैसा वो अब ही क्यों किया जा रहा है? पिछले 15-25 साल पहले जब कुओं में पानी कम हो गया तो कृषि के कनेक्शन कुछ कट गए और कुछ कटवा दिए गए। लेकिन पिछले 20-25 साल तक उनके पास ना कोई नोटिस पहुंचा और उनसे या उनके परिवारजनों से, उनके बेटों से या उनके पोतों से अब पैसा जोडकर लिया जा रहा है। यह 15 25 साल के बीच में कर्मचारी कहां पर चले गए थे? उनका पैसा उस समय क्यों नहीं जोड़ा गया कि जिसकी डिमांड अभी की गई है?

MLS/RTM/16.07.2024/12:40/1l

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बकायेदारों की जब भी ऑडिट होती है या विभाग के ध्यान में आता है कि यह बकायेदार काफी लम्बे समय से लम्बित है, उन पर ही वसूली का प्रयास किया जाता है। बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य के क्षेत्र में 2024 तक की जो स्थिति है, उसमें बांदीकुई शहर में ऐसे 21 घरेलू कनेक्शंस हैं, जिन पर कृषि कनेक्शंस का पैसा जोड़कर भेजा गया और जिसकी राशि 5.43 लाख है। ग्रामीण क्षेत्र में 146 ऐसे घरेलू उपभोक्ता हैं जिनके कनेक्शंस पूर्व के कटे हुए हैं, उनकी राशि 10.45 लाख है। बसवा में 2 कनेक्शंस हैं, जिनके ऊपर 0.19 लाख है। बेजूपाड़ा में 16 ऐसे घरेलू कनेक्शंस हैं, जिनके ऊपर 4.82 लाख है। कुल-मिलाकर ऐसे 185 घरेलू कनेक्शंस हैं, जिन पर 20.79 लाख बकाया है, जिन्हें यह भेजा गया है।

इसमें एक नियम है। उस नियामक आयोग के नियमानुसार जो विद्युत आपूर्ति नियमों की शर्तें हैं, उनमें 2021 के क्लॉज 17(7)(d) में जो निहित प्रावधान हैं, उनके अनुसार ही यह वसूली जब बकाया रह जाती है तो उनके घरेलू कनेक्शंस के जो बिल चालू हुए हैं या किसी और कनेक्शन के, चाहे वे औद्योगिक हों या कुछ और हों, उन पर जोड़ने का नियामक आयोग का जो नियम है, उसके अनुसार ये जोड़ी जाती हैं। इसमें फिर भी वह सदस्य अगर असन्तुष्ट हैं तो इसमें सैटलमेंट की जो प्रक्रिया है, उसमें 20 हजार तक का सैटलमेंट एईएन के यहां किया जा सकता है, 50 हजार तक का एक्सईएन के यहां किया जा सकता है, 50 हजार से 5

लाख तक का एसई के यहां समझौता समिति में जाकर समाधान कराया जा सकता है।

एमनेस्टी स्कीम अभी चल रही है। इस सैटलमेंट के तहत कई उपभोक्ता आये भी हैं, जिन्होंने सैटलमेंट में आकर आवेदन किये हैं। उन्होंने वह राशि भी जमा करायी है 30 परसेंट, 40 परसेंट और वे सैटलमेंट भी चाहते हैं।

ऐसे उपभोक्ताओं का हम सैटलमेंट कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो आपके विधान सभा क्षेत्र के सदस्य हैं, हम उनके लिए विशेष प्रयास करके, कोई वहां कैम्प लगाकर भी उनका सैटलमेंट करके उन्हें राहत देने का प्रयास करेंगे। नियमानुसार वे सैटलमेंट कमेटी में आएं। यदि वे सैटलमेंट कराएंगे तो हम निश्चित रूप से उन्हें जो भी राशि है, उसके मूल पर ही सैटलमेंट करने के लिए मैं निर्देश करूंगा कि उन्हें एमनेस्टी के तहत लेकर उनकी मूल बकाया राशि पर सैटलमेंट कर दिया जाये।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, 15 से 25 साल के बीच में ऐसे कितने नोटिस विभाग द्वारा उन उपभोक्ताओं को दिये गये? सालों तक कोई नोटिस नहीं दिया गया और फिर अब उन्हें धमकी दी जाती है कि आपके कनेक्शंस काट दिये जाएंगे, तो मजबूरन वे समझौता समिति में जाकर अपना पैसा जमा करवाता है।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैंने अभी बताया माननीय सदस्य को कि 185 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके घरेलू कनेक्शंस पर कृषि कनेक्शंस की बकाया राशि जोड़कर उनके बिल में भेजी गयी है, जो कुल-मिलाकर 20.79 लाख होती है। इस पूरे विधान सभा क्षेत्र में 185 ही ऐसे पुराने उपभोक्ता हैं, जिसमें से कई उपभोक्ता सैटलमेंट करा चुके हैं, कुछ का प्रक्रियाधीन है और बच रहे हैं।

देखिये, यह एक प्रक्रिया है और नियम है और उसके तहत वसूली नियामक आयोग के प्रावधानों के अनुसार की जा रही है। अगर उन्हें नहीं करते हैं तो फिर ऑडिट में भी ऑब्जेक्शन आता है। निश्चित रूप से निगम को भी आपने देखा है कि हमने तो 62 हजार करोड़ का कर्जा अपने माथे लिया था, फिर 90 हजार करोड़ का और कर्जा पिछली सरकार ने कर दिया तो इस विभाग को चलाना है और अगर बिजली देनी है तो निश्चित रूप से बकाया भी वसूल करना पड़ेगा।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय मंत्री महोदय, जिन अधिकारियों ने 15-15 साल तक कोई नोटिस नहीं दिया, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करने का आपका विचार है?

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न काल नहीं है। ध्यान आकर्षित कर दिया, आपका उत्तर आ गया। बैठिये।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। डॉ. दयाराम परमार।

समिति प्रतिवेदन

पर्यावरण सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (क्र.सं. 1 व 2)

डॉ. दयाराम परमार (खेरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से

पर्यावरण सम्बन्धी समिति के 2024-25 के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

याचिका

मुलेवा (आहोर) में वर्षा ऋतु में विद्युत प्रसारण नहीं किया जाना

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम मुलेवा में बिजली की लाइन बलदरा होते बांध के भराव क्षेत्र में आने के कारण वर्षा ऋतु के दौरान बिजली नहीं आने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेश धाकड़। एक मिनट में सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, भाषण नहीं।

सूचना

मंडावरी ग्राम (बेगूं) में फूड पॉइजनिंग से मौतें

डॉ. सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बेगूं में मंडावरी गांव है, वहां फूड पॉइजनिंग की वजह से दो लोगों की मौत हो गयी और 10 अस्पताल में भर्ती हैं। मेरा चिकित्सा मंत्री से आग्रह है कि वे थोड़ा दिखवाकर एक विशेष टीम भेजकर पानी के सैम्पल लेकर जांच करवाएं।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

अनुदान की मांगों पर चर्चा के लिए निर्धारित समयावधि में

कटौती प्रस्तावों की प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों को एक जानकारी देनी है कि परसों से डिमांड्स पर चर्चा होगी। कई नये सदस्यों को पता नहीं है कि जिन्हें भी उस दिन बोलना है या कट मोशंस देने हैं, वे 48 घण्टे पहले नीचे में अपने कट मोशंस दे दें, वरना उस दिन कहेंगे कि हमें बोलने की अनुमति दें। यदि सूची में नाम नहीं होगा तो वे नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि नये लोग इसे सुनिश्चित कर लें।

सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12:46 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

mkd/rtm/16.07.2024/14:00/2c

(समय: 14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 अग्रतेर सामान्य वाद-विवाद। श्री रफीक खान।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर सामान्य विवाद

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): महोदय आपने बजट 2024-25 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा है और सत्ता पक्ष के लोगों को, आप देखें एक भी मंत्री सदन में मौजूद नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विपक्ष के भी सदस्य कम हैं, ये भी कम हैं। अभी आ रहे हैं, कितने मंत्री हैं, दिखा दूं। आपका टाइम लिमिटेड है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप आये बहार आई। आइये, देर आये, दुरुस्त आये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि बजट इतना शानदार है। इनके पास विरोध करने के लिए कोई सामान नहीं है। इसलिए बार-बार मंत्री नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं हैं, ये बात कर रहे हैं। ये फालतू में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दों पर आओ। यदि हिम्मत है तो बजट पर आलोचना करके बताओ।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): **सूरज के खुदाओं की ये कोर निगाही है,**
महलों में उजाला है, कुटिया में सियाही है,
महसूस ये होता है, ये दौर-ए-तबाही है,
शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है।

आप सबने बजट दिया। मैं दो दिन से देख रहा हूं कि किस तरह बजट के नाम पर...। आपने अच्छा तो कहा, आपको समझ तो आया, शुक्र है। अब आप बैठ जाओ, मैं बहुत मतलब की बात बता रहा हूं, थोड़ी देर सुन लो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं खुद शायर हूं और मेरी किताब आ चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मुझे समझा रहे हो?

श्री अध्यक्ष: माननीय सचेतक जी, आप बोलने दीजिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): असंवैधानिक बजट बिना गवर्नर की स्पीच के, हमने आसन के कहने पर माना, लेकिन सच्चाई यह है कि यह अनकांस्टीट्यूशनल बजट है। बजट में इंकाम्पीटेंट मंत्री, यह पता नहीं किस मद में कितना पैसा आयेगा, कहां से आयेगा। जेब में पैसा नहीं है। मंत्री डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में जाकर मीटिंग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री मीटिंग कर रहे हैं। आपने बजट दिया नहीं है, बजट अप्रूव नहीं हुआ है। उससे पहले..।

श्री अध्यक्ष: बजट कभी भी असंवैधानिक नहीं होता है, रखने का ढंग हो सकता है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बजट के इम्प्लीमेंटेशन पर चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब तक आप बजट पास नहीं करोगे, उसके बगैर ही आप जाकर कलेक्ट्रेट में मीटिंग कर रहे हो। भाई, बजट तो पास करवाओ। जेब में पैसा तो लाओ, उसके बाद खर्च करने की बात करना। ये जो आसन के ऊपर बैठे हैं, यहां से जब बजट अप्रूव हो जाये, तब मीटिंग करना। यह अनकांस्टीट्यूशनल काम मत करो। आपको संविधान की रक्षा करना नहीं आता है।

फिर भी, हमारे जयपुर की विधायक, जयपुर की प्रिंसेज ने यह बजट दिया। पहली महिला उप मुख्य मंत्री ने बजट पेश किया, मैं आपको बधाई देता हूं। दिया कुमारी जी को भी बधाई देता हूं। आप सबको भी बधाई देता हूं। पहला बजट महिला उप मुख्य मंत्री ने यहां प्रस्तुत किया है। हमारे मन में उनके लिए जगह है। हमारे पूर्व सांसद प्रत्याशी, जो जयपुर से लड़े, जिनको इन्दिरा गांधी ने महावीर चक्र दिया, जिनको राजीव गांधी ने ब्रिगेडियर की उपाधि दी। उनकी पुत्री हैं। इसलिए, हमारे मन में उनके लिए जगह है। उनकी पुत्री ने यह बजट पेश किया। इन्दिरा गांधी के मार्गदर्शन में 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान के अन्दर जाकर गांव पर कब्जा किया। ऐसे महावीर को जब हमने जयपुर से लड़ाया तब आप सब उनके खिलाफ हो गये। उनकी पुत्री ने यहां बजट दिया। मैं आपको बधाई देता हूं और मुबारकबाद देता हूं।

आपने 10 संकल्पों पर आधारित बजट दिया। इतनी जल्दी बेचैन नहीं हों। अभी तो मैंने शुरू किया है। भवानी सिंह जी, वो शख्सियत थे, जिनको ब्रिगेडियर की उपाधि तो मिली ही मिली और कभी बीजेपी के दरवाजे पर झांककर नहीं देखा। आप क्यों उठ-उठकर जोर-जोर से बातें कर रहे हो।

यह 400 बिन्दुओं का बजट, जिसमें आपने कह दिया कि हमने 400 बिन्दुओं के बजट पर 43 बिन्दु पर काम कर लिया। 53 परसेंट, 400 बिन्दुओं पर 53 परसेंट कैसे पूरा हो गया? कौन-सी गणित पढ़कर आये हो? जैसे साढ़े तीन सौ बिलियन डॉलर की इकॉनोमी बनाने जा रहे हो, वैसी ही पढ़ाई करके आये हो क्या? मुझे यह बता दें कि एक बिलियन में कितनी बिंदियां होती हैं, जब जवाब दें, तब यह बता दें कि एक बिलियन में कितनी बिंदियां होती है और डॉलर में..।

श्री अध्यक्ष: नहीं तो, आप बात दें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं तो बता दूंगा, 9 बिंदियां होती हैं और 100 करोड़ रुपये होते हैं। मैं यह पूछूंगा आपने डॉलर में दिया तो डॉलर का हिसाब भी दे दो। आप कह रहे हैं कि हम 2047 में कर लेंगे, साढ़े तीन सौ बिलियन का। डॉलर ही ऊपर पहुंच जायेगा, डॉलर का पीछा करते-करते खत्म हो जाओगे। इंडियन रूपीज को सशक्त करने वाले लोग आज डॉलर को मजबूती देने की बात सदन में कर रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

एक बात और बात दूं। आप पर भी आऊंगा, थोड़ा सुनने का मादा रखो। आपने कहा कि हमने साढ़े चार सौ रुपये में सिलेंडर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। हमने 500 में सिलेंडर दिया। हिन्दुस्तान में कितने राज्यों में आपका राज है? कितने राज्यों में आपका शासन है? और कितने राज्यों में आपने साढ़े चार सौ रुपये में दे दिया? यह आप सदन को बता दें।

राजस्थान के अन्दर कर रहे हो, क्योंकि हमने कर दिया, मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर साढ़े चार सौ रुपये में सिलेंडर कर दिया। इसलिए, यह बात आप सदन में कहना

चाहते हो। इससे आपका कोई लेना-देना नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी में बुजुर्ग बहुत हैं, ये बहुत-बहुत जोर-जोर से बोल रहे हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): कोई बात नहीं, आप चिन्ता नहीं करें। सारे के सारे कह रहे हैं, बजट का कीर्तिमान। सभापति महोदय, मैं आपको बताता हूं क्या कीर्तिमान है। यह आज तक का सबसे बड़ा घाटे का कीर्तिमान है। 70 हजार करोड़ रुपये के घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। आज तक राजस्थान के इतिहास में इतने बड़े घाटे का बजट किसी ने प्रस्तुत नहीं किया है। यह जो आप बातें कर रहे हो, इस इकॉनोमी को छूएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप घाटे में छूओगे। जिस 70 हजार करोड़ के घाटे से शुरुआत कर रहे हो, पांच साल बीतते-बीतते कहां लेकर जाओगे, आप भी यहीं होंगे, हम भी यहीं होंगे, आपको बता देंगे। आप कितना घाटा लेकर जा रहे हो, घाटे में कीर्तिमान कर रहे हो। आप यहां 70 हजार करोड़ रुपये का घाटा दे रहे हो।

मैं एक बात और बता दूं। अभी जयपुर शहर में लू से आदमी मर गये। ये मेरे सिविल लाइन के साथी, इनकी कांस्टीट्यूएसी के आदमी मर गये। इनकी आवाज नहीं उठी। गर्मी से, लू से मर गये, एसएमएस में कितनी डेड बॉडीज आईं, कितनी लाशें लाईं, खाली बात कर सकते हैं। आम आदमी की बात, गरीब आदमी की बात नहीं है।

श्री सभापति: विराजें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सुना तो सही। अभी तो मैं शुरू हुआ हूं, रुको तो सही। यह कैसा सर्वजन हिताय है? ये 10 बिन्दुओं पर बात कर रहे हैं। 10 रिजोल्यूशन लायेंगे। यदि बजट की किताब बन्द करके इनसे 10 रिजोल्यूशन पूछेंगे तो एक आदमी नहीं बता पायेगा। कौन से विदेशी बजट की 10 लाइनें टीपकर अधिकारियों ने इसमें लिख दी, इनको पता नहीं है कि कौन से 10 रिजोल्यूशन हैं।

10 रिजोल्यूशन के अन्दर गरीब आदमी का जिक्र नहीं है, कच्ची बस्ती का जिक्र नहीं है, थड़ी ठेले वाले का जिक्र नहीं है। रिजोल्यूशन लाओ, रिजोल्यूशन पर काम तो करो। आप संकल्प लाने की बात कर रहे हो। हम 10 संकल्प लेकर आ रहे हैं। ये 10 संकल्प क्या-क्या है? आप 10 संकल्पों पर आधारित बजट देने जा रहे हो। आप कह रहे हो कि हम राजस्थान को नई दिशा देने आये हैं। पहला संकल्प है कि हम डॉलर 350 बिलियन की इकॉनोमी बनाने जा रहे हैं, कहां से बनाओगे? जब 70-70 हजार करोड़ के घाटे का बजट लेकर आओगे तो 2047 तक तो राजस्थान की इकॉनोमी की हवा निकल जायेगी।

Bhs/Rtm/16.7.24/14.10/2d

अब नाम देखो आप इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात पूर्ण करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आधा टाइम तो इन्होंने मेरा वैसे ही

खराब कर दिया।

श्री सभापतिः समय आपके द्वारा ही दिया हुआ है। आपके दल ने दस मिनट दिया है। आप अपनी बात कहें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): हमारी सरकार थी, इसमें क्या अभाव दिया इन्होंने बजट में कच्ची बस्ती का कहीं नाम नहीं है, स्ट्रीट वेंडर का कहीं नाम नहीं है, झोंपड़-पट्टी में रहने वालों का कहीं नाम नहीं है, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा वालों का कहीं नाम नहीं है, चौखटी पर दिहाड़ी करने वालों का कहीं नाम नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा बजट था, हमारे बजट की चन्द बातें पढ़ना चाहता हूं। चिरंजीवी योजना ...।

श्री सभापतिः विराजें, माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक मिनट में खत्म कर रहा हूं, सभापति महोदय। पच्चीस लाख रुपये तक की बीमारी का इलाज फ्री करते थे और इंश्योरेंस कंपनी देती थी आपकी जेब से कुछ नहीं जाता था। दस लाख रुपये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता था। सौ यूनिट फ्री आप सबको, आपको सबको सौ यूनिट फ्री आज तक मिलती है और आपने एक भी बात नहीं की इसके ऊपर और ओपीएस के बारे में बिलकुल नकार गये। ओपीएस की कोई बात नहीं। सामाजिक सुरक्षा पहले ढाई सौ रुपये मिलती थी, हमने पांच सौ रुपये दी, फिर हजार रुपये दी और फिर कानून बनाया हमने और कानून बना कर यह तय किया कि हम पूरे प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के नाम पर हर साल पन्द्रह प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगे।

श्री सभापतिः विराजो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, मैं पहला वक्ता हूं। एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।

श्री सभापतिः आज सदन के नेता अपना वक्तव्य देंगे और प्रतिपक्ष के नेता भी बोलेंगे।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक मिनट में खत्म करूंगा। हमारी दस उपलब्धियां भी हैं। इन्दिरा रसोई और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिनको आपके मंत्री बन्द कर देना चाहते हैं। कॉलेजेज, पांच सौ रुपये में सिलेंडर, राजीव गांधी स्कोलरशिप योजना और हर डिस्ट्रिक्ट में होस्पिटल, शहरी रोजगार गारंटी, फ्री राशन किट और किसानों को दो हजार यूनिट बिजली फ्री। आपसे मैं दावा करता हूं कि पांच चीजें गिना दो ऐसी।

श्री सभापतिः विराजिये माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। माननीय श्री बाबू सिंह जी राठौड़।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। यह बजट सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय है। पिछली कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान को गर्त में डुबो दिया और कर्जा तो विरासत में देकर गये। इसलिये मैं कहना चाहूंगा,

'कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें,

लहर-लहर तूफान मिले और मौज-मौज मंझधार हमें।
फिर भी दिखाया है हमने और फिर यह दिखा देंगे सबको,
इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें।'

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपने सुना ही नहीं। रफीक साहब, आपने सुना ही नहीं आपके काम की बात आई थी आपने सुनी नहीं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आपके शेर का जवाब दिया था। सभापति महोदय, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। आजादी के 77 साल बाद भी आज भी गांवों में पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से ग्रामीण इलाके वंचित हैं। पिछली कांग्रेस सरकार ने आनन-फानन में आओ और पाओ खूब सारी घोषणाओं का अम्बार लगाया और उन घोषणाओं में किसी ने कहा कि आप मेरे तहसील कर दोगे तो चुनाव जीत जाऊंगा। किसी विधायक ने बोला कि जिला कर दो तो जीत जाऊंगा। मेरे पीएचसी कर दो, सीएचसी कर दो। बजटीय प्रावधान था नहीं, वित्तीय प्रावधान था नहीं, मानव संसाधन थे नहीं, पदों का सृजन था नहीं। आओ और एक लेटर बनवा कर ले जाओ और इलाके में बता दो।

एक बार मेरे तेना गांव में सीएचसी की मांग की गांव के लोगों ने तो वहां के एमएलए साहब ने कहा कि ऐसा अस्पताल बनाएंगे कि सड़क के बाहर खड़े होकर अस्पताल को देखोगे तो मरीज ठीक हो जाएगा। ऐसे अस्पताल बनाये। ...(व्यवधान)... हां, ऐसा ही बना हुआ है वहां पर। आपका कोई बीमार हो तो भेज देना तो सभापति महोदय, जिले बनाये, तहसील बनाई, उप तहसील बनाई, पीएचसी बनाई, सीएचसी बनाई लेकिन मेरा यह कहना है कि घोषणाएं चाहे ये सरकार करे चाहे हमारी सरकार करे लेकिन वहां पर जनता को राहत मिलनी चाहिये। अब जो जिले बनाये हैं राजनीतिक लाभ के लिए जहां राजनीतिक लाभ होता है वहां जनता समझती है और चुनाव के समय में कोई घोषणा करे तो लोगों को लगता है कि हमें प्रलोभन देने के लिए लोक लुभावनी घोषणा है लेकिन जब पहले वर्ष में घोषणा की जाती है तो वह सरकार का दर्पण होता है और पांच साल का वीजन होता है यह सरकार पांच साल में जनता के भरोसे और विश्वास पर खरी उतरेगी और यह बजट 'सर्वजन हिताय है, सर्वजन सुखाय' है और जिस प्रकार का बजट आया है सभी वर्गों का समावेश है, सभी क्षेत्रों का समावेश है और सब जगह भूरि-भूमि प्रशंसा इसकी हो रही है। ...(व्यवधान)... जिलों में जीते, दूसरी घोषणाओं में जीते।

सभापति महोदय, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जैसे पीएचसी अस्पताल बनाया तो वहां न तो डॉक्टर है न स्टाफ है जो पहले हमारे पीएचसी थे उसमें से डेपुटेशन कर दिया वो भी नहीं आ रहे हैं आज वो सारे अस्पताल बन्द पड़े हैं तो जनता को इसका क्या लाभ मिला। आज हमारे जो बजट आया है इस बजट में आदरणीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा है चार लाख नयी भर्तियां करेंगे, 12 लाख युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार देंगे और इस बार भर्तियां बढ़ा कर इस साल में एक लाख भर्तियां करेंगे जिससे पदों का सृजन होगा और ये जो

घोषणाएं होंगी उन घोषणाओं में सब जगह इस प्रकार के मानव संसाधन स्थापित होंगे।

सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं कि गांवों में जैसे सबसे बड़ी कोई समस्या थी पिछले पांच सालों में तो पानी और बिजली को लेकर समस्या आयी और पेयजल के लिए हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता और यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने यह घोषणा की थी कि 2024 तक प्रत्येक घर में नल लगेगा, नल से जल आयेगा, जल जीवन मिशन की शुरूआत की। शुरूआत तो की लेकिन कांग्रेस राज में आनन-फानन में योजनाएं बनाई गई। गांव में विलेज प्लान बनाया, ओटीएमपी की स्कीम बनाई, सतही जल की योजना नहीं बनाई। अब उस ओटीएमपी स्कीम के अन्दर प्रत्येक ढाणी जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में ढाणियां दूर-दूर है, एक ढाणी को जोड़ने के लिए पैंतीस हजार का बजट लिया। अब जितने हाउस होल्ड थे, ढाणियां थी पैंतीस हजार के हिसाब से वहां गांव का बजट निर्धारित कर दिया। अब उस बजट में उच्च जलाशय बन गया, पम्पिंग स्टेशन बन गया, चारदीवारी बन गई और जैसे ही बजट कम पड़ तो जो पाइपलाइन का बजट था वह 70 प्रतिशत बजट कम कर दिया। पाइपलाइन के लिए 30 प्रतिशत बजट बचा अब 30 प्रतिशत जब बजट बचा तो हमारी 70 प्रतिशत ढाणियां पेयजल से जुड़ने से वंचित रही और सतही जल की योजना थी नहीं इसलिये आज मैं कह सकता हूं कि अभी हमारे भजन लाल जी सरकार ने घोषणा की है कि पन्द्रह हजार करोड़ का व्यय करके पच्चीस लाख घरों में नल से जल पहुंचाया जायेगा।

सभापति महोदय, वास्तव में यह बात सही है कि हम प्रत्येक घर में पानी पहुंचायें यह हमारी सरकारों की जिम्मेदारी है और जनता का अधिकार है ह्युमन राइट, तो इसमें विस्तृत सर्वे होना चाहिये और डीपीआर बननी चाहिये प्रत्येक घर में पानी कैसे जाये तो मेरी सरकार से मांग है कि सभी विधान सभा क्षेत्रों में जो ढाणियां वंचित रह गई, घर वंचित रह गए उन सबका विस्तृत सर्वे होना चाहिये, डीपीआर तैयार होनी चाहिये। डीपीआर के आधार पर स्वीकृतियां निकल करके जो हमारे मोदी साहब ने दो साल का समय बढ़ाया उन दो सालों में प्रत्येक घर में पानी पहुंचे क्योंकि सरकार को 27 हजार करोड़ रुपये मिले और 27 हजार करोड़ में ऐसी स्थिति कर दी कि जहां पर कार्यादेश हुआ था और जहां पेयजल का काम होना था उस जगह पर मैटेरियल पहुंचा नहीं और 80 प्रतिशत पैसा पहले उठा लिया। अब धन का दुरुपयोग हुआ और जल जीवन मिशन के अन्दर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। अब यह तो धर्म का काम है। अब धर्म के काम में भ्रष्टाचार हो तो यदि बाड़ ही खेत को खाये, रक्षक ही भक्षक बन जायेगा तो पीछे क्या रहेगा। यह पानी की भयंकर समस्या थी। आज मैं कह सकता हूं कि पानी में भी आप भेदभाव कर रहे हो।

सभापति महोदय, पहले जनता जल योजना ग्राम पंचायत देखा करती थी। पिछली सरकार में पीएचईडी विभाग को हस्तांतरण हुई जब वो जनता जल योजनाएं पीएचईडी का हस्तांतरण हुई तो उसमें भी जहां पर जो नलकूप का संचालन कर रहा था, संधारण कर रहा था और पता किया कि यह बीजेपी को वोट देता है बीजेपी का है इसलिये ऐसे हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी दो सौ नलकूपों पर बीजेपी का ठप्पा लगा करके इस जनता जल योजना को पीएचईडी

में ट्रांसफर करने से रोका। आज वो सेवाएं दे रहे हैं, ट्यूबवैल चला रहे हैं लेकिन उनको मानदेय नहीं मिल रहा है।

मैं सरकार से मांग करूंगा कि जहां-जहां भी इस प्रकार का राजनीतिक भेदभाव हुआ है उन जनता जल योजनाओं को अनुमति देनी चाहिये और जितने भी जनता जल योजनाओं में संचालन/संधारण कर रहे हैं, मानदेय पर लगे हैं उनका भी मानदेय बढ़ाया जाना चाहिये।

Kas/rtm/16.07.2024/14.20/2e

मेरे यहां ऐसे कई प्रकरण आये कि बड़ी-बड़ी मेन राइजिंग लाइनें चल रही हैं, राइजिंग लाइनों पर बड़े कनेक्शन लिये गये, टांके भरे गये और टांके भरने के बाद जिनके हक का पानी जाता था, उसको रोक कर उन्हीं को टेंकर से बेचा गया। लोगों को 1500 रुपये देकर टेंकर से पानी डलवाने के लिये मजबूर होना पडा। जब हमने शिकायतें की तो वहां के नेताओं ने कहा कि हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता आज पैसा नहीं कमायेगा तो कब कमायेगा? पेयजल को भी आपने कमाई का जरिया बना लिया, यह ठीक बात नहीं थी। आपने कभी कोई अभियान चलाया नहीं। जलदाय विभाग में किसी प्रकार की सामग्री मिली नहीं। हैंड पम्प मरम्मत अभियान चलाया नहीं। आर.ओ. प्लांट जो आदरणीय वसुंधरा जी के समय गांव-गांव में लगे थे, वह सारे बंद पड़े हैं, उसका कोई ओ.एण्ड एम. किया नहीं, वापस उनको चालू किया नहीं और पेयजल की भयंकर समस्या देखने को मिली। मैं आज हमारी भजन लाल सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ई.आर.सी.पी. योजना लागू की है। हम भी मांग करेंगे कि सबसे ज्यादा पानी की समस्या पश्चिमी राजस्थान में है और पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़ के लिये डब्ल्यू.आर.सी.पी की योजना स्वीकृत होनी चाहिये, जिससे वहां पर पेयजल संकट का समाधान होगा और उनको सिंचाई के लिये भी पानी मिलेगा। इसके लिये भी हमारी भजन लाल सरकार में 20370 करोड़ की लागत की 6 परियोजनाओं को पूरा किया जायेगा। अमृत 2.0 योजना में भी कार्य होगा। नवीन नलकूप और हैंडपम्प अगले दो साल में लगाये जायेंगे। पानी की समस्या का समाधान हमारी सरकार की प्राथमिकता है, जो यह सरकार करेगी।

दूसरी समस्या हमारे यहां विद्युत की रही। मेरा मानना है कि चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हम क्यों मांग करें। सरकार की जिम्मेदारी है कि पानी के जितने सोर्स हैं, उनका सरकार सर्वे करे और उस समस्या का समाधान करे। वैसे ही बिजली में जब आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार थी, तो उन्होंने एक नियम बना रखा था कि कभी ट्रांसफार्मर जलेगा तो 72 घंटे में बदला जायेगा, नहीं तो कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। जब से कांग्रेस सरकार आई है, जब भी ट्रांसफार्मर जले तो स्टेंड बाई ट्रांसफार्मर नहीं मिलते थे, सामान नहीं मिलता था। महीने भर ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था, इस प्रकार की स्थिति थी। ...(व्यवधान)... आप विराजो, मैं तो कभी बोला ही नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कभी इन्होंने विद्युत भार का सर्वे तक नहीं किया कि

400 के.वी. का जी.एस.एस. चल रहा है, कितना भार हो गया। हमारा जोधपुर आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब का गृह जिला था, मुख्य मंत्री थे, लेकिन दो ही 400 के.वी. के जी.एस.एस. काकाणी और सूरपुरा में थे। जोधपुर का इतना लोड बढ़ा कि दोनों में फॉल्ट आया, दोनों जले और हमारे बालेसर में भी इतना विद्युत भार था कि 132 में फॉल्ट आ गया। लोगों को 15-20 दिन तक बिजली नहीं मिली। मारवाड़ी में कहते हैं कि कोठे में आई तो खेली में आई। कोठे में आयेगा तभी खेली में आयेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा यह सारे जी.एस.एस. सर्वे हो। 400 का है तो उसको 700 किया जाये। जहां 220 का है, उसको 400 किया जाये। जो 132 का है, उसको 220 किया जाये। मैं कहना चाहूंगा कि जितने घरेलू ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, कनेक्शन देते गये, नया ट्रांसफार्मर दिया नहीं, विद्युत भार बढ़ गया, जिससे घरेलू ट्रांसफार्मर जलने लगे। आदरणीय वसुंधरा जी ने एफ.आर.डी., फीडर रिन्युअल प्रोग्राम चलाया था, जिसमें 11 के.वी. लाइनें दुरुस्त की थीं, नये ट्रांसफार्मर लगाये थे, एक-एक ट्रांसफार्मर का सर्वे किया था। केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र में 800 ट्रांसफार्मर सिंगल फेज के लगे थे। मैं आज खास तौर से कहना चाहूंगा कि हमारी भजन लाल सरकार ने आगामी 10 वर्षों की कार्य योजना में विद्युत मांग का 6 प्रतिशत बढ़ोतरी दर के अनुसार ऊर्जा उत्पादन की कार्य योजना तैयार की है। पिछले पांच सालों में जिन उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन लेने थे, उनको घरेलू कनेक्शन दिये नहीं। हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' बनाकर 500 रुपये डिमांड लिये, चाहे 100 पोल लगे, लेकिन उसका घर का कनेक्शन हुआ। पिछले पांच साल में आपने 4000 डिमांड लिये, केबल आप दोगे नहीं, पोल आप दोगे नहीं और केबल से कनेक्शन होगा, लोगों के कनेक्शन हुए नहीं। आज मैं भजन लाल सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने बजट में घोषणा की है कि दो लाख घरेलू कनेक्शन दिये जायेंगे। किसानों के लिये भी आपने लास्ट बजट में घोषणा कर दी कि हम किसानों को कृषि कनेक्शन देंगे। कृषि कनेक्शन की घोषणा तो कर दी, लेकिन सामान का टेंडर करना ही भूल गये। अब हमारी सरकार आई तो पता किया तो कहा कि टेंडर ही नहीं है। ट्रांसफार्मर आ रहा नहीं, सामान आ रहा नहीं, उनके कनेक्शन हो रहे नहीं। समय पर ट्रांसफार्मर आये, किसानों को कृषि कनेक्शन मिले, हमारी भजन लाल सरकार ने घोषणा की है कि हम इस प्रकार से कृषि कनेक्शन देंगे।

हमारी भजन लाल सरकार ने पहली बार घोषणा की है कि 700 के.वी. के 6 जी.एस.एस. बनाये जायेंगे। आपने कितने बनाये, आप अपने जवाब में जरूर बताएं। 400 के.वी. के 7, 200 के.वी. के 15, 132 के.वी. के 40, 33/11 के.वी. के 240 जी.एस.एस. बनाये जायेंगे। हमारी केन्द्र सरकार की ग्रामीण पुनरुद्धार योजना है, आर.डी.एस.एस., इस योजना में जो केबल के कनेक्शन लगे थे, धूप लगने से वह केबलें खराब हो गईं। केबलें जल रही थीं, शॉर्ट हो रही थीं, इनके समय कोई केबल विभाग में बदली नहीं गई। ...(व्यवधान)... हमारा समय है। मैं कहना चाहूंगा कि अब आर.डी.एस.एस. में 33 के.वी. जी.एस.एस. बनेंगे, केबलें बदली जायेंगी, 33/11 के.वी. की लाइनें होंगी, साथ ही जहां-जहां घरेलू कनेक्शन लगे हैं, उनके

ट्रांसफार्मर भी इसमें बदले जायेंगे। मैं कहना चाहूंगा-

मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है,

फन से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।

इसलिए चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, यह पहला काम है जो गांव के लोगों की मांग है और मुझे विश्वास है कि यह काम भी होगा।

आप सब जानते हैं कि विकास सड़कों से होकर गुजरता है। पहली बार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के माध्यम से गांवों को जोड़ने का काम किया था। आपको याद होगा कि पूरे हिन्दुस्तान में आदरणीय वसुंधरा जी के राज में 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' में राजस्थान प्रथम नंबर पर था। यही नहीं, जब पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी ...(व्यवधान)... उस समय सरकार वसुंधरा जी की थी, जिसकी बात मैं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः बैठिए आप।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आप बोले जब मैंने आपको टोका नहीं, इसलिए आप मेहरबानी करो।

श्री सभापतिः आप बैठिए, उम्र का तो लिहाज करो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): गत कांग्रेस की सरकार में यह सड़कों का नवीनीकरण करना भूल गये। मैं पिछली सरकार को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इन्होंने 250 तक की जनसंख्या के गांवों को जोड़ने की घोषणा की कि 2011 में 250 तक की जनसंख्या के गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। यह तो आपकी सराहनीय घोषणा थी, लेकिन जब भी आप कोई काम करते हो तो उसमें राजनीतिक द्वेष भावना और भेदभाव जरूर करते हो। जब यह सड़कों की घोषणा हुई तो उसमें तय किया गया कि यह पूरा राजस्व गांव भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, इसलिए उन गांवों को सड़कों से जोड़ने से वंचित रखा। आज मैं कह सकता हूं कि 250 की जनसंख्या वाले गांवों में मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने भेदभाव करते हुए 114 गांवों को सड़कों से वंचित रखा। ऐसे गांव जहां पर 8 किलोमीटर बननी थी, वहां एक किलोमीटर बनाई। ऐसे 444 किलोमीटर कम लंबाई की सड़कें दीं, जिससे राजस्व गांवों को लाभ नहीं मिला। अब सभी जगह सड़कों का काम होगा। सड़कों की खस्ता हालत हो गई है। आप नई सड़कें बनाना चाहते थे, क्योंकि आपको वोट का लाभ मिले, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि सड़कों की खस्ता हालत है। सड़कों की स्थिति यह हो गई कि अब डब्ल्यू.बी.एम. बचा है, न तो डामर बचा है, सड़क खड्डों में है या खड्डे सड़कों में हैं, ऐसी हालत हो गई। वसुंधरा जी की सरकार में और अब भजन लाल जी की सरकार में चरणबद्ध तरीके से, सीनियरिटी से वर्षवार सड़कों का नवीनीकरण होना चाहिये और वह होगा। इसके लिये शानदार बजट सड़कों में दिया है। अब हमारी भजन लाल सरकार पांच वर्षों में 53 हजार किलोमीटर सड़कों में 60 हजार करोड़ रुपये व्यय करेगी। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि हमारी मांग है कि जो भी राजस्व गांव सड़कों से जुड़ने से वंचित रह गये हैं, अब

उन सबको ले लो, जिससे किसी के साथ राजनीतिक भेदभाव न हो। सबका साथ, सबका विकास, सर्वजन हिताय काम होना चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन है कि लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और भार वहां बढ़ रहा है। चिकित्सा का भार भी बढ़ रहा है। जिला मुख्यालय पर, जैसे हमारे यहां एम्स है और बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, वहां बहुत भार है। वहां पर बेड तक नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि चिकित्सा की सुविधा गांवों में बढ़ाई जाये। इसके लिये एक नियम और नीति बना दें कि प्रत्येक पंचायत में उप स्वास्थ्य केन्द्र होगा। चार पंचायतों में एक पी.एच.सी. होगी। इस समूह के आधार पर सी.एच.सी. होगी।

msk/rtm/16.07.2024/1430/2f

उसमें सारी सुविधाएं हों, डॉक्टर हो, स्टॉफ हो, तब जाकर वहां इलाज हो। तो मैं यह चाहूंगा कि अब हमारी भजन लाल सरकार 27660 करोड़ रुपये का प्रावधान कर चिकित्सा क्षेत्र में आमूलचल परिवर्तन करने वाली है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात पूर्ण कर लें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): बस दो मिनट। मेरी सरकार से मांग है कि हमारे यहां भी उप स्वास्थ्य केन्द्र को पीएचसी में, कनोडिया पुरोहितान, बैरवा खतरिया, उटाम्बर, सोलकियातला, रायसर, भूंगरा, खेजा तेबड़ा, सुआड़िया, बसवा, सूण्डा, भोटलई पुरोहितान, लोटता, असलावता, बावली ठाडिया, बाड़ूराजवा, दासाणियां को पीएचसी में बदले। मेरा दूसरा निवेदन यह था कि आदरणीय वसुन्धरा जी के राज में राजस्थान को शिक्षा में एक नया मॉडल बनाया गया था, जिसकी प्रशंसा पूरे हिन्दुस्तान में ही हुई थी। वहां पर समय पर डीपीसी हुई, सीनियर प्रणाली लागू की गई। प्रत्येक पंचायत में, पहले माध्यमिक हुई और उसके बाद प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक हुई, लेकिन आपके राज में तो जब शिक्षक सम्मेलन हुआ तो आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने पूछा, शिक्षा मंत्री साथ में बैठे थे। कि क्या शिक्षकों को स्थानान्तरण के पैसा देना पड़ता है तो सारे शिक्षक खड़े हुए और कहा कि पैसा देना पड़ता है। वास्तव में यह सही बात है।

कांग्रेस का राज आया और राज आने के बाद में जो सारे शिक्षक थे, विद्यालयों में बढ़िया पढ़ाई चल रही थी। वहां नामांकन बढ़ा था, आपका राज और कांग्रेस सरकार को नारियल चढ़ाया और सारे शिक्षकों के पद रिक्त हो गये। आज वहां स्थितियां खराब है। आपने वहां अंग्रेजी माध्यम की। करना चाहिए, लेकिन पहले जो हमारे प्राइमरी विद्यालय मर्ज हुए, आप वहां खोल देते। हिन्दी माध्यम की बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही थी, जहां सात-आठ सौ का नामांकन था, वहां हालात खराब हो गये। अब वहां आप छठी से अंग्रेजी शिक्षा दे रहे हैं। आपको कोई मॉडल तो बनाना चाहिए कि इसमें हमारे अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक आयेंगे, वे करेंगे। तो यह हालत की है। राजकीय महाविद्यालय तो संविदा के माध्यम से चल रहे हैं। एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। आपने ये हालात किये हैं। अब आमूल-चूल परिवर्तन

होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ईडब्ल्यूएस, निकाय में पंचायती राज का आरक्षण होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि अब समस्याओं का समाधान होगा।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मेरी एक मांग है कि गायों का अनुदान 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करना चाहिए। विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा विकास होगा कि जो लोग गांव छोड़कर गये हैं, वे वापस शहर छोड़कर गांव आयेंगे।

नजर को बदल तो नजारे बदल जाते हैं,
सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं,
कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं,
दिशाओं को बदलो, तो किनारे खुद-ब-खुद बदल जाते हैं।

सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सभापति महोदय, आज पर 2024-25 पर ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरे गरु हैं, मेरे गरु का निवेदन करना, मेरा फर्ज है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): गुरू या गरु है?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): वह हम दोनों का मामला, तीसरा बीच में नहीं।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): गरु हटवाओ।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सभापति महोदय, 2024-25 के राजस्थान के बजट पर विचार के लिए हम यहां पर बैठे हैं। आप और हम, पक्ष और विपक्ष के दोनों ही विधायकों का यह दायित्व है कि राजस्थान का विकास कैसे हो, हम कैसे आगे बढ़ें, इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है। मैं आपको यह भी बता दूं कि आप और हमारे बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहना चाहिए, क्योंकि इस सदन का इतिहास रहा है कि 1952 से लेकर आज तक 200 में 140 विधायक जीतकर नहीं आये। चाहे टिकट नहीं मिला, चाहे हार गये, चाहे चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जो एवरेज है, जब चार साल बाद चुनाव होंगे तो इन 200 में से 60 आदमी यहां पर उपस्थित होंगे तो आपसी सम्बन्ध कटुता का नहीं, प्रेम का बनाये रखें।

आजकल शेर-शायरी का दौर चल गया। रफीक साहब भी बोल गये और बाबूसिंह जी भी। आप ये नंबर कटवा रहे हैं, 20 बार वसुंधरा जी का नाम लिया है और भजन लाल जी का एक बार लिया है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हरिमोहन जी, आप बजट के बारे में मुझे जो बाहर कह रहे थे, वही बोलना।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): एक छोटा-सा है।

रिश्ता हो न हो, भावना होनी चाहिए,
मोहब्बत हो न हो, बात होनी चाहिए,

यूं तो उलझे हैं सभी, अपनी उलझनों में,
पर सुलझाने की कोशिश भी होनी चाहिए।

इस भावना से मैं अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा हूं। वर्तमान वित्त मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी को इस बात का सौभाग्य मिला कि बजट बनाने में जो तीन अधिकारी थे, वे वही थे, जिन्होंने माननीय अशोक गहलोत जी के वित्त मंत्री के काल में अपना बजट बनाने में सहयोग दिया था। जो अनुभव अशोक जी गहलोत का था, जो विजन अशोक जी गहलोत था, उस विजन के अनुसार ही इन्होंने उस समय का बजट बनाया था। आप तो इनको बदलना चाहते थे। यह तो मुख्य मंत्री जी का भला हो, जिन्होंने कहा कि अगर इन अधिकारियों को बदलेंगे तो बजट भी नहीं बन पायेगा। इसमें एक कमी रह गयी। अशोक जी गहलोत को तो जिन्दगी का अनुभव था। माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, माननीय वित्त मंत्री जी हैं, उप मुख्य मंत्री हैं, अगर इनको भी राजनीतिक अनुभव होता तो यह बजट और अधिक मजबूत एवं कारगर बनाया जा सकता था। खाली अधिकारियों के भरोसे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... अब आप सुन लें। आपका जन्म दिन था। मैंने तो सवेरे ही आपसे कह दिया कि जन्म दिन की एक ही उपलब्धि है। आप तो मुझे बोल लेना देना। गोपाल भाई से भी मैंने कह रखा है।

मेरा निवेदन यह है कि बजट में सबने अपने विचार रखे। पूर्ववर्ती सरकार, हारना एक अलग चीज है, योजनाएं चीज अलग है। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की जो योजना थी, चाहे वह चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, महंगाई राहत कैम्प हो, मुख्य मंत्री दुर्घटना बीमा हो, पशु दुर्घटना बीमा हो, बिजली फ्री योजना हो, इंदिरा रसोई योजना हो, उस योजना के बाद भी जो व्यापक जन समूह उभरकर आया। आप लोग उससे परेशान थे कि यह परिवर्तन क्या है? कितने आदमी आ रहे हैं। कितने कैम्पों में लाभान्वित हो रहे हैं? आपने भी अपने सोर्स से पता लगाया कि इन योजनाओं का असर क्या है? उस हालत में, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने तो 2030 में राजस्थान को इस देश में प्रथम बनाने का वादा किया था, कल्पना थी। आपने उसको अपने आप ही उम्र बढ़ाकर 2047 कर दिया। राजस्थान को 2030 में प्रथम बनाना था, आपने राजस्थान को 2047 में प्रथम बनाने का जो संकल्प लिया। आप मानकर चलिये कि वसुंधरा जी की सरकार में प्रति व्यक्ति आय 65 हजार 98 रुपये थी। कांग्रेस की सरकार के पांच सालों में 1 लाख 68 हजार रुपये प्रति व्यक्ति आय है, यह मैं आपके रिकॉर्ड के आधार पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। पक्षपात को तो आपने गजब कर दिया। राजस्व घाटे की बात, दूसरा घाटा। घाटे के मामले में सबने अपने-अपने विचार बोल दिये। सही है कि आपने घाटा और ज्यादा बताया है, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से शोभाजनक बात नहीं है। बून्दी विधान सभा क्षेत्र में, आपने जो अपनी पुस्तिका बांटी, उसमें तीन काम उपलब्ध होना बताया है। बताया है कि बून्दी, सिलोद, नमाना, गरबदा रोड। दूसरा बताया है कि बीजासन माता का रोप-वे। तीसरा बताया है, केशोरायपाटन मन्दिर का विकास। ये तीनों काम तो पहले ही हो गये। अभी आपके प्रभारी मंत्री जी बून्दी गये थे।

उन्होंने मुझे भी बुलाया था। उनके सामने ही अधिकारियों से जो चर्चा हुई, रोप-वे के लिए तो प्राइवेट कंपनी ने 29 लाख रुपये साल-डेढ़ साल पहले ही जमा करा दिये। यह कौनसी योजना है? यह भोपतपुरा जो सड़क है, नमाना, यह तो पूर्व में ही 234 करोड़ रुपये की स्वीकृत है। इसका तो फोरेस्ट विभाग में क्लीयरेंस के लिए पड़ा हुआ है। केशोरायपाटन का मन्दिर का जो 19 करोड़ का है, यह तो आप मेरे प्रश्न के जवाब में ही स्वीकार कर चुके कि यह तो केन्द्र सरकार का पैसा है, जो आ गया। आपने यह तीनों उपलब्धियों में लिख दिये, आप यह बतायें। कमाल की बात है। यह तो देखो, अगर अनुभव होता तो उन अधिकारियों के भरोसे उस कागज को नहीं छोड़ते, कुछ देखते कि कौनसी योजना है, इन्होंने कैसी-कैसी स्वीकृत की, यह मेरा आपसे निवेदन है।

mdp/rtm/16.07.2024/14:40/2g

एक बात आपने लिखी है कि 5 हजार करोड़ रुपये राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड के लिए। बहुत अच्छी कल्पना है आपकी। राजस्थान का विकास होना ही चाहिए, पर्यटन का विकास होना ही चाहिए। इस साल के लिए कौनसी योजना है? न कोई डीपीआर है, कितना पैसा खर्च करेंगे, कुछ नहीं। ये कल्पना है कि हम 5 हजार करोड़ का एक बोर्ड बनाएंगे, वह राजस्थान में टूरिस्ट डवलपमेंट का काम करेगा। यह तो कल्पना है। उपलब्धि बता रहे हैं आप। आप काम करने का बता रहे हैं। उसका डीपीआर ही नहीं बना, क्या काम करेंगे? अगर करना भी है तो आप देखते तो सही, इसके साथ ये तो जोड़ते कि 2024-25 में इस साल में हम कौन-कौनसा काम करेंगे, यह तो बताते और हवा बना दी 5 हजार करोड़ का हम फंड बनाएंगे। उसमें लिखा है हैरिटेज के लिए, हैरिटेज के लिए भी मैं आपको बता दूं, जो बढ़िया हैरिटेज हैं, वह तो निजी लोगों के पास हैं, राजा-महाराजाओं के पास। उनमें तो आप पैसा लगा नहीं सकते। फालतू के काम में पैसा बर्बाद करने के बजाय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से, पर्यटन मंत्री जी से, यह निवेदन करूंगा कि पहले जाकर स्वयं अपनी आंखों से देखें कि कौनसा हैरिटेज है। बावड़ियों के नाम पर, कुछ बावड़ियां तो ठीक हैं, ऐतिहासिक हैं। कुछ बावड़ियां ऐसी हैं जिनमें बिना काम ही करोड़ों रुपये लगाये जा रहे हैं, जिनका कोई उपयोग ही नहीं है। सारा पैसा बर्बाद जा रहा है। उसको जाकर देखें। पंचायती राज के क्या हालात है?

श्री सभापति: समाप्त करें, साहब।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): पांच मिनट, साहब।

श्री सभापति: दस मिनट का समय है आपका।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): बाबूसिंह जी को दिया है, थोड़ा मेरे साथ भी रिलेक्सेशन कीजिए। आप मंच पर विराजे हैं, कोटा के आदमी हैं, थोड़ा तो पक्षपात कीजिए।

श्री सभापति: श्री प्रताप पुरी जी। आज आपको भी मालूम है आपके प्रतिपक्ष के नेता रिप्लाई देंगे और सदन के नेता भी। आप विराजे।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): कोई बात नहीं। आराम से बोल लेंगे। 8 बजे के बजाय 9

बजे बढ़ा देना। पूरा तो करने दीजिए।

श्री सभापति: श्री प्रतापपुरी जी। ...(व्यवधान)... 12 मिनट दे दिये आपको।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): बोलने तो दीजिए।

श्री सभापति: आपके द्वारा ही लिखा हुआ है। बैठिए आप। विराजिए। जितना लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से समय दिया जा रहा है, यहां भी और वहां भी। इसमें किसी प्रकार का कुछ नहीं किया जा रहा है। प्लीज, आप वरिष्ठ हैं, सम्मान करता हूं। विराजिए आप।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): जय-जय श्री राम। बजट 2024-25 पर विगत तीन दिनों से सदन के सभी सम्मानित सदस्य अपने-अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी कड़ी में मुझे भी अपने विचार रखने का सुअवसर प्रदान किया है, मैं आसन का आभार प्रकट करता हूं। खुशहाल किसान, सुरक्षित समाज, सशक्त महिला, उत्कृष्ट शिक्षा, समर्थ युवा, आरोग्ययुक्त प्रदेश, कुशल प्रशासन, मजबूत कानून व्यवस्था, गौरवशाली विरासत, अद्वितीय पर्यटन, प्रबल अर्थव्यवस्था एवं उद्योग सुदृढ़, आधारभूत संरचना और सबका विकास-सबका विश्वास के कृत संकल्प होकर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य राजस्थान में प्रस्तुत उक्त बजट बहुत ही उत्तम एवं प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए विकासशील पथ अग्रसर करेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

मैं इस पवित्र वेदी सदन में विपक्ष में विराजे हुए माननीय सदस्यों को मेरी भावना उल्लेखित निम्न काव्य संदेश के माध्यम से करता हूं, चूंकि मेरे से पहले सभी ने शेरो-शायरी में बात की, मैं संत की भाषा में बात करूंगा।

अहंकार का भाव नहीं रखूं, न किसी पर क्रोध करूं।

देखूं दूसरों की बढ़ती को, कभी न किसी से ईर्ष्या भाव करूं।

मैं भी आपसे आशा रखता हूं कि इसी भाव से हम सब लोग -

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पथ पर चलकर राजस्थान के विकास में किसी भी प्रकार का कोई भी अहंकार न रखते हुए विकास पर ले जाने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

भारत देश की जनता ने तीसरी बार मोदी जी एवं एनडीए सरकार को अपना प्रतिनिधित्व स्वीकार करते हुए राजस्थान और भारत की सत्ता को हाथ में दिया है। इसलिए पूरे राजस्थान की जनता और भारत की जनता को मैं हृदय से साधुवाद करता हूं कि ये सुअवसर जनता की सेवा करना सर्वोपरि है, क्योंकि हमारा धर्म सेवा धर्म: परं गहनो योगिना मप्यगम्यं, सेवा करने का मौका मिला है, निश्चय ही एनडीए सरकार, राजस्थान में नहीं भारत में और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां की जनता की सेवा करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि विपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों की देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी एवं हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के बारे में अवधारणा आपकी अच्छी है और

अच्छी की ही मैं आशा रखता हूं। यही हमारा कर्तव्य बनता है और यही हमारा धर्म बनता है। नेता बनने के बाद वह हम सबका है और हम सबका प्रतिनिधित्व करता है। राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनका सम्मान देश का सम्मान है। मुख्य मंत्री जी का सम्मान पूरे राजस्थान का सम्मान है। इसी भावना से हम सब लोग उनका सम्मान करेंगे। आगे से ऐसा कोई भाव न हो जो किसी प्रकार से राजस्थान को या देश के प्रति, हमारे प्रति कोई भावना कुंठित हो।

यह भी सत्य है कि आप विपक्ष में विराजे हैं और हम लोग पक्ष में बैठे हैं। ये सत्ता परिवर्तन होता रहेगा। कभी विपक्ष और पक्ष, परंतु राज्य के विकास में हम सब को एकजुट होकर, अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने जो हमारे से बहुत वरिष्ठ हैं, जो सलाह दी, मुझे बहुत हृदयंगम हुई है कि यही भाव और यही कर्म करने के लिए हम सबको जनता ने चुनकर यहां भेजा है। केवल हम 200 जो बैठे हैं, इतनी ही नजर और दृष्टि हमारे पर नहीं है। पूरे प्रदेश और पूरे देश की एक-एक पल हमारे ऊपर नजर है। सब हमें देख रहे हैं कि जो हमारे प्रतिनिधि गये हैं, वह किस प्रकार से बातें करते हैं? क्या उनका व्यवहार होता है? कैसी योजना हमारे बारे में बनाई जाती है? इसलिए पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं, आइए राजस्थान के विकास की बात करे। राजस्थान को अग्रणी ले जाने में हम सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए विपक्ष में विराजे हुए आपकी भी वही भूमिका रहनी चाहिए जो विपक्ष की गरिमामय भूमिका है।

मैं इस बजट के बारे में करूंगा कि राजस्थान की सरकार ने बजट जो दिया है, वह अकल्पनीय है, अतुल्य है, प्रशंसनीय है और विजन के साथ है। यदि कोई इसमें वाद-विवाद के माध्यम से हमें बात रखनी है, आइए आपके सुझाव किस प्रकार से विकास से बात करनी है, उन पर विचार जरूर किया जायेगा। इस बजट में मेरी विधान सभा को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने, उप-मुख्य मंत्री जी ने जो योजनाएं दीं, उसके लिए पोकरण की जनता और मैं स्वयं बहुत हृदय से धन्यवाद और साधुवाद भी करता हूं। फिर भी कुछ आशाएं, अपेक्षाएं हैं, क्योंकि हम सबका कर्तव्य बनता है कि जनता केलिए यहां आए है तो जनता के लिए मांग भी रखेंगे।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार के सामने मेरे कुछ सुझाव और मांगें रखूंगा, जो आपके पटल से सरकार तक पहुंचेगी। मेरा विधान सभा क्षेत्र पोकरण पश्चिमी राजस्थान का, आप सब जानते हैं दुर्गम क्षेत्र है। मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पोकरण विधान सभा 5 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नहीं है, 300 किलोमीटर लम्बी विधान सभा है। आप कल्पना कीजिए और मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि आप सब वहां पधारे। मेरी विधान सभा का भौगोलिक और सामाजिक संरचना के लिए आप पधारे, आपका स्वागत है, पता चलेगा कि पोकरण की जनता किन विषम परिस्थितियों में जी रही है। क्या-क्या उनकी आवश्यकताएं हैं? 70 साल देश स्वतंत्र होने के बाद भी आज दिन तक ढाणियों में बैठे हुए लोग सड़क, लाइट, पानी से वंचित है। वह भी आपकी जनता

है, वह भी देश के नागरिक है, उनको भी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। जिस प्रकार शहर में रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपनी सुविधा के लिए कहता है, ठीक वैसे ही मानव अधिकार के आधार पर वहां की जनता को भी सड़क मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान आकर्षित हो कि वहां जनसंख्या को आधार में रखते हुए कोई विकास की योजना नहीं बने। वहां भौगोलिक परिस्थिति और विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए योजना बने। जिस प्रकार से आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा को ध्यान में रखते हुए आपने योजना बनायी है, ठीक वैसे ही पश्चिमी राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मानवीय सुविधा देने के लिए योजना बननी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे मुरब्बों में जो किसान रहते हैं। किसानों को फसल करना अति-आवश्यक है, क्योंकि उसकी आजीविका का आधार वही है। अब यदि वे मुरब्बे सिंचित करें और 5-6-7 किलोमीटर अपने पांच या छः साल के बच्चे को स्कूल में कैसे भेजेगा? उसके लिए योजना क्या बनेगी? आप दूरियां नहीं रखकर जनसंख्या रखेंगे तो मुरब्बों में जनसंख्या नहीं है, वहां दूरियों को ध्यान में रखकर विद्यालयों का निर्माण होना चाहिए, चिकित्सालय भी होने चाहिए और सड़क भी होनी चाहिए। वहां का रेगिस्तान है। आप सड़कें जो बना रहे हैं, विशेष कोटा रेगिस्तान को देना चाहिए। न वहां मोटर साइकिल चलती है, न साइकिल चलती है, न सिविल गाड़ी चलती है, वहां चलते हैं तो ऊँट चलते हैं या फोर व्हीलर गाड़ी चलती है। इसलिए सड़कों का भी यदि जाल बिछाना है तो सबसे पहले राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आपको देना चाहिए, तब राजस्थान का विकास दिखेगा आपको। वहां की जनता की आवाज दिखेगी।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पोकरण की जनता आपसे बहुत अपेक्षाएं रखती है। मैं दूसरी बात करूंगा कि आप सब जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में मेरे क्षेत्र के ही केबिनेट मंत्री थे। केबिनेट मंत्री जी ने सरकार की जो योजनाएं बनीं, उन योजनाओं को सीमित करना शुरू किया। मैं सत्य कह रहा हूं, दुर्भावना रहित कह रहा हूं, उन्होंने व्यक्ति विशेष और विशेष समाज के लिए योजना बनायी। क्षेत्र के लिए योजना नहीं बनायी।

Ans/rtm 14.50 2h 16.07.2024

वक्फ बोर्ड को मजबूत किया। अल्पसंख्यकों के छात्रावास की जमीनें अलॉट की। जो आबादी भूमि थी, सरकारी ऑफिस के लिए जो जमीन थी उनको वक्फ बोर्ड व अल्पसंख्यक छात्रावास को देकर, उनका विकास जरूर किया, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। हमारे जो भी सरकारी कार्यालय बनने चाहिए, उनकी जमीन आरक्षित, उनके पास रहनी चाहिए। आबादी के लिए आबादी की रहनी चाहिए। उसके बाद देश का विकास, सबका विकास, सबका विश्वास हम भी चाहते हैं कि उनके लिए छात्रावास बने परन्तु नियमों को तर्क संगत रखते हुए किया जाए।

श्री सभापतिः दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अंत में एक बात कहूंगा। पिछली सरकार में मेरे क्षेत्र में बहुत बड़े घोटाले हुए। उसमें सबसे बड़ा घोटाला गायों को चारा, अल्पसंख्यक छात्रावासों एवं वहां जो कॉपरेटिव सोसायटी है, उनके माध्यम से किसानों के हित को मारने के लिए बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। एक विशेष निष्पक्ष टीम बनाकर गौ चारा अनुदान में एवं हमारे किसानों का कॉ-आपरेटिव सोसायटी के माध्यम से हक मारा गया है, उनकी निष्पक्ष जांच की जाए। मेरे क्षेत्र में विकास के बहुत माध्यम है। बहुत सारी विदेशियां कम्पनियां आई है।

श्री सभापति: विराजे।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): सीएसआर का फण्ड मेरे यहां विकास में लगाए। चूंकि रामदेवरा बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है। जिस प्रकार आप धार्मिक स्थानों का विकास करते हैं, बाबा रामदेव 36 कौम, सभी समाजों के देवता है, रामदेवरा का विकास किया जाए।

पोकरण नगरपालिका देश आजाद होने से पहले 1936 में बनी, लेकिन आज भी ढांचा ऐसा पड़ा है कि लगता नहीं है कि आप नगरपालिका में गए हो या किसी गांव में गए हो, इसके लिए उसको भी ध्यान में रखे। ऐतिहासिक नगरी है, परमाणु नगरी है। पोकरण का विकास हो। पोकरण के क्षेत्र का विकास हो। पोकरण सिंचित एरिया कैसे हो, उसके लिए एक योजना बनी हुई है। पोकरण सिंचाई परियोजना को लागू किया जाए। हमीर सिंह जी विराज रहे हैं, यहां बहुत से लोग बैठे हैं। नाचना से निकलर बायतू तक एक नहर चलती है, सिंचाई के लिए नहीं है पेयजल के लिए है। जब क्लोजर आता है, उस समय यदि पानी नहीं मिलेगा तो पानी कैसे पहुंचेगा, इसके लिए मेरा सुझाव है कि फलसूंड के अन्दर पानी का एक बहुत बड़ा हब बनाया जाए। 550 गाँवों में आपातकालीन पानी योजना सुचारु की जाए। मैं इतना ही कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं इस सरकार को, जिन्होंने राजस्थान के विकास में चार चाँद लगाने के लिए इतना सुन्दर और सटीक बजट बनाया। मैं आपसे भी आशा रखता हूं, आइये राजस्थान के विकास में 5 साल अपने कर्तव्य का निर्बाध, ना रूकेंगे ना झुकेंगे, ना बिकेगे, ना बंटेगे, एक होकर राजस्थान के विकास में काम करेंगे। जय-जय राजस्थान। जय-जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री अशोक चांदना।

श्री अशोक (हिण्डोली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: आपको दस मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है।

श्री अशोक (हिण्डोली): बिलकुल, मुझे यह ज्ञात है। इस बजट को मैंने पढ़ा। पूरा बजट पढ़ने के बाद मुझे पांच बिन्दु लगे जिन पांच बिन्दुओं के ऊपर पर्ची सरकार का बजट केन्द्रित है। वह पांच बिन्दु मैं इस सदन को बताना चाहता हूं।

पहला, नाम बदलो बजट। जो भी योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार की थी, उन योजनाओं को नये नाम के साथ जनता के सामने पेश करने का यह बजट है। पूर्ववर्ती सरकार कोसो बजट।

आप आगे क्या करनेवाले हैं, आपका क्या विजन है, वह विजन भी मत बताओ, अपनी दिशा भी मत बताओ, पूर्ववर्ती सरकार को कोसकर ही अपना काम चलाओ, यह पूर्ववर्ती सरकार को कोसो बजट है। तीसरा, नहीं सहेगा राजस्थान कहकर इस राजस्थान के राज में सरकार आई। इस बजट से तो यह लगता है कि अब बेरोजगारी, महंगाई और अपराध सहेगा राजस्थान बजट हमारे बीच आ चुका है। पक्षपात करने वाले, इस बजट के मैं बाद में आपको बिन्दु बताऊंगा। भाजपा को वोट नहीं देने वालों के साथ बदला लेने वाला यह बजट माननीय मुख्य मंत्री और माननीय उप मुख्य मंत्री महोदया ने पेश किया है। आँकड़ों के साथ प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला बजट, प्रदेश की जनता के सामने इस सरकार ने रखने का काम किया।

सबसे पहले मैं बात करुंगा, राजस्थान में बहुत बड़ी आबादी है जो किसानी करती है और बहुत बड़ी आबादी है जो किसानी पर आधारित है। बार-बार एमएसपी की बात होती है। देश के अन्दर 700 किसानों ने एमएसपी के लिए शहादत दी। 125 रुपये प्रति क्विण्टल एमएसपी बढ़ाकर वाहवाही लूटने वाली सरकार सदन में यह बता दे कि 2700 रूपये क्विण्टल गेहूँ खरीद का वादा करके 2400 रुपये क्विण्टल में गेहूँ की खरीद की। पूर्व में जहां डेढ़ से दो लाख मैट्रिक टन एमएसपी पर खरीद होता था, अगर इस साल दस लाख मैट्रिक टन भी खरीद हुआ हो तो यह सरकार इस सदन को बता दे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आंकड़ों के आधार पर जनता को गुमराह करने वाला बजट है।

दूसरा, माननीय मुख्य मंत्री जी की एक दिन प्रेस मीट हुई। उन्होंने कहा कि राजस्थान के किसानों को रात के बजाय दिन में बिजली देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इस बजट के अन्दर ऐसा कोई प्रावधान हमें नजर नहीं आया कि विशेष बजट या प्रावधान रखा हो कि किसानों को दिन में बिजली मिलने की व्यवस्था करेंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने भी की थी लेकिन अभी ऐसा कोई बजट में प्रावधान नहीं है। यह वही सरकार है जिसने वीसीआर काटने के लिए लिखित आदेश निकाले हैं। ज़िले को सम्बोधित करते हुए कि फलां ज़िले के अन्दर दिसम्बर में वीसीआर भरो किसानों का, इस प्रकार का आदेश लिखित में निकाला। ...(व्यवधान)... शर्म ही नहीं आती। बीच-बीच में बोलते हैं।

माननीय सभापति महोदय, कृषि कनेक्शन। अभी घरेलू कनेक्शन के लिए तो इस बजट में प्रावधान किया गया है, अब कितने पूरे होंगे वह तो बजटीय वर्ष पूरा होगा तब पता लगेगा। पुराने पेंडिंग कृषि कनेक्शन हैं, उनको लगाने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। इस बजट में उल्लेख किया गया कि किसानों की आमदनी डेढ़ गुणा की जाएगी, तो वह किस आधार पर डेढ़ गुणा होगी, उसका प्रावधान इस बजट में नहीं है। यह बजट पूरी तरह से इस प्रदेश के किसान के सपनों का, किसान के बच्चों के भविष्य का और प्रदेश के किसान के अरमानों का धोखा है।

सभापति महोदय, अब में युवाओं के रोजगार पर आना चाहूंगा। बहुत वाहवाही लूटी गई कि हम लोग 4 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे, लेकिन उसमें यह तो बताइये कि पूर्ववर्ती

सरकार ने नौकरियों की जो प्रक्रिया पूरी कर ली, वह चार लाख में इंक्ल्यूड है? क्या पूर्ववर्ती सरकार ने एक साल, दो साल, तीन साल काम करके, नौकरियां पकाकर ज्वाइन बाकी रह गई, परीक्षाएं हो चुकी है, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्या उनको इन 4 लाख में लाया जाएगा? मैं तो कह रहा हूं यह बजट का प्रथम सत्र है, अगर 4 लाख नौकरियां देंगे तो इनको मान जाएंगे। वह समय भी हमारे सामने बहुत दूर नहीं है।

माननीय समापित महोदय, अपनी ही बात में विरोधाभास है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि नौकरियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ बिन्दु 51 में, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेड के साथ 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। रोजगार देंगे कि अवसर उपलब्ध कराएंगे, अवसर तो उपलब्ध है। राजस्थान में हज़ारों इंडस्ट्रीज हैं, अवसर तो है,लेकिन रोजगार दिलाने में सरकार की क्या योजना है, सरकार का क्या रोल रहेगा, यह पेश करे।

दूसरा, बिन्दु संख्या 54 में, पांच वर्षों में 50 हजार से अधिक एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी लाई जाएगी, जिससे 50 हजार से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। रोजगार देना चाहते हो कि अवसर देना चाहते हो। आंकड़ें दिखाकर जनता को भटकाना चाहते हो। यह नहीं चलेगा। आपकी मानसिकता आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी। बिना स्पष्ट किए आप राजस्थान के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। यह वह सरकार है जो एक तरफ रोजगार देने की बात करती है और दूसरी तरफ रोजगार पाए हुए लोगों को बेरोजगार करने का आदेश निकालती है, मैं इस सदन में इनकी दोहरी मानसिकता बताता हूं। 25 दिसम्बर, 2024 को 5 हजार युवा मित्रों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया।

VPS-RTM-16.07.2024-15.00-2j

महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती जो सम्पूर्ण हो चुकी थी, हमारे प्रदेश के युवा और युवतियां ज्वाइनिंग करने वाले थे, उस भर्ती को इन्होंने निरस्त कर दिया तो यह भर्तियां निरस्त करके, राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाकर आप रोजगार देने की मानसिकता का परिचय नहीं दे रहे हैं, आप तो बेरोजगार करने का परिचय दे रहे हैं। सरकार को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि इनकी मानसिकता प्रदेश के बारे में क्या है?

माननीय सभापति महोदय, साथ ही इन्होंने एक बात कही है कि हम नशा मुक्ति केन्द्र दस जिलों में बनाएंगे। भारतीय समाज में शुरू से नशा और जुआ, इन दो सबसे बड़ी कुरीतियों के खिलाफ सभी समाज के वरिष्ठ लोग हमेशा आवाज उठाते हैं लेकिन आज ऑनलाइन गेमिंग सट्टा घर-घर में चल रहा है, गांव-गांव में चल रहा है। वह ऑनलाइन सट्टा कौन चला रहा है? उन कम्पनियों को लाइसेंस कौन दे रहा है? उनसे चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा कौन ले रहा है?

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अशोक (हिण्डोली): उन लोगों का भी खुलासा इस सदन में होना चाहिए क्योंकि यह

किसी भी प्रकार से प्रदेश के युवा के साथ धोखा करने वाली मानसिकता है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के बेरोजगार युवा को, जिसको कि पूर्ववर्ती सरकार ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने 4500 रुपये तक भत्ता दिया। एक लाख बेरोजगारों को भत्ता देने की सीमा को बढ़ाकर दो लाख तक किया तो इसके बाद यह सीमा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी?

माननीय सभापति महोदय, जब से यह सरकार बनी है उसके बाद में, इसको बने सात-आठ महीने हो गये, अभी मैंने एक प्रश्न लगाया कि आज तक बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया गया? 250 करोड़ रुपया, बेरोजगारों का पैसा छह महीने तक इन्होंने अपनी ट्रेजरी में रखा है। बेरोजगारों के ये हितैषी है ही नहीं।

श्री सभापतिः एक मिनट में आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्री अशोक (हिण्डोली): माननीय सभापति महोदय, युवाओं के लिए खेल बहुत ही जरूरी है। खेलों में पूर्ववर्ती सरकार ने आउट ऑफ टर्न पॉलिसी बनाई कि जो अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं, उनकी सरकारी जॉब लगने का रास्ता खोला तो आप युवाओं को यह भी बतायें कि इन छह से आठ महीने के अन्दर क्या एक भी खिलाड़ी को आपने ज्वाइनिंग दी क्या? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जब खिलाड़ियों से कोई नौकरी लगाने के नाम पर पैसा ले लेगा, उनके साथ धोखाधड़ी कर देगा, उनके अरमानों को कुचल देगा तो क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? आपने जो पेंडिंग 300-400 एप्लीकेशंस हैं, उनकी स्क्रूटनी करके ज्वाइनिंग क्यों रोकी हुई है? इस सदन में यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताये।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री अशोक (हिण्डोली): जो कि अपने आपको युवाओं का बड़ा हितैषी बताने का काम कर रही है। साथ ही साथ ग्रामीण ओलम्पिक जैसी योजना को बंद कर दिया।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिये। आपका समय समाप्त हुआ। श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल।

श्री अशोक (हिण्डोली): चलिये, मैं इसको आखिरी में एक बात कह कर अपनी बात को खतम करता हूं। एक मिनट में ही कर रहा हूं।

श्री सभापतिः आज आप समझें। 30 सैकण्ड में अपनी बात कह दें।

श्री अशोक (हिण्डोली): एक मिनट में ही कर रहा हूं।

इन्होंने सिसरो का अपने बजट के अन्दर उल्लेख किया जिन्होंने यह लिखा था कि लोगों का स्वास्थ्य, कल्याण, सहायता, खुशहाली सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन इनके कर्मों में विरोधाभास है।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री अशोक (हिण्डोली): क्योंकि इनको कर्मों में मन्दिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, आदिवासियों का डी.एन.ए. करवाना, ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक (हिण्डोली): 000

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे परिवर्तित बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: आपको दस मिनट में अपनी बात को समाप्त करनी है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय सभापति महोदय, भजन लालजी की सरकार ने राजस्थान में जो नया इतिहास बनाया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने देखा और हम सबने देखा कि जिस समय बजट को पढ़ा जा रहा था, उस समय सिर्फ एक ही मंशा थी उप मुख्य मंत्रीजी की कि राजस्थान में विकास घर-घर तक कैसे पहुंचे, राजस्थान में विकास हर गांव तक कैसे पहुंचे और उसी मंशा को ध्यान में रखते हुए ई.आर.सी.पी. जैसी बड़ी योजना जो कि 21 जिलों को प्रभावित करती है और कई वर्षों से गहलोत साहब जिसके लिए छुपा-छुपी का खेल खेल रहे थे। कभी वे यह कहते थे कि मध्यप्रदेश वाले नहीं मान रहे हैं, कभी कहते थे कि केन्द्र सरकार को भेज दिया और सिवाय असत्य बोलने के उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन माननीय भजन लालजी ने मुख्य मंत्री बनने के 55वें दिन इस घोषणा को लागू करके यह अहसास दिलवा दिया कि राजस्थान के अन्दर किसान का बेटा ही किसान की समस्या का समाधान करने के लिए मुख्य मंत्री बना है।

माननीय सभापति महोदय, जब बजट के अन्दर यह घोषणा की गयी कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक मॉडल सी.एच.सी. सरकार बनाएगी तो उसमें हमने यह नहीं दिखा कि इस विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस का विधायक जीता है या बी.जे.पी. का विधायक जीता है, बल्कि हमने तो 200 के 200 विधान सभा क्षेत्र में मॉडल सी.एच.सी. बनाने की बात कही है। यह समानता से देखने का नजरिया भारतीय जनता पार्टी का ही हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, पांच करोड़ रुपये की सड़कें हमने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को देने की जो बात कही थी उसको भी हमने बिना पक्षपात के देने का काम किया है और विधान सभा के अन्दर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच करोड़ रुपये की सड़कें बनेंगी, यह हमने घोषणा की थी और इसको हमने पूरा किया है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): मुझे यह कहते हुए भी बड़ा गर्व होता है कि दस हजार की जनसंख्या की, पापुलेशन के अन्दर ऐसे विद्यालयों के अन्दर जिम बनेंगे जिसमें बच्चों को जिम की सुविधा उपलब्ध होगी और मुझे यह कहते हुए भी बड़ा गर्व होता है कि आंगनबाड़ी के अन्दर हफ़्ते में तीन दिन गरीब के बच्चों को दूध पिलाने का भी अगर काम किया तो माननीय भजन लालजी की सरकार ने किया है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: श्रवणजी, बैठ जाओ।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार): माननीय सभापति महोदय, मैं पिछली सरकार के लोगों को यह याद भी दिलवा देना चाहता हूं कि इन्होंने जो इतिहास बनाये, एक तरफ तो

भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के इतिहास बना रही है और दूसरी तरफ पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार के इतिहास बनाये। पिछली सरकार ने पेपर लीक का इतिहास बनाया। पिछली सरकार ने दलित के ऊपर बलात्कार, अत्याचार का इतिहास बनाया, पिछली सरकार के अन्दर मंत्री और मंत्री पुत्रों द्वारा पेपर बेचने के और घर-घर जल जैसी योजना के अन्दर बड़ा घोटाला करने का इतिहास बनाया, 20 लाख करोड़ रुपये का और मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं होता है कि जिस बिजली पर यहां पर बारबार चर्चा हो रही है, इस बिजली के अन्दर भी अभी की जो डिमांड है, अभी की जो मांग है 19 हजार मेगावाट और कांग्रेस के समय में, कांग्रेस ने जो हमें दी थी वह 13 हजार मेगावाट और इनके बेकलॉग में ये जो दिखा रहे हैं 23 हजार मेगावाट बिजली दिखा रहे हैं जबकि कोटा, अंता, छबड़ा, सूरतगढ़, धौलपुर, झालावाड़ सहित इनकी कई सारी यूनिट तो यह कोयले की कमी के कारण चला ही नहीं पाये थे।

माननीय सभापति महोदय, इनकी करनी और कथनी में अंतर है। उस समय इन्होंने यह सोच कर कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बचानी है, उसी उद्देश्य से इन्होंने काम किया है। आये दिन नई घोषणा, आये दिन नये वादे और यहां तक कि हजारों करोड़ रुपया फाइव स्टार होटल में भी खर्च करने का काम किया है तो पिछली गहलोत सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना सा ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक विजन लेकर आये हैं। माननीय प्रधान मंत्रीजी मोदीजी एक सोच के साथ में काम करते हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमारे घोषणा पत्र के अन्दर हमने जो-जो बातें हमने कही थीं, उन सभी बातों पर इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को कहा और उनसे यह भी कहा कि हमने जो वादा किया है उसको हम 100 प्रतिशत पूरा करने का काम करेंगे।

SSY/RTM/16.07.2024/15.10/2k

माननीय सभापति महोदय, मुझे धन्यवाद देने में कोई संकोच नहीं होता पहली बार एक ऐसा इतिहास बना है कि खण्डार के अन्दर लगभग साढ़े 300 करोड़ की सड़के पहले बजट में उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी ने दी। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

मुझे यह कहते हुए भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमने जो-जो डिमांड हमारे विधान सभा क्षेत्र को लेकर की थी, वह सारी मांगें चाहे वह पर्यटन को डवलप करने की बात हो, उसके अन्दर हमारे जोगी महल को डवलप करने के लिए पैसा दिया गया। रोजगार को लेकर तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा, हम सब के ध्यान में है, की है।

साथ ही, पूरे राजस्थान के अन्दर हरित क्रांति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए माननीय भजन लाल जी ने 7 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान के अन्दर लगाने की भी इस बजट में घोषणा की। मैं उसके लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने

एक संकल्प लिया, देश के प्रत्येक नागरिक से यह आग्रह किया कि एक पेड़ मां के नाम, हम सोचकर अपने-अपने घर में स्वयं लगाने का काम करेंगे तो हरित क्रांति के नाम पर पूरा राजस्थान हरा हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 10 लाख रोजगार देने की बात भी हमारे घोषणा-पत्र में, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में की। साथ ही, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमने आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति जिनको कोई बीमारी हो, 25 लाख, 25 लाख यह कहा करते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि 25 लाख के राजस्थान के अन्दर कितने मरीजों का इलाज आपने करने का काम किया?

सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी ने प्रस्तावित बजट जो रखा, उसके अन्दर पूरे राजस्थान का ध्यान रखा गया। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अपने क्षेत्र के अन्दर छोटी-छोटी एक-दो बाते हैं जो आपके माध्यम से उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं। भगवतगढ़ के अन्दर कन्या महाविद्यालय खोलने की बात, खण्डार के अन्दर उप जिला स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की बात, बहरावंडा में 132 जीएसएस खोलने की बात मैंने कही थी। सिवाड़ के अंदर उप तहसील बनाने की बात मैं उनके ध्यान में दिलाना चाहता हूं। खण्डार के किले का जीर्णोद्धार, ऐसी छोटी-छोटी चीजें हैं, जो आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में जायें।

हमारे मुख्य मंत्री जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। जब-जब भी उनसे कोई निवेदन करता है, मैं तो उनके साथ 20 साल से काम कर रहा हूं, उनको संगठन का बहुत लंबा-चौड़ा अनुभव है। वह अपनी सूझ-बूझ के साथ निर्णय लेते हैं, वह आगे आने वाले समय में भी राजस्थान के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। प्रियंका चौधरी जी। आपको 5 मिनट में अपनी बात पूरी करनी है।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): सभापति महोदय, आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा एवं माननीय उप मुख्य मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी को हार्दिक बधाई देना चाहूंगी कि आपने एक ऐतिहासिक बजट राजस्थान के लिए अपने कार्यकाल के प्रथम सत्र में दिया।

इस सदन में जो चर्चा सुन रही थी, 3 दिन से जो चर्चा हुई उसमें एक बात बार-बार आई, पर्ची की बात बार-बार आ रही थी। पर्ची इधर भी है। पर्ची उधर भी है। हम बीच में हैं। हम उस पंक्ति में हैं जो न 'ना' में है, न 'हां' में हैं। लेकिन जब पर्ची की बात आती है तो मैं माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी पर आज राजस्थान की जनता को जो भरोसा है, जो विश्वास है, एक साधारण

सा कार्यकर्ता भी पूरी हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ यह बोलता है कि नहीं, मैं मुख्य मंत्री जी को जानता हूं और आधी रात को भी जाऊंगा तो मेरा काम होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी।

इत्तफाक अपनी जगह खुशकिस्मती अपनी जगह,

खुद बनाता है आदमी जहां में अपनी जगह।

पर्ची तो अलग बात है। मैं यह मानती हूं कि यह 4 पंक्तियां सिर्फ भजन लाल जी शर्मा साहब के लिए नहीं बल्कि इस सदन में बैठे हर व्यक्ति पर लागू होती है कि यहां इस सदन में आये हैं तो सभी में कोई न कोई बात है। तब इस सदन में आये हैं।

सभापति महोदय, बोलने का वक्त बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप मुझे संरक्षण दें और मैं अपनी बात कर पाऊं।

मैंने जब बजट पर चर्चा सुनी तो यह बात सामने आई, विपक्ष ने कहा, ना पक्ष ने कहा कि चुनावी बजट है। मैं मानती हूं कि चुनावी बजट बोलना ही इस बजट की खासियत को हमारे सामने लेकर आता है। क्योंकि जब आप चुनावी बजट बोलते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जो नीति है, वह स्पष्ट है और जो नीयत है वह नेक है। आपने जो इस ना पक्ष ने, जो पूर्ववर्ती सरकार ने काम किया, वह किसान की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहें दलितों की बात करें, आपने सिर्फ उसको राजनीति करने के लिए एक मुद्दा बनाया और इसीलिए जो घोषणाएं कीं, वे अंत में की।

मैं धन्यवाद देती हूं आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा को और श्रीमती दिया कुमारी जी को, जिन्होंने पूरे राजस्थान के विजन को ध्यान में रखते हुए इस प्रदेश को फिर से अग्रणी श्रेणी में किस तरह लाया जाये, इसके लिए यह बजट दिया। मैं उनको राजस्थान की पूरी जनता की तरफ से धन्यवाद देती हूं।

अभी बहुत सारी चर्चाएं हुई। युवाओं की बात सभी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यह जो युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, कहां गये पिछले 5 साल जब हमारा राजस्थान बेरोजगारी में दूसरे नम्बर पर था। बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं रोजगार चाहिए। कहां हमारे प्रदेश को आप अग्रणी श्रेणी से, मुझे ध्यान है जब आदरणीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी थी, तब हमारा प्रदेश शिक्षा में पहले नम्बर पर था। रोजगार में पहले नम्बर पर था। कौशल प्रशिक्षण में पहले नम्बर पर था। जल स्वावलंबन अभियान में पहले नम्बर पर था। पिछले 5 साल में राजस्थान की क्या दुर्दशा कर दी, देखते हुए अफसोस होता है।

अभी सड़कों की बात हो रही थी। सड़कों की बात आपको याद दिलाना चाहूंगी कि इस सदन के ही विपक्ष के पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय हेमाराम जी चौधरी, उन्होंने इसी सदन में पिछले सत्र में मुद्दा उठाया था। जो सड़क बनी थी, बाड़मेर विधान सभा के विधायक की एक फर्म ने, उनके रिश्तेदार की फर्म ने वह सड़क बनाई थी। उस सड़क की स्थिति यह थी कि वह बनने से पहले ही जर्जर अवस्था में पहुंच गई। यह पिछले समय की सड़कों के हालात

थे।

सभापति महोदय, शिक्षा की बात करें। बार-बार शिक्षा की बात आती है। अभी किसी माननीय सदस्य ने पिछले दिनों में कहा था कि किसी की हिम्मत नहीं कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद कर दे। हम देखते हैं कि कैसे बंद कर देंगे। यह विपक्ष से बात आई थी। मेरा प्रश्न है कि आप सब बहुत सीनियर हैं, हमारे राजस्थान की, हमारे विकास की जो नींव है वह शिक्षा है। इस शिक्षा के साथ आपने यह खिलवाड़ कैसे कर दिया? कैसे स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बना दिया बिना व्यवस्था कराये? बिना टीचर्स की व्यवस्था कराये? मानती हूं कि यह समस्या केवल 'हां पक्ष' की नहीं, जो विपक्ष में, 'ना पक्ष' में बैठे हैं, उनकी भी हर विधान सभा में यह समस्या होगी। वहां के बच्चों का रजिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, वह कम हो रहा है, क्योंकि टीचर्स नहीं हैं। मिडिल स्कूल के जो टीचर्स हैं वह 12वीं के बच्चों को लेकर बैठे हैं। ऐसी शिक्षा से हम कैसे बच्चों को रोजगार तक ले जायेंगे और क्या शिक्षा देंगे?

सभापति महोदय, मैं आदरणीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहूंगी, हमारी लंबी मांग थी, बाड़मेर में एयरपोर्ट के लिए जमीन देने की। उन्होंने निःशुल्क जमीन देने की व्यवस्था की है। मैं उनको धन्यवाद देती हूं।

132 केवी जीएसएस के लिए धन्यवाद। सड़कें 25 किलो मीटर दी हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारी एक बहुत बड़ी मांग थी नशा मुक्ति सेंटर की, वह 25 बैड का दिया है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में इसका विस्तार भी होगा।

श्री सभापतिः श्री पितराम सिंह काला।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): मैं मांग करुंगी, एक मिनट, एक मिनट। सभापति महोदय, मांगने तो दीजिये।

श्री सभापतिः देखिये, सदन के नेता अपना वक्तव्य देंगे। विराजें।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): मांगने दीजिये, एक चीज मांगने दीजिये। मैं धन्यवाद देती हूं कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो हरियालो राजस्थान मिशन की बात की है, जो अरबन लंग्स की बात की है, एक ऑक्सीजोन की मांग हमने की है। जिसमें बाव़डिया हैं, जिसमें धार्मिक स्थल हैं।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैडम जी, आपका समय हो गया है।

Spp/Rtm/16.7.2024/15:20/2l

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): उसमें एक पांच किलोमीटर के क्षेत्र के अन्दर अगर वह ऑक्सीजोन का प्रोजेक्ट हमारे बाड़मेर को दिया जाये तो निश्चित रूप से वहां पर्यावरण को

बचाने में मदद मिलेगी। बिजली में दो नये उपकरण दिये जायें और पी एच सी सनावड़ा को...(व्यवधान)..

श्री सभापतिः बिराजिये। अंकित नहीं होगा।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): 000

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान बिन्दु संख्या 9 के तहत दिलाना चाहता हूं। बजट के बिन्दु संख्या 9 के अन्दर यह प्रावधान किया गया है इसको गौर से सुनना। दो वर्ष में प्रत्येक विधान सभा में 20-20 हैण्डपम्प और 10 ट्यूबवैल सैंक्शन किये जायेंगे। दो वर्ष में, एक वर्ष में नहीं किया गया है। मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा पिलानी विधान सभा क्षेत्र है, उसके अन्दर नरग्राम पंचायत है, उसके अन्दर 16 ट्यूबवैल हैं। उनमें से 13 ट्यूबवैल सूख चुके हैं। देवरोड ग्राम पंचायत है, उसके अन्दर 9 में से 7 सूख चुके हैं और सूखे हुए ट्यूबवैल हैं उनकी जगह दूसरे ट्यूबवैल लगाने का जो प्रस्ताव भेजा है, वह आज तक भी सैंक्शन नहीं किये गये हैं। इसी के साथ 16 ट्यूबवैलों में से कुछ ट्यूबवैल टी.एस.एस.स्कीम के तहत सैंक्शन कर दिये। जब जलदाय विभाग के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि ग्राम पंचायतों के ट्यूबवैल हैं। ग्राम पंचायत यह कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है। सात महीने से किसी प्रकार का बजट आवंटन नहीं हुआ है। आज वहां यह स्थिति है कि लोग पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। टंकियों में पीने के लिये पानी ही नहीं है। लोगों को आन्दोलन करना पड रहा है तो ऐसी भंयकर स्थिति पानी की है कि वहां पिलानी विधान सभा के अन्दर पानी का जो टैंकर है, उसको तीन दिन पहले बुक करवाना पड़ता है उसके बाद में पानी मिलता है। आप दूध क्विंटल में ले लीजिये, मिल जायेगा। आपको घी मिल जायेगा, तेल मिल जायेगा, तुरंत शाम तक पहुंच जायेगा, लेकिन जब पानी की बारी आती है तो तीन-तीन दिन तक टैंकरों से पानी नहीं मिलता है। यह आज हमारे लिये बड़े शर्म की बात है।

माननीय सभापति महोदय, आगे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिलानी एक विधान सभा क्षेत्र है जिसमें लोक सभा के अन्दर और विधान सभा के अन्दर ग्रामीणों ने दस जगह चुनाव का इसलिये बहिष्कार किया कि पहले हमें पानी का हक और अधिकार दो। हमारे पास पीने के लिये पानी नहीं है। उसको देखते हुए यह किया गया कि चुनाव का बहिष्कार किया गया। गरीब, किसान, मजदूर हैं, उनके पास टैंकर मंगवाने के लिये पैसे नहीं हैं तो आप लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि लोग वहां से पलायन करने के लिये मजबूर हो रहे हैं। केवल और केवल पानी के अभाव के अन्दर पलायन हो रहा है। अतः मेरी इस सदन से मांग है कि जो हैण्डपम्प का प्रावधान किया गया है, माननीय सभापति महोदय, शेखावाटी का जो क्षेत्र है उसके लिये नासा की रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया है कि सबसे ज्यादा भूजल स्तर यदि कहीं नीचे गया है तो वह शेखावाटी और विशेष रूप से पिलानी क्षेत्र के अन्दर गया है। वहां हैण्डपम्प काम नहीं करते। पूरी शेखावाटी के अन्दर ही काम नहीं करते। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उन हैण्डपम्पों के स्थान पर ट्यूबवैल सैंक्शन

कराने का आप प्रावधान करें।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ पिलानी के अन्दर यमुना जल का जो पानी है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय वहां गये थे और उन्होंने घोषणा की थी कि हमने समझौता कर लिया और चार महीने के अन्दर इसकी डीपीआर बन जायेगी। वह चार महीने की अवधि 17 जून को समाप्त हो गयी, पर अभी तक भी डीपीआर नहीं बनी। केवल और केवल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पब्लिक मीटिंग के अन्दर यह कहा था, यह बड़े शर्म की बात है। मैं निवेदन करता हूं कि जब तक यमुना के पानी की व्यवस्था नहीं होती है, कुम्भाराम लिफ्ट योजना के द्वारा पानी की व्यवस्था की जाये। जब तक कुम्भाराम लिफ्ट योजना की व्यवस्था नहीं होती है, जो ड्राई ट्यूबवैल हैं, प्रत्येक के आगे, वहां 122 ग्राम हैं, उसके अन्दर 64 ढाणियां हैं, तीन नगर पालिकाएं हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है, जगह जगह पानी सूख गया है तो जो ड्राई ट्यूबवैल हैं उनके पास में नई स्वीकृति दिलायें जिससे जनता को राहत मिले।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं आगे निवेदन करना चाहूंगा जो किसान है उनके पीने के लिये ही पानी नहीं है तो उनके खेतों के अन्दर कुण्ड बनाने के लिये अनुमत किया जाये और उसको अनुदान दिया जाये जिससे कम से कम वह कृषि के लायक तो नहीं, पीने के लिये पानी तो रहे और वे जिंदा रह सकें और पलायन को मजबूर नहीं हों।

माननीय सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों आप लाइट की बात कर रहे थे जितनी बिजली की परेशानी इस गर्मी के अन्दर देखी, आज तक कभी नहीं देखी। पूरी- पूरी रात मात्र एक एक घंटे बिजली दी गयी जिससे किसान न तो काश्त कर सका, गर्भवती महिला जो डिलीवरी के अन्दर भी उनको भी काफी दिक्कत हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली कटौती है उसको बंद किया जाये। अभी शिक्षा के अन्दर जो बात कर रहे थे। ...(व्यवधान)..

श्री सभापतिः विराजें माननीय सदस्य।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, मैं कन्क्लुड कर रहा हूं, केवल एक मिनट।

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा। बिराजें माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल जी। दस मिनट में आपको अपनी बात कहनी है।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): 000

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, परिवर्तित बजट 2024-25 के लिये मुझे बोलने का अवसर दिया है। माननीय सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे जीवन में पहली बार इस लोकतंत्र के मन्दिर पर बजट पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं इस बात के लिये मेरे विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा और वागड़ की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे भारी बहुमत से जिताकर अपने क्षेत्र के चहुंमुखी विकास करने की बात रखी और यहां पर प्रतिनिधित्व करने भेजा। माननीय सभापति महोदय, माननीय भजनलाल जी शर्मा, माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं वित्त मंत्री महोदया दिया कुमारी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इस बजट 2024-25 में पूरे राजस्थान के चहुंमुखी

विकास के साथ-साथ वागड़ का भी पूरा ध्यान रखा है। राजस्थान में पिछले समय भर्ती करने के नाम पर जो अनियमितता हुई है, वह बात कोई छिपी हुई नहीं है। युवाओं के साथ अन्याय किया गया। उनके सपनों को पेपर लीक की भेंट चढ़ा दिया गया। सब्जी मंडी में जिस तरह सब्जी खरीदने जाते हैं, ऐसे ही पेपर की बिक्री हुई जिससे अभ्यर्थियों के कैरियर की बलि चढ़ा दी गयी। युवाओं में निराशा का माहौल बन गया। आज के बजट से युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है एवं एक लाख भर्ती का कलैण्डर तैयार कर नई उम्मीदें बना दी हैं। दूसरी ओर पेपर लीक करने में लिप्त लोगों में दहशत का माहौल बना दिया है, जो पूर्ववर्ती सरकार में निडर होकर पेपर बेचा करते थे, वह अब स्पेशल टास्क फोर्स से छिपते बचते नजर आ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट से गरीब, युवाओं, अन्नदाता और महिलाओं को सम्बल देने का प्रयास किया गया है। जो आने वाले दिनों में उनको स्वाभिमान से जीने का अवसर देगा। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई। ऐसी सोच एक सरकारी बेटा ही सोच-समझ सकता है। जो माता-पिता के लिये नई उम्मीद लेकर आया है। पिछली सरकार ने मेरे वागड़ में जातियों को लड़ाने एवं काकरी-डूंगरी जैसा दहशत का माहौल बना दिया जिसमें समाज-समाज में आपस में एक वैमनस्यता फैलाई गयी और मेरे आदिवासी बच्चों पर मुकदमें दर्ज करा दिये। मेरे 1201 आदिवासी बच्चों पर मुकदमे दर्ज हुए। वे आज न्याय की भीख मांग रहे हैं। इनके जीवन को बर्बाद कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट से मेरे वागड़ को सोम कमला अम्बा डेम से सिंचाई एवं पेयजल हेतु नहर का पानी मिला। 24 घंटे बिजली हेतु 220 केवी जीएसएस मिला। इसके अलावा भी कई सौगातें भी मिली हैं। ऐसा बजट विजनरी व्यक्ति जो सोच सकता है, जो विकसित भारत के साथ-साथ विकसित राजस्थान को बनाने का सपना देखता है। इसलिये मोदीजी कहते हैं यही समय है, सही समय है। इसी पर शायर खुशबीर सिंह ने कहा है कि इस उम्मीद पर तो काट लीं मुश्किलें हमने, अब इसके बाद तो ये शायद आसानी में रहता हो।

Jyg/rtm/16.07.24/15.30/2m

इस सरकार ने बजट के माध्यम से हमारे क्षेत्र वागड़ में आदिवासियों की योजनाओं के लिए आदिवासियों को भी बहुत सारा दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्य मंत्रीजी को और हमारे वित्त मंत्रीजी को, जिन्होंने हमारे वागड़ को ध्यान में रखते हुए वहां पर विकास की जो बात कही है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भी आज का जो बजट है उसको देखा जाए तो आने वाले पांच साल में यह बजट आगे बढ़कर हमारे वागड़ का, हमारे डूंगरपुर जिले का, सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र का बहुत सारा आगे विकास होने वाला है। वहां किसानों के लिए जो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, उस समस्या का इतिहास में पहली बार समाधान हुआ है। वहां पर कैनाल से पानी देने का काम किया। इसको 130 करोड़ रुपये का

बजट दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं सदन के माध्यम से हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को और हमारी वित्त मंत्रीजी को, मैं धन्यवाद देता हूं, यहां पर हम सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे यहां जितने भी सदस्य बैठे हैं। राजस्थान की पूरी जनता की नजर है कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं आने वाले समय में हमारे यहां वागड़ में विकास की और भी बहुत-सी जरूरतें हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में इण्डस्टीज खोलने के लिए मैं सदन से निवेदन करता हूं। वहां पर 20 से 25 हजार युवा लोग काम करें, जो बेरोजगार हैं, जो गुजरात के लिए जाते हैं, पलायन करते हैं, वे वहां नहीं जाकर यहीं अपना गुजारा करें, ऐसी व्यवस्था किए जाने का मैं सदन से निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आखिर में, सबने मेरी बात को सुना, मुझे बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबकी ओर से सागवाड़ा की जनता को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती इन्द्रा। पांच मिनट।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, 32 हो चुके हैं, आप बीच में ही रोक देते हो।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपनी-अपनी बात रख रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी अपनी बात रखना चाह रही हूं कि जिस तरीके से बजट पेश हुआ, हमने देखा, सुना, जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष के लोग बात कर रहे हैं, ये जो बजट है वो किसी भी प्रकार से जनता के हित में नहीं है। माननीय सभापति महोदय, पक्ष के सदस्य कहते हैं कि 2023 के अन्दर आनन-फानन में बहुत सारी घोषणाएं कीं, बहुत सारे ऐसे वायदे किए लेकिन मैं अवगत कराना चाहूंगी कि हमने जो देखा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कोई ऐसा कार्य नहीं बचा जो हमारी सरकार ने घोषणा की और वो धरातल पर नहीं उतरा। इतने सारे मुद्दे, इतनी सारी योजनाएं सरकार की रहीं। इन सब बातों से यह जाहिर होता है कि ये चुनावी घोषणाएं इन मुद्दों को बताते हैं, लाइट फ्री देने को, चिकित्सा फ्री देने को, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को अगर राजनीतिक बजट बताते हैं तो इसका मतलब है कि ये कोई भी इस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का इन पांच सालों के अन्दर इस राजस्थान के अन्दर नहीं करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में इन्होंने न ईआरसीपी की बात की, न एमएसपी की बात की, किसानों के लिए कोई इस प्रकार की योजना नहीं लेकर आए जो उनके लिए महत्वपूर्ण फायदे की बात हो। ईआरसीपी की बात की इन्होंने तो पिछली हमारी सरकार के अन्दर जो बजट हमने घोषित कर दिया, उसी बजट को दुबारा इन्होंने पढ़ने का काम किया है। नौकरियों की बात इन्होंने की, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए तो हमारी सरकार काम कर चुकी थी या माननीय सदस्य, माननीय मंत्री भी जो यहां विराजमान हैं, उन्होंने अपने

ट्विटर पर उन पोस्टों को किया जो कि हमारी सरकार ने कर दीं, बाद में युवाओं को और बेरोजगारों को पता चला कि ये गलत कर रहे हैं तो इन्होंने अपनी पोस्टें ट्विटर से डिलिट कर दीं। अगर ये सही थे तो अपनी पोस्टों को अपने ट्विटर पर रहने देते।

माननीय सभापति महोदय, हर राजस्थानी का एक ही संकल्प-एक ही नारा, इस तरह के पोस्टर इन्होंने बनाए, जिनमें इन्होंने लिखा, बहन-बेटियों पर अत्याचार, दलित पर अत्याचार, कर्ज मरता किसान। मैं कहना चाहूंगी कि किसान कृषि मंत्री बनाये। उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज देना ही नहीं चाहिए। तो किस तरीके से फायदा किया इन्होंने? बहन-बेटियों पर अत्याचार, मैंने सवाल किया, बहन-बेटियों पर इतना अत्याचार बढ़ गया कि एक साल का आंकड़ा इन्होंने पांच महीने में पार कर दिया। दलित अत्याचार, दलित अत्याचारों का आंकड़ा हम देखेंगे तो गांव के अन्दर दलित इतना परेशान और सहमा हुआ महसूस कर रहा है, इतना डरा हुआ महसूस कर रहा है, इस सरकार के अन्दर कि कोई उसकी सुनने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, पेपर लीक की बात करते हैं ये बढ़-चढ़कर, क्या इन्होंने पेपर लीक रोक दिया? पेपर लीक की बात इनको अपने मुंह से कहते हुए शर्म नहीं आती? ये लोग जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आए, उन मुद्दों को इन लोगों ने हल नहीं किया। भष्टाचार की ये बात करते हैं, मैं कहना चाहूंगी कि खण्डार से हमारे माननीय सदस्य आते हैं, उन्होंने एक रोड बजट के अन्दर ली, उस भगवतगढ़ से हथरोली तक का रोड लिया, वहां पर हाई नहीं है, वहां के लोगों की कोई मांग नहीं है लेकिन साफ-साफ उस रोड को इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र से बजरी निकाल कर ले जा सकें, तो इसमें भष्टाचार साफ-स्पष्ट होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगी कि इन पांच सालों के कार्यकाल में जितने भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में काम हुए हैं उनकी भी जांच कराई जाए और इन छह महीनों में जो काम हुए हैं, उनकी भी जांच कराई जाए तो भ्रष्टाचार का पता लगता है इन लोगों का। एक काम मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुआ रीको का नाम बदलने का, राम-जानकी रीको इण्डस्ट्रियल एरिया बना दिया उसको जबकि हमारी सरकार ने उसका सारा काम कर दिया था।

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, सारे के सारे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, शिक्षा, चिकित्सा, पंचायतीराज और कानून-व्यवस्था, इन सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं कराना चाहते, इसका यह मतलब हुआ कि सदन के अन्दर आप इन सारे जो जन कल्याणकारी मुद्दे हैं, जो जन कल्याणकारी विभाग हैं, जिनसे जनता सीधे जुड़ी हुई है, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं कराने का सीधा-सा मतलब है कि आप जनता के सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, आप जनता के हित में नहीं हो।

श्री सभापतिः बैठिए आप।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: डॉ. सुरेश धाकड़।

डॉ. सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस बजट सत्र में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

पिछले दो दिनों से जो बहस हम सुन रहे हैं, उसमें हमारे ना पक्ष लॉबी के लोग कुछ ज्यादा ही दु:खी हैं। इनको युवाओं की बड़ी चिंता है। बेरोजगारों की और युवाओं की चिंता के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कोई छात्र अगर कोई पढ़ाई करता है, कोई युवा अगर कोई एक्जाम की तैयारी करता है, बड़ी मेहनत से वो घर-बार छोड़कर, उसके मां-बाप के अरमान होते हैं। जब मेहनत करने के बाद जब वो परीक्षा देने जाता है और परीक्षा देने के बाद जब वो पढ़ता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन मीडिया में आता है कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक प्रकरण। यह पेपर लीक सरकार, इसीलिए आप लोगों को विपक्ष में बैठाया गया कि आपने रोज-रोज पेपर लीक कराकर, बार-बार आपकी जब सरकार थी तो यह चीज पढ़ने में आती थी कि यहां पेपर लीक हो गया, वहां पेपर लीक हो गया। या बजरी की कोई बात, या अवैध खनन की कोई बात, एक सदस्य, जो कोटा के अभी तो विधायक नहीं बन पाए, पर वो अवैध खनन को लेकर आपकी सरकार को ही कोसते रहे, मुख्य मंत्रीजी को पता नहीं कितनी चिट्ठियां लिखीं, पर कुछ नहीं कर पाए। फिर नाथी का बाड़ा, रोज छपता, अख़बार में, आपके एक परिवार के कितने अधिकारी बन गए, क्या बन गए और अब आप घड़ियाली आसूं बहा रहे हो कि युवाओं के, बेरोजगारों के लिए क्या किया? क्या नहीं किया? यह पहला बजट है, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की है कि हम चार लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे जब हमारा अंतिम बजट आए तो आप यहां पर खड़े होकर प्रश्न करना कि हमने चार लाख नौकरियां नहीं दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार चार लाख नौकरियां देगी, आपको उसको गिन कर बताएंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह डबल इंजन की सरकार है। पहले हमारी दिल्ली में सरकार थी, यहां की आपकी सरकार को हटा कर हम बने तो डबल इंजन की सरकार बनी। थोड़े दिनों बाद वापस चुनाव हुए तो हमारी सरकार बन गई। हां, थोड़े-बहुत आप लोग जरूर खुश हुए कि आप 99 पर आ गए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जिन्दगी भर 99 पर ही रहें और हमारी सरकार बराबर बनती रहे।

माननीय सभापति महोदय, मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, मोदीजी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने तीसरी बार सरकार बनाई। उप मुख्य मंत्रीजी, दिया कुमारीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिस तरीके से ब्राह्मणी नदी पर एक एनिकट की घोषणा की और जो पुलिया बन रही है, एनिकट कम कॉज वे या बड़ी पुलिया, उससे मेरे आदिवासी क्षेत्रों को आने-जाने के लिए रावतभाटा होकर जाना पड़ता था, हमारे क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग थी, उस जंगल में एक पुलिया बनेगी तो निश्चित रूप से उससे चार-पांच ग्राम पंचायतों

को फायदा होगा तो मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, श्रीपुरा के निकट एक सड़क जो जंगल में होकर निकलती, फोरेस्ट लैंड में थोड़ी दिक्कत रहेगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पहले बजट में आपने उस सड़क की घोषणा कर दी, जिससे हमारे हरिमोहनजी के विधान सभा क्षेत्र को जोड़ने का मौका मिलेगा तो उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी एक सड़क, नौ मील चौराहा गंगरार, साड़ास, बेगूं से एमपी सीमा तक जो 94 किलोमीटर की है, उसके लिए 129 करोड़ रुपए के लगभग लागत आएगी और आपने प्रथम बजट में मुझे, मेरे क्षेत्र के लोगों को दी है तो मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से और आपकी तरफ से, क्योंकि पिछली बार जब मैं विधायक था तब भी मेरी इच्छा थी कि यह सड़क बन जाए, लेकिन उस समय, अंतिम समय होने के कारण नहीं बन पाई तो इस बार पहले बजट में आने के कारण में आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी बिजली के लिए सब लोग कह रहे हैं, यह बिजली आपकी ही देन है। आप लोग जो घाटे-घाटे की बात कर रहे हो न, इतना गड़बड़ कर दिया ..(व्यवधान)...

MLS/RTM/16.07.2024/15:40/2n

इसकी भी हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि हम किसानों को दिन में बिजली देंगे। आने वाले समय में अभी साढ़े चार साल तो कोई चुनाव नहीं हैं, हम वापस मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि अब किसानों को दिन में बिजली मिलने लग गयी है। इस बात की भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यवस्था करेगी। सभापति महोदय, किसानों को दिन में बिजली मिले, इसके लिए 400 केवी जीएसएस, 220 केवी जीसएसएस, 33 जीएसएस, ऊर्जा मंत्री जी भी यहां विराजमान हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक 220 केवी का जीएसएस बनेगा, जिससे मेरे क्षेत्र में जो लोड शेडिंग, ट्रिपिंग या किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलने जैसी समस्याओं का समाधान होने की पूरी सम्भावना रहेगी और मेरे क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। आपने बस्सी, जो कि एक दूरस्थ क्षेत्र है, वहां पर 33 केवी का जीएसएस स्वीकृत किया है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, पता करें कि पूरी की पूरी प्रतिपक्ष की बैंचें खाली क्यों हैं? कहीं कोई विशेष घटना-दुर्घटना तो नहीं हुई?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): पारीक साहब नहीं दिख रहे आपको?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पारीक साहब तो आराम से नींद ले रहे हैं।

श्री सभापति: रफीक भाई प्रतिपक्ष के कार्यवाहक नेता की भूमिका अदा कर रहे हैं। अपने सदस्यों को बुलाएं।

डॉ. सुरेश धाकड़ (बेगूं): सभापति महोदय, ब्राह्मणी नदी पर 500 करोड़ की लागत से एक

बड़ा बांध बनने वाला है। मेरे क्षेत्र में भी छोटी-मोटी डिमांड रहेगी वहां। यदि खेती के लिए कोई उपलब्धता हो सकती है तो मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाये। रावतभाटा में एक बाड़ोली मन्दिर है। वहां 22 साल पहले नटराज की मूर्ति चोरी हो गयी थी। एक घीया नाम का तस्कर था, उसकी चोरी का प्रकरण लम्बा चला। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूंकि वे उस मूर्ति को लन्दन में पकड़वाकर वापस लाये और वापस उसे रावतभाटा में शिफ्ट किया। इसके लिए मैं देश के प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं। अभी रफीक जी, आप बोल रहे थे न, आपकी सरकार थी तब इनको तो मन्दिर से कोई लेना-देना नहीं, अगर यह सरकार चाहती तो दो साल से वह मूर्ति इन्तजार कर रही है कि उसके लिए छाया हो, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मुझे इस क्षेत्र की जनता ने विधायक बनाया है, यह डबल इंजन की सरकार वहां नटराज की मूर्ति के लिए छाया की व्यवस्था भी करेगी और रावतभाटा का वह जो बाड़ोली का मन्दिर है, वह एक ऐतिहासिक मन्दिर बनेगा।

छोटे-मोटे काम चिकित्सा सम्बन्धी हैं। चिकित्सा में कुछ दिक्कत आ रही है। जल्दी से इलाज नहीं मिलता है। मेरा चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि उस पर थोड़ा ध्यान दें। जैसे ही रोगी हॉस्पिटल में जाये, उसे तुरन्त इलाज मिलना चाहिये। अन्त में, यह जो पेपर लीक सरकार थी पुरानी, हमारी सरकार के बारे में बोलती है कि हमारी सरकार पर्ची सरकार है, मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि देश के पहले प्रधान मंत्री का चुनाव कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पर्ची पर किया, आपको बोलना नहीं चाहिये। केवल हल्ला-गुल्ला मचाना, बातें करना, इससे काम नहीं चलता है। काम होना चाहिये। मैं भजनलाल जी को धन्यवाद देता हूं कि हजारों युवाओं का जो भविष्य अन्धकार में जा रहा था, पेपर लीक के सारे प्रकरण खुलवाकर, एसओजी से जांच कराकर उन्होंने बड़े-बड़े लोगों को अन्दर डाला है।

अभी कुछ माफिया तो यह कह रहे हैं कि हम सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने कहा, आपको सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, हम आपको पकड़कर जेल में डालने का काम करेंगे। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय।

श्री सभापति: श्री मांगेलाल मीना। पांच मिनट।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस परिवर्तित बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस शुभ अवसर पर राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की 36 कौम जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां भेजा है। बजट भाषण माननीय वित्त मंत्री महोदया के द्वारा प्रेषित किया गया था। इसका अवलोकन करने के उपरान्त यह पता चला है कि राजगढ़-लक्ष्मणगढ़, जो पिछड़ा हुआ आदिवासी क्षेत्र है, उसकी पूर्ण रूप से उपेक्षा की गयी है। कहीं भी एक बार भी उसके नाम का उल्लेख नहीं किया गया कि राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ को हमने इस बजट में यह दिया है।

एक माननीय सदस्य: पानी पिला दिया पानी।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): महात्मा जी, आप ईआरसीपी की बात करते हैं, पानी पिलाने की बात ही नहीं है कहीं भी। कुछ भी नहीं दिया। अरावली पर्वत की श्रेणियों के बीच बसा हुआ और दो गढ़ों राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ से मिलकर बना हुआ विधान सभा क्षेत्र है। तपोभूमि के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी अवहेलना की गयी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैंने बजट में समावेश करने के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ कार्यों की सूची उन्हें दी है। सम्बन्धित मंत्रियों को भी उनके मेल पर डाली हुई है। कृपया प्रत्युत्तर देते समय आप उसका समावेश करेंगे तो मैं और वहां की जनता आपका आभार व्यक्त करेगी उसके लिए।

सदन की कार्यवाही में प्राय: देखा गया है कि पक्ष-विपक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं कि आपने यह कर दिया, आपने वह कर दिया। यह करने से राजस्थान का भला होने वाला नहीं है। राजस्थान का भला समस्याओं पर मन्थन करने से होगा। आप कहते हैं कि पेपर लीक सरकार थी। नीट, यूजी के भी बारे में बात कर लें। अपनी तरफ भी देख लें। कोई कम नहीं है। आप भी कम नहीं हैं। आपके भी यूजी नीट का हल्ला हो रहा है। उसे रिजेक्ट भी किया आपने। पहले 2004 में एक बार 13 लोगों के पास पेपर पहुंचा था। उस नीट के एग्जाम को 2004 में रिजेक्ट कर दिया गया था। अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लेना, इससे बड़ी गलत धारणा बनती है।

मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नाम बदलने की धारणा में विश्वास नहीं करते हुए गहलोत सरकार के द्वारा चलायी गयी जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। आप कहते हैं, 450 रुपये में सिलेंडर दिया है, किसने याद दिलाया था, उज्ज्वला योजना देने के बाद भूल गये थे, 1250 रुपये में सिलेंडर दे रहे थे। माननीय गहलोत साहब का गरीब जनता, गरीब परिवारों की तरफ ध्यान गया और उन्होंने 500 रुपये में दिया। 50 रुपये आपने कम किये। हमने 750 रुपये कम किये थे। आप इस तरह से वाह-वाही मत लूटिये। 20 हजार नौकरियां देने की बात करते हैं, 20 हजार नौकरियां दी कहां हैं? एक भी नौकरी का विज्ञापन यदि जारी किया हो पिछले 7 महीनों में तो बता दें। पहले की सारी प्रक्रिया पूरी कर रखी थी, उन्हें नौकरियां मिली हैं। वह गहलोत सरकार की उपलब्धि थी, जो आपने उन्हें नौकरियां दी हैं।

आप पक्ष-विपक्ष में बैठने के बाद ''जय श्री राम'' के नारे लगाते हैं। हम भी कहते हैं ''सीता राम'', सारे सदस्यों को पुन: मैं राम-राम करता हूं। गारंटी की बात करते हैं, मैं यह कहता हूं, दस साल में एक भी गारंटी पूरी की हो तो बता दें। सारी गारंटियां फेल हो गईं। हम हिन्दू धर्म और उसकी संस्कृति को मानते हैं, सात फेरे लेते हैं, हवन भी होता है, अग्नि साक्षी होती है, पर उसके उपरान्त भी पहली गारंटी ही फेल हो जाती है तो ऐसी गारंटियां देने वालों का क्या देश विश्वास करेगा? आप ईआरसीपी और पीकेसी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, अलवर के कोई बांध डीपीआर में नहीं जोड़े हैं। उसके लिए पहले भी मैंने माननीय जल संसाधन मंत्री जी को और

मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा था और मेल भी डाला था। आज तक उसका प्रत्युत्तर नहीं आया है कि उनका उसमें समावेश कराएं।

अगर बांधों को जोड़ेंगे ही नहीं तो फिर उनसे सिंचाई की कैसे कल्पना कर सकते हैं? पीने का पानी, मैं तो यह कहता हूं, राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ और अलवर के ही तो आदिवासी क्षेत्रों के वे सब लोग हुए हैं जो जा-जाकर पानी पिलाते हैं, यूपी में जाकर गिरिराज जी महाराज के वहां प्याऊ लगाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, राजगढ़ शहर की जनता को तो पानी पिला दें। सेकण्ड फेज में डीपीआर के लिए सैंक्शन थी, उसके बाद ईसरदा बांध से केवल बसवा में पानी जा रहा है। बसवा से मात्र तीन किलोमीटर दूर है, उसे ईसरदा से पानी तो पिला दें। पानी पिला दीजिये, इतना मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है। युवाओं के लिए अग्निवीर लाये थे... (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापतिः विराजें। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्रजी।

श्री मांगेलाल मीना (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): 000

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान की विधान सभा में परिवर्तित बजट के सम्बन्ध में मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री भजनलाल जी और आदरणीय दीया कुमारी जी ने जिस प्रकार से राजस्थान की आम जनता के लिए बजट पेश किया है, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की 36 कौम के लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह है, खुशी है। मैं मानता हूं कि इसमें हर एक विधान सभा क्षेत्र में कहीं भी न पार्टी को देखा गया है, न जाति को देखा गया है। सिर्फ प्रदेश का कैसे भला हो, उस दृष्टि से माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट जनता के बीच में रखा है।

मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने 10 तारीख को बजट पेश किया और आज 16 तारीख है। इन पांच दिनों के अन्दर-अन्दर हमारे प्रभारी मंत्री और हमारे अधिकारियों के माध्यम से विधान सभा क्षेत्रों में जो-जो घोषणाएं हुई हैं, उनमें भी त्वरित गति से कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

mkd/rtm/16.07.2024/15:50/2o

मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत जी की सरकार, मैं मेरे महवा विधान सभा क्षेत्र का उदाहरण दूंगा, वहां करीब दो उप-तहसीलों की घोषणा हुई थी, तीन कॉलेजों की घोषणा हुई थी। वहां पर अभी तक यह पता नहीं है कि उप-तहसील कहां है, कहां उप तहसीलदार बैठता है, कहां कॉलेजेज हैं, अभी तक कुछ अता-पता नहीं है और कुछ कॉलेजों की जो घोषणा हुई है, उनको अपने चहेते विधायकों के मार्फत महवा विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय पर अगर कोई घोषणा हुई तो उसको चार किलोमीटर दूर ले जाने का काम गहलोत सरकार ने किया। वहां पर न छात्र पहुंच सकते हैं, न वहां पर छात्राएं पहुंच सकती

हैं।

मैं तो आपसे इतना कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जिस प्रकार का बजट पेश किया है निश्चित रूप से यह बहुत कारगर साबित होगा और आने वाले पांच वर्षों में हमारे मुख्य मंत्री जी और अन्य घोषणाएं करेंगे, निश्चित रूप से राजस्थान की दशा और दिशा तय करेंगे। मैं आपके मार्फत यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा में, जो केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन परियोजना थी, जो हर घर में नल देने का काम, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार से उसमें जबरदस्त घोटाला किया। आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी पार्टी जब विपक्ष में थी तो सरकार के खिलाफ बड़ा जनआंदोलन हुआ और पूरे राजस्थान में करीब 20 हजार करोड़ रुपये का जबरदस्त घोटाला गहलोत सरकार ने इसमें किया।

मेरे अकेले महवा विधान सभा क्षेत्र में करीब 40 करोड़ का घोटाला हुआ। जिसमें पीएचईडी मंत्री जी भी सरकार बनने के बाद वहां पर मौके पर पहुंच थे, कहीं पाइप पालन नहीं थी, कहीं तार नहीं थे, कहने का मतलब है कि उस पूरी व्यवस्था को इतना जबरदस्त खराब किया। राजस्थान की जनता आज पानी के लिए तरस रहीं है।

मैं विपक्ष में बैठने वाले भाइयों से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है। जो कारनामें आप पिछले पांच वर्षों में करके गये थे, हमारी सरकार उन सभी कामों को मूर्त रूप देकर जनता के सामने रखेगी। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, खासतौर पर मुख्य मंत्री जी को और प्रधान मंत्री जी को कि आदरणीय किरोडी लाल जी का सपना, जो 1989 से था कि ईआरसीपी का पानी आम जनता तक कैसे पहुंचे, उन्होंने जब-जब अवसर मिला इस ईआरसीपी के लिए बहुत आंदोलन किये। आम जनता के लिए, आज हमारी सरकार बनने के बाद मुख्य मंत्री जी ने पहला जो काम किया है, वह ईआरसीपी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। निश्चित रूप से सरकार इस काम को पूरा करके आम जनता तक पानी पहुंचाने का काम करेगी। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि इनकी सरकार, जो एक अपंग सरकार थी, जिसको निर्दलीय विधायको का समर्थन था। उस सरकार में, उनको इतनी खुली छूट दी गई थी, एक विधायक के कहने के अलावा क्षेत्र के अन्दर आम जनता का कोई भी काम नहीं होता था।

मैं आपसे मेरे महवा विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा, वहां पर जब तक क्षेत्रीय विधायक मेडिकल ऑफिसर या हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट को फोन नहीं करें, तब तक किसी को भी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल सकता था। आम जनता जाये भाड़ में। इसलिए इनकी नकारा, निक्कमी सरकार ने पांच साल जो कारनामें किये हैं, भ्रष्टाचार चरमसीमा पर था, निर्दलीय विधायकों को वहां एक मिनी मुख्य मंत्री बनाकर सत्ता सौंपने का इन्होंने काम किया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन्हीं के कारनामों से ये विपक्ष में बैठे हैं। निश्चित रूपसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री, क्योंकि वे संगठन से आते हैं। संगठन का व्यक्ति निचले स्तर के एक-एक व्यक्ति का दु:ख दर्द समझता है, इसलिए इस

राजस्थान को हम सब मिलकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आपने मुझे अवसर दिया, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री जयकृष्ण पटेल। आप चार मिनट में अपनी बात कहें।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बजट सत्र पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। आज के इस मौके पर मैं सबसे पहले मेरी बागीदोरा विधान सभा क्षेत्र की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस क्षेत्र के अन्दर कई समय से विकास के नाम पर काम तो हुए हैं लेकिन फिर भी वहां पर और राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताकर राजस्थान के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया।

मेरे जिले के अन्दर मुख्यालय बांसवाड़ा जिला पड़ता है और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ हमारा सम्भागीय क्षेत्र के अन्दर आता है। हमको वहां पर सड़क के नाम पर 9 हजार करोड़ में से मात्र 75 करोड़ का बजट दिखाई देता है। वहां पर भी हमारे साथ में भेदभाव हुआ है।

सभापति महोदय, विगत तीन-चार साल से पिछली सरकार ने भी, हमारे यहां पर व राजस्थान में कई दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब वर्ग के छात्रा-छात्राएं अध्ययनरत हैं और उनको आज तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है। सरकार ने छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए भी कुछ नहीं कहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं और जहां जल जीवन की बात आती है तो सरकार का 1300 करोड़ रुपये के ड्रेनेज जल संरक्षण का प्लान है, उससे बांसवाड़ा, डूंगरपुर को दूर रखा है।

माननीय सभापति महोदय, आज के इस मौके पर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डूंगरपुर जिले के डूंगर बरांडा, बांसवाड़ा जिले के बांसिया, चरपोटा और उदयपुर में काली बाई संग्रहालय बनाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापतिः विराजें।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): साथ ही, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में आनन्दपुरी के अन्दर उप जिला स्वास्थ्य केन्द्र बनाया है, उसके लिए भी मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने 70 हजार भर्तियों की घोषणा की है। उस बजट घोषणा के अन्दर टीएसपी क्षेत्र के अन्दर कितनी नौकरियां होंगी। उसके बारे में कोई विवरण स्पष्ट नहीं किया है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, हमारे वहां की जनता बैठी है, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, आज के बजट भाषण पर मैं आपको एक बात और अवगत कराना चाहता हूं कि यहां पर बीस हजार हेक्टेयर वन संरक्षण के माध्यम से सरकार वहां पर वन संरक्षण का प्लान लाई है लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे वहां पर जगपुरा, भूकिया सहित जो 10 गांव हैं, वहां पर खनन के लिए नीलामी के जो

आदेश निकाल दिये हैं, वहां पर विस्थापितों के लिए सरकार के पास क्या योजना है।

श्री सभापतिः विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): 000

श्री सभापतिः श्री लालाराम बैरवा।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): माननीय सभापति जी, आपने बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रदेश को अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका कल्याण की सोच के साथ अथक परिश्रम कर अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का सतत प्रयास किया है।

प्रसिद्ध कवि श्री शिवमंगल सिंह की पंक्तियों से प्रेरणा लेकर हम सार्थक संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर-दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पडा, जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है।

माननीय सभापति जी, पिछली सरकार ने रेवड़ी की तरह हमारे राजस्थान में जिले दिये। जिसमें शाहपुरा को भी जिला बनाया। उन्होंने राजनैतिक लाभ लेने के लिए जिले का सीमांकन किया। वहां पर जिन्दल की, हिन्दुस्तान जिंक की शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में जो माइंस आती थीं, उनको विधिवत तरीके से मांडल के अन्दर, 6-6 पंचायतों को मिलाया गया, केवल राजनैतिक लाभ लेने के लिए और शाहपुरा को केवल ऐसे ही खाली छोड़ दिया। जिससे शाहपुरा जिला बन तो गया, लेकिन शाहपुरा जिले के विकास के लिए वहां पर कोई साधन नहीं हैं।

Bhs/Rtm/16.7.24/16.00/2p

औद्योगिक क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो शाहपुरा में आज की तारीख में वहां पर कुछ नहीं है। एक केवल आगूचा माइन्स की तरफ से डीएमएफटी फंड से वहां पर जो पैसा आता था वो भी सीधा-सीधा भीलवाड़ा जिले में ट्रांसफर होकर जाता है वहां केवल मात्र दस परसेंट शाहपुरा जिले को मिलता है। इसी प्रकार जब जिले की घोषणा हुई तब शाहपुरा की जनता पिछली सरकार से यह निवेदन कर रही थी कि आगूचा माइन्स को शाहपुरा में रहने दिया जाये। वह शालीनता के साथ अपनी मांग कर रही थी और पिछली सरकार ने अपने दबंगई दिखा कर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उन पर मुकदमे लगाये, उनके सिर फोड़े गये, उनको शारीरिक चोटें पहुंचाई गई उसके बावजूद भी राजस्थान में सरकार नहीं आई। जिन्होंने जिले घोषित किये, जिनको तोहफे दिये गये वो भी इस सरकार में जीत कर नहीं आये।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार पिछली सरकार में युवाओं के साथ अत्याचार किये गये, बेरोजगारी के आलम पर लाकर उनको खड़ा किया गया, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हुए यह वास्तव में उस सरकार का जघन्य अपराध था।

मान्यवर, मैं कुछ बातें आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि पिछली सरकार में 2020 में खाद्य सुरक्षा के नाम पर मिलने वाली सुविधा को बन्द कर दिया और आज गांव-गांव में खाद्य सुरक्षा के लिए लोग तरस रहे हैं, नये नाम उनके जुड़ नहीं रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस योजना को भी तुरन्त प्रभाव से चालू कराया जाये।

सभापति महोदय, औद्योगिक क्षेत्र में शाहपुरा बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शाहपुरा अगर जिला बना है तो रोजगार की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए शाहपुरा में औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना चाहिये। मैं भाजपा सरकार और हमारे सम्माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने शाहपुरा को ध्यान में रखते हुए शाहपुरा के अन्दर जो अभी बजट में घोषणाएं की हैं उनमें युवाओं का ध्यान रखते हुए युवाओं को खेल अकादमी और तीन मण्डलों में उन्होंने हमारे को स्टेडियम दिये इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का और मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापतिः धन्यवाद। विराजें।

श्री लालाराम बैरवा (शाहपुरा): और उन्होंने हमारे को 270 करोड़ के जो रोड़ दिये हैं उसके लिए भी मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री संजय कुमार। पांच मिनट में अपनी बात कहें।

श्री संजय कुमार (बसेड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने की अनुमति प्रदान की। माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय पूर्वी राजस्थान से आते हैं और पूर्वी राजस्थान में हमारा धौलपुर, करौली, गंगापुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और दौसा पांच-छह जिले आते हैं, जो बजट पेश किया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ जहां आपके भाजपा के विधायक हैं वहीं बजट दिया गया है और जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां बजट नहीं दिया गया, तो यह पूर्वी राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात है उनके साथ धोखा हुआ है। यह उनके साथ बिलकुल धोखा हुआ है।

पूर्वी राजस्थान की जो जनता आपको देख रही है उनके साथ बिलकुल धोखा किया गया है। रही आपकी बात, आप देख लीजिये 25 में से 14 पर आये हैं 11 हमने जीती है और पूर्वी राजस्थान में तो सूपड़ा साफ किया है हमने आपका।

रही आपकी बिजली की समस्या पिछले सात माह से जो आमजन बिजली से त्रस्त था परेशान था, गर्मी कितनी पड़ी थी हीटवेव चली थी लेकिन आपकी सरकार के द्वारा उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। आपने बजट में बताया कि दो साल में हम दो लाख आठ हजार घरेलू कनेक्शन देंगे लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सात महीने में घरेलू कनेक्शन की कितनी पेंडेंसी है, उनके डिमाण्ड नोटिस भर चुके हैं लेकिन उनके लिए आज तक, पैसा भी वो जमा करा चुके हैं लेकिन आप उनके लिए न तो मीटर लगा चुके हैं और न

ही कनेक्शन लगा चुके हैं।

महोदय, दूसरी बात आपसे मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं जिस जिले से आता हूं करौली धौलपुर उस जिले में आपने करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व घोषित किया सैद्धांतिक सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और उसके अन्तर्गत वन भूमि में स्टेट काल से जो लोग रह रहे हैं रियासत काल से लोग रह रहे हैं सौ-सौ साल से लोग रह रहे हैं उनके विस्थापन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उनके लिए जैसे कहते हैं आदिवासी जो अपने लोग हैं उनके पास जंगल, जल, जीवन, जमीन उनका ही तो है लेकिन विस्थापन के लिए आपने कोई बजट में व्यवस्था नहीं की। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं उसमें अधिकतर फोरेस्ट का क्षेत्र आता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आप उनके विस्थापन के लिए या उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी लेकर के आयें जिससे व्यावसायिक गतिविधियां मिले उनको और उनके विकास के लिए कुछ हो सके। साथ ही, मैं यह कहना चाहूंगा आपने ईआरसीपी के ऊपर इस बजट में 710 करोड़ रुपये कालीसिंध परियोजना के लिए बताये हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं पहली बार का विधायक हूं मुझे बोलने दें। कालीसिंध परियोजना में जो पॉलिसी लाई गई है मैं चाहता हूं कि आपकी डबल इंजन की सरकार है सेन्टर में भी आपकी सरकार है लेकिन उसको वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने के कारण वह काम ठप पडा हुआ है। काम चालू नहीं हुआ। मैं चाहता हूं सदन के माध्यम से कि हम एक ऐसी पॉलिसी, मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं, सत्ता और विपक्ष सबसे कहना चहता हूं कि हमें वन विभाग की एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिये जिससे कि डाईवर्जन का या कोई भी सड़क हो या कोई प्रोजेक्ट हो तो राजस्थान सरकार से ही उसका निस्तारण हो जाये न कि सेन्टर गवर्नमेंट को जाये। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी पॉलिसी लेकर के आयें।

सभापति महोदय, साथ ही मैं कहना चाहूंगा मेडिकल व्यवस्था के लिए। बड़े शर्म की बात है कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी पांच-पांच मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई और उलटा उन पर फाइन भी लगा दिया गया है जबकि आपकी डबल इंजन की सरकार है। मैं चाहता हूं कि राज्य में जो सोसाइटी के कॉलेज चल रहे हैं प्रत्येक जिले में उनकी वेतन विसंगति को जो राजस्थान आरपीएससी के द्वारा सात मेडिकल कॉलेज में भी ली जाती है उनके बराबर किया जाये जिससे राजस्थान की जनता को मेडिकल चिकित्सा में अच्छी सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भैरा राम चौधरी। पांच मिनट में अपनी बात कहें।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे परिवर्तित बजट 2024-25 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बजट में देख रहा था इसमें पूरे राजस्थान के लिए जैसे बिजली, पानी हरेक पहलू को छुआ। इसमें मेरे एक-दो सुझाव हैं। आपकी सोलर नीति के अन्दर 2023 में जो

इतनी सारी परियोजनाओं के लिए सोलर के लिए जो आपके एमओयू हुए हैं उसमें एक बात की अड़चन आ रही है और वह अड़चन यह है कि जो सामान्य वर्ग की जमीन है उस जमीन को तो भूमिधारक लीज पर दे सकता है पर जो एससी/एसटी की जमीन है उस जमीन को वह एससी/एसटी वर्ग लीज पर नहीं दे पा रहा है। इससे सोलर कंपनियों को भी और इन्वेस्टर को भी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। इसमें सामान्य वर्ग को तो 25 साल या 29 साल या जितने साल की भी लीज हो रहा है उसमें तो उनकी बंजर जमीन का एक रेवेन्यू प्राप्त होता रहेगा लेकिन एससी/एसटी वर्ग के साथ में यह भेदभाव हो रहा है उसमें कुछ न कुछ आपके रेवेन्यू के नियम आड़े आ रहे हैं, उन नियमों में संशोधन करके एक समानता का उदाहरण देना चाहिये कि यदि सामान्य वर्ग अपनी भूमि को 29 साल के लिए लीज पर देकर उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टर आता है और सोलर के उत्पादन की अपनी यूनिट लगाता है तो एससी/एसटी वर्ग भी अपनी भूमि को देना चाहता है,, लेकिन कहीं न कहीं रेवेन्यू में यह प्रोब्लम है इसलिये ऐसे नियमों में संशोधन होना चाहिये।

सभापति महोदय, एक मेरा दूसरा सुझाव है कि जब अपने राजस्थान में जैसे 14 जिलों में ईआरसीपी आयी है उसके लिए माननीय भजन लाल जी को और अपने देश के नेतृत्व को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

Kas/rtm/16.07.2024/16.10/2q

14 जिलों के लिये ई.आर.सी.पी. बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार पेयजल और सिंचाई की योजना आई है और आपने सिर्फ 3 से 6 महीनों में यह काम करके दिखाया है। इसमें मेरी यह मांग रहेगी कि हम लोग पश्चिमी राजस्थान से आते हैं और इंदिरा गांधी नहर इतने पुराने समय से बनी हुई है, इस ई.आर.सी.पी. की तर्ज पर ही हमारे पश्चिमी राजस्थान के लिये डब्ल्यू.आर.सी.पी. भी आनी चाहिये। इससे पश्चिमी संभाग, जोधपुर, पाली संभाग भी पेयजल और सिंचाई के लिये इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि वहां पीने का पानी भी नहीं है। वहां हमारे पास जमीन तो है, लेकिन पानी नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से और सदन से निवेदन रहेगा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही, आपके जालोर और सिरोही में तो थोड़ा बहुत नर्मदा का पानी आता है, लेकिन नागौर, जोधपुर, पाली में बिलकुल भी पानी नहीं है। ई.आर.सी.पी. की तर्ज पर डब्ल्यू.आर.सी.पी., वैस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट आये तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि पी.एच.ई.डी में जेजेएम के तहत पिछली सरकार में जिन्होंने यह ड्राइंग बनाई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने पूरे गांव में आधी ड्राइंग बनाई और आधा गांव छोड दिया है। गांव में जाते हैं तो आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति होती है। कोई कहता है बीजेपी वालों को दे रहे हैं, कोई कह रहा है कांग्रेस वालों को दे रहे हैं। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस बात की गलती की है, वह अपनी ड्राइंग चेंज करें। पी.एच.ई.डी. वाले कहते हैं कि हम डिविएशन नहीं देंगे। जब आप डिविएशन नहीं देंगे तो

विभाग के अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि वह गांवों में जाएं, उनका खेत देखें, उनकी ढाणी देखें। हमारे पश्चिमी राजस्थान में 'अपना खेत, अपना घर' का कंसेप्ट है। यदि प्रत्येक घर को नल से जोड़ना है तो आप अपनी ड्राइंग को चेंज करें और चेंज करके प्रत्येक घर में जल पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था करें।

मेरा एक और निवेदन है कि आपके पी.एच.ई.डी. विभाग में जब 2013-2018 में हमारी सरकार थी, 750 नलकूप बने थे। आपकी पिछली सरकार के 2018-2023 में मेरे क्षेत्र के लगभग 250 नल कूप बंद पड़े हैं, एक बूंद भी उसमें पानी नहीं आ रहा है। मेरा पी.एच.ई.डी. विभाग से भी यह निवेदन रहेगा कि उन नकारा नलकूपों को देख कर उनको ठीक करें या उनको दोबारा से करें, जिससे पेयजल की समस्या का समाधान हो सके।

मैं देख रहा हूं कि इतना शानदार और जानदार बजट दिया, इसके लिये आदरणीय भजन लाल जी, आदरणीय उप मुख्य मंत्री जी और टीम बीजेपी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः महन्त बालकनाथ जी।

महन्त बालकनाथ (तिजारा): धन्यवाद सभापति महोदय, आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राजस्थान के लिये आने वाले समय में राजस्थान का विकास, राजस्थान की जनता का भला किस प्रकार से हो, उस बजट की चर्चा में बोलने का मुझे अवसर दिया है। हम सबने इस बजट को बहुत अच्छे से देखा है, पढ़ा है। इस बजट में यह भावना हम सबको स्पष्ट रूप से नजर आती है कि यह बजट आने वाले समय में राजस्थान के विकास को लेकर आगे बढ़ेगा। हमारा एक विकसित राजस्थान बने, उस भाव को प्रदर्शित करने वाला यह बजट है।

मैं देख रहा था कि विपक्ष लगातार बजट को इस प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रहा था कि इस बजट में कुछ नहीं है। पिछले पांच वर्ष की सरकार को भी हमने देखा है। उस बजट की घोषणाएं तो यह भूल चुके हैं कि इन्होंने कितनी घोषणाएं की थीं और धरातल पर कहीं एक काम भी इनकी घोषणाओं का पूरा हुआ हो, ऐसा हमें राजस्थान में देखने को कहीं नहीं मिलता है। उन घोषणाओं के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करने का काम तो अवश्य रूप से इन लोगों ने पिछले पांच वर्ष में किया। जैसे ही बजट की घोषणा होती थी, पूर्व सरकार के नेता अपने क्षेत्र में जाकर ढोल बजाते थे, लेकिन उस बजट की घोषणा के अनुरूप कोई भी काम धरातल पर हमको देखने को नहीं मिला।

मैं मानता हूं कि पिछली सरकार में स्कूलों को क्रमोन्नयन करना रोज की घटनाएं थीं। स्कूल को 10वीं से 12वीं कर देना, उसका बोर्ड बदल देना, केवल इतने मात्र से स्कूल हायर सैकण्डरी नहीं हो जाता, उसमें अध्यापकों की नियुक्ति भी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, तब जाकर वह स्कूल उस लायक बनता है। इस दिशा में पिछली सरकार में कोई भी काम हम सब को देखने को नहीं मिला। आपको कोई अधिकार नहीं है इस बात को बोलने का, क्योंकि आप स्वयं का बजट नहीं जानते हो कि आप लोगों ने पिछले पांच वर्षों में कितनी

घोषणाओं का पिटारा खोला और जनता को क्या दिया। अभी हमारे अलवर जिले के विधायक और हमारे नेता, प्रतिपक्ष भी अलवर से हैं, वह भी पहुंच चुके हैं, वह भी ध्यान से सुन लें, उनको भी मैं बहुत ध्यान से सुनता आया हूं। आपकी सरकार में 2019 में पहले बजट में अलवर जिले को पानी पिलाने के लिये आपने 4718 करोड़ की घोषणा की थी। आज से लगभग साढ़े पांच वर्ष पहले आपने जो 4718 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, वह कहां लगा है? उसकी डी.पी.आर. कहां है, इसका जवाब आप दे सकते हैं तो सदन में देने की कृपा करें।

उसके बाद आपने आगे चलकर आपके फेसबुक पेज पर आपने ट्विट किया था, सोशल मीडिया पर डाला था कि ईसरदा से पानी आ गया, ढोल बजाओ। वह ढोल वैसे के वैसे रह गये, आज तक अलवर को पानी नहीं मिला है। इनके कार्यालय पर खूब ढोल बजाये थे, इनको खूब साफे पहनाये गये कि मंत्री जी पानी ले आये। मैं आपको बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी अलवर और अलवर के साथ उन सभी 13 जिलों को पानी पिलायेगी। बस आप लोग ध्यान रखना कि उस पानी में आप कहीं डूब कर मत मर जाना, क्योंकि वह इतना पानी आयेगा कि कांग्रेस को ले डूबेगा। सदा, सदा के लिये ले डूबेगा।

इस बजट में जो हमारी भजन लाल जी सरकार ने लिखा हैं, यह घोषणा आपके लिये होगी, हमारे लिये यह घोषणा नहीं है, एक संकल्प है, जो आने वाले पांच वर्षों में हमारी सरकार पूरा करेगी और इस संकल्प की नींव भरनी अभी से शुरू हो चुकी है। राजस्थान के विकास का नया निर्माण शुरू हो चुका है। कांग्रेस उस निर्माण की नींव में दब जायेगी और आने वाले समय में कांग्रेस राजस्थान में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार से इस बजट के एक-एक भाव को आने वाले पांच वर्षों में पूरा किया जायेगा और राजस्थान की जनता को विकास के पथ पर, राजस्थान के हर व्यक्ति का, हर वर्ग का विकास हो, इस भावना से इस बजट को आगे बढ़ाया जायेगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रदेश में या देश में जब तक हमारी कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, कानून का विषय एक ऐसा विषय है जिसमें समग्र विकास भी समा जाता है, उसमें शांति भी समा जाती है और प्रदेश में एक अच्छा माहौल भी बनता है। कानून व्यवस्था में अगर हम लोग काम करते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है, विकास को भी पंख लगते हैं। कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अपराध हो, अगर उस अपराध की घटनाओं को हम कम करते हैं तो प्रदेश में एक अच्छी व्यवस्था और लोगों को एक बेहतर वातावरण का अनुभव मिलता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि आज का युग नये दौर का युग है। आज के समय पर क्राइम एक ऐसी समस्या है और क्राइम को आज के समय में खतम करने के लिये हम सबको नये आधुनिक युग में जाना होगा, जिसमें फोरेंसिक साइंस का बहुत बड़ा रोल है। जिस प्रकार से आजकल साइबर क्राइम बढ़ा है, उस क्राइम को समझते हुए राजस्थान विधान सभा के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर इस पर हमको काम करना होगा। मेरा हमारी सरकार से निवेदन है कि हम आने वाले समय में हमारे इस प्रदेश में एक फोरेंसिक साइंस

यूनिवर्सिटी का भी निर्माण करें, जिसके माध्यम से हम इन अपराधियों को और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम करें।

msk/rtm/16.07.2024/1620/3a

अलवर जिले के अन्दर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जिला है, उस जिले के अन्दर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी रहते हैं, हिन्दू धर्म के लोग भी रहते हैं, हरियाणा से लगती हुई सीमा है और उत्तर प्रदेश से लगती हुई सीमा है। वहां पर आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है, वह क्राइम की। उस क्राइम के अन्दर भी सबसे बड़ा क्राइम, जिससे आज लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना न केवल अलवर व राजस्थान के लोगों को अपितु देश भर के लोगों को करना पड़ता है, वह है साइबर क्राइम जिसके अन्दर ऑनलाइन ठगी होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसका अलग से आईजी लेवल तक अधिकारी और इसका एक पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहां पर इसकी समस्या ज्यादा होती है, जैसे अलवर, भरतपुर, वहां पर इसके डीएसपी लेवल के कार्यालय हों और इनके लिए अलग से थाने का निर्माण हो, ताकि इन समस्याओं से आम व्यक्तियों को निजात मिले और अपराधियों को सज़ा मिले। इस प्रकार से भी हमको उसमें चिन्ता करनी चाहिए।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अलवर के लिए, हमारे तिजारा के लिए बजट में काफी घोषणाएं की हैं। जिसमें हमारे तिजारा की भी कई मांगों को उन्होंने पूरा किया है, जैसे कि तिजारा का जो सीएचसी हास्पिटल था, उसको उप जिला अस्पताल के रूप में उन्होंने बनाने की इस बजट में घोषणा की है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे तिजारा में नवीन कृषि मण्डी यार्ड बनाने की घोषणा भी की, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। हमारे भिवाड़ी के अन्दर जो आई.टी.आई. कॉलेज है, उसके अन्दर भी और बेहतर व्यवस्थाएं हों, उसके लिए भी बजट दिया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। देव नारायण भगवान जी के नाम से वहां पर एक छात्रावास बनाने की उन्होंने इस बजट के अन्दर घोषणा की, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन उसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि भिवाड़ी जो कि हमारे राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण शहर है, जो बहुत बड़ा रेवेन्यू राजस्थान को देता है और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में उद्योग हैं, वहां पर बी-टेक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, ताकि वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और उन बच्चों को अच्छा रोजगार भी आने वाले समय पर वहां पर उपलब्ध हो पाये।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी ईआरसीपी योजना जो कि आने वाले समय में हमारी राजस्थान की जनता की प्यास बुझायेगी। उस ईआरसीपी योजना के अन्दर जो हमारे अन्तिम जिले हैं, जैसे कि अलवर और अलवर के बाद अलवर की प्रत्येक विधान सभाएं, जो कि लास्ट में टेल के ऊपर आती हैं, अभी से उसी में निर्धारित हो, जो भी

पानी उपलब्ध हो, उस जिले की, उस विधान सभा की जनसंख्या के अनुसार उसको वह पानी मिले। क्योंकि मुझे पता है कि जब पानी की नहरें बन जाती हैं, पाइपलाइन डल जाती हैं, अगर पानी कम होता है तो जो शुरूआत के लोग होते हैं, शुरूआत का जिला आता है, वहां पानी आगे जाने से रोका जाता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि हर एक विधान सभा की जनसंख्या के अनुसार, भविष्य की जरूरत के अनुसार उसका पानी भी तय हो। जो भी उपलब्ध पानी हो वह उस विधान सभा को मिले, उस विधान सभा के लोगों को मिले, इस पर भी सरकार आगे बढ़कर काम करे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और आप सब के बीच में आज इस बजट के ऊपर चर्चा करने के साथ ही इस राजस्थान और हमारे प्रदेश के विकास में हम सब लोग मिलकर, माननीय भजन लाल जी के साथ मिलकर हमारे देश की जनता के, हमारे प्रदेश की जनता के विकास को आगे बढ़ायेंगे और हमारी पार्टी के द्वारा किये गये एक-एक वादे का पूरा करके राजस्थान को विकास के पथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।

अभी मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट के माध्यम से जो विपक्ष की बौखलाहट है, वह देखते ही बनती है। विपक्ष ने पिछले पांच वर्षों के अन्दर जो असत्य का ढोल बजाया और जनता ने ऐसा ढोल बजाया कि उसको विपक्ष में बैठा दिया। अभी इस बजट के माध्यम से जो घोषणाएं हुई हैं, उन घोषणाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को, हर एक समुदाय को और हर एक विधान सभा को मिलने वाला है। अंतर्मन से तो विपक्ष भी खुश है, इस बजट को देखकर, सुनकर, क्योंकि उनको भी विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, भजन लाल जी के भाव से हमारी सरकार हरियाणा, साथ में राजस्थान, गुजरात, चारों आस पास के प्रदशों में जो चली है, यह सरकार हमारे राजस्थान के विकास के एक-एक कार्य को पूरा करेगी। विपक्ष को यह चिन्ता आज से ही सताने लगी है, जो पहला बजट है, आने वाले समय में इस सरकार के जो चार बजट होने वाले हैं, उनमें राजस्थान के विकास को किस प्रकार से यह सरकार आगे ले जायेगी। इस प्रकार से ले जायेगी कि विपक्ष, जब चुनाव का समय आयेगा तो उस समय विपक्ष चुनाव से भागता हुआ नजर आयेगा, ऐसा प्रतीत आज आपकी दशा देखकर होता है।

मेरा आप सबसे कहना है कि इस विषय को आप सब लोग भी इस भावना से आगे बढ़ायें कि हमारा प्रदेश है। आज आप विपक्ष में हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आज हम पक्ष में हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिलकर अपने प्रदेश के हित में कार्य करते हुए इस बजट के माध्यम से अपने प्रदेश को एक विकसित राजस्थान के रूप में विकसित करते हुए राजस्थान का भला और राजस्थान की जनता का विकास एवं राजस्थान की जनता को एक सुखद जीवन का अनुभव हमारे प्रदेश में हो, इस प्रकार से हम सब लोग मिल-जुलकर काम करें। आप सबका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। पुनः अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। जय हो।

श्री अध्यक्षः श्री हाकम अली। पांच मिनट में खतम करिये। आपका तो नाम भी नहीं है। साढ़े चार बजे ये बोलेंगे।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत आभार कि बजट 2024-25 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उप मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी को कि उन्होंने बजट में फतेहपुर का नाम भी नहीं लिखा। मैडम, कम से कम नाम तो लिख देतीं, फतेहपुर भी राजस्थान में आता है, सीकर जिले में आता है। तो मुझे गर्व होता कि मेरे फतेहपुर का नाम बजट में लिखा गया है, फिर भी धन्यवाद कि आपने बजट पेश किया। माननीय मुख्य मंत्री जी आ चुके हैं। मुख्य मंत्री जी, नमस्कार। मेरा इतना ही निवेदन रहेगा कि जो काम पिछले पांच सालों में हमने बजट में करवाये थे, पिछले पांच सालों या लास्ट बजट में, वे काम चालू हैं, जो घोषणाएं हुई थीं, वे सारे के सारे चालू हैं। ...(व्यवधान)... सारे चालू हैं, वे पूरे कर देना। आप सुन लें।

श्री अध्यक्षः श्रीचन्द जी, लास्ट चार मिनट है, बोलने दें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आपके नेता को बोलना है, बीच में मत बोलो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः विराजें। फिर आपका नाम नहीं आयेगा।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): आप सम्माननीय हैं, सुन लें, सुनने की क्षमता रखा करें। जो काम चालू हैं वे पूरे कर देना, मैं तो यह मानूंगा कि आपने बजट में फतेहपुर के लिए बहुत कुछ दिया है। यह मैं मान जाऊंगा कि वे काम चालू रखना, उनको बन्द मत करना। अभी मेरे सुनने में आया है कि बजट के अभाव में सारे काम रुके पड़े हैं। उन कामों को आधा-अधूरा मत छोड़ना, भले ही आप उनका लोकार्पण कर देना, मुझे मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फतेहपुर की जनता के लिए अगर आप काम करके लोकार्पण करेंगे तो फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पूर्व में जब वसुन्धरा जी हमारी मुख्य मंत्री थीं, अपने दौरे पर फतेहपुर गयीं, वहां के विद्यार्थियों ने मिलकर मांग की कि, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, बहुत सालों से हमारी मांग है कि फतेहपुर के अन्दर एक महाविद्यालय खोला जाये। मुख्य मंत्री जी का जवाब क्या था? एमएलए दो, पहले। क्या जो एमएलए जीतकर आता है, क्या वह विधायक नहीं है? लेकिन मैं पूर्व मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे कहने पर फतेहपुर में एक नहीं, दो-दो महाविद्यालय खोले और वे आज संचालित हैं और 1300 से ज्यादा बच्चे उनमें पढ़ रहे हैं। उनके भवनों का काम भी चालू है। एक का तो भवन बनकर तैयार है, भामाशाह ने बना दिया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। एक का काम चालू है।...(व्यवधान)... पहले सुन लें। सुनने की क्षमता रखें। आपने अगर फतेहपुर में एक हैंडपम्प भी खुदवाया या एक हैंडपम्प की घोषणा की है, इन छह-सात महीनों में, तो आप मुझे बता दें कि हमने फतेहपुर में एक हैंडपम्प भी खुदवाया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा। इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए,

क्योंकि पांच मिनट ही दिये हैं।

माननीय, आप ही पीडीब्ल्यूडी मंत्री हैं, आप ही वित्त मंत्री हैं। मुख्य मंत्री भी आ चुके हैं। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप रिप्लाई में नाम ले देंगी तो। दो-तीन सड़कें बहुत ही क्षतिग्रस्त हैं। वही बची हैं, बाकी पिछले पांच सालों में हमने सब बना दीं। एक तो ठेडी से गोडिया होते हुए फतेहपुर, गोडिया बड़ा से एतमसर होते हुए देवास तक, सीकर-फतेहपुर हाई-वे से लेकर रिणाऊ चुआस बीबीपुर बड़ा तक। एक सड़क चुरू रामगढ़ हाई-वे से लेकर फदनपुर-दाणुंदा, नगरदास और रामगढ़ ढाणन तक, वह सड़क रिनुअल है। नई नहीं बनानी है, वह रिनुअल है, वह कर देना, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन के लिए निवेदन है कि चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, अगर कोई गलत बात हो, उसको गलत बताओ कि आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं, अगर कोई सही बात है तो उस पर धन्यवाद दें। हम तो सदन की पुरानी बात सुनते हैं जैसे कि माननीय पारीक साहब बैठे हैं, इनसे। कि पहले सदन चलता था, अध्यक्ष का आदेश होता था ऑर्डर-ऑर्डर, सारे सदस्य बैठ जाते थे। आज क्या हो रहा है? चाहे विपक्ष के हो, चाहे पक्ष के हो, इसलिए भी इसका थोड़ा ध्यान रखा जाए।

mdp/rtm/16.07.2024/16:30/3b

अध्यक्ष महोदय, कोई नया सदस्य अगर बोले तो उसका हौसला बढ़ाना चाहिए कि नया कोई जीतकर आया है, वह अपनी बात रखना चाहता है, अपने क्षेत्र की बात रखना चाहता है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः विराजिए। अगले बजट में। माननीय सभी सदस्यों से आग्रह है कि अभी सबसे पहले विपक्ष के नेता का भाषण होगा, इधर से अपेक्षा कर रहा हूं कि कोई टोका-टोकी नहीं करें और जब यहां पर वित्त मंत्री जवाब दें तो यहां से भी कोई व्यक्ति न बोले। सदन की गरिमा को बनाए रखें। एक पक्ष करेगा, फिर दूसरा पक्ष करेगा तो फिर सारा आज का, आपको जो कोई लक्ष्मी आ रही होगी, वह कहीं न कही रुक नहीं जाए, इसलिए निवेदन है कि शांतिपूर्वक दोनों का भाषण सुने। विपक्ष के नेता, श्री टीकाराम जी जूली।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जय संविधान। ...(व्यवधान)... जय संविधान।

श्री अध्यक्षः शांतिपूर्वक। मैं सबसे वापस निवेदन कर रहा हूं, keep silence, आपको इतना आग्रह किया, आपके नेता बोल रहे हैं। इधर से भी आग्रह है कि इनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष):

राम-राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख सहना होगा,
पहली चुनौती तो यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा
और मर्यादा का मतलब है, कुछ खास नहीं कर जाना है,
बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है!

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपनी बात पर आऊं उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सदन में जो ये चल रहा है, ये ऐसे मानेंगे नहीं। दो-तीन लोग हैं, उनको मंत्री बनाना पड़ेगा, मुख्य मंत्री जी उनको बना दो तो ये सदन अच्छे-से चल जाएगा। हालत ये हैं

श्री अध्यक्षः श्रीचन्द जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये आपकी नजर में आ गये हैं। एक तो आ गया है। आप कह रहे थे कि विपक्ष से कोई बोले तो सत्ता पक्ष नहीं टोके और सत्ता पक्ष से कोई बोले तो विपक्ष से नहीं टोके, परंतु आप बोलते हैं, ये कृपलानी जी जब भी टोकते हैं। इनका क्या करेंगे? मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद देता हूं वित्त मंत्री महोदय को, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दो घंटा बावन मिनट, 125 पेज लंबा वाचन किया और इतना लंबा बजट भाषण पढ़ने का आपने साहस दिखाया। मैं समझता हूं कि सदन ने इतना नीरस, दिशाहीन, निराशाजनक बजट कभी देखा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा शरीर है, वह पंचतत्वों से बनता है और उसी प्रकार से किसी भी सरकार का जो बजट है, बजट की जो आत्मा है, उसके भी पांच तत्व होते हैं, गरीब, किसान, मजदूर, महिला और युवा। ये बजट की आत्मा होते हैं। लेकिन आपने इसे अमृतकाल खंड का बजट बताया। सर्वजन हिताय की आपने बात की। आपने दस बिंदु रखे इसमें, आपका विजन रखा। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं आपकी प्रायोरिटी देख रहा था कि आपकी प्रायोरिटी क्या है? प्राथमिकता क्या है? अच्छी बात है, हर सरकार दस बिंदु पर, बीस बिंदु पर काम करती है, लेकिन प्राथमिकता होती है कि हमारी यह पहली प्राथमिकता है, यह दूसरी, यह तीसरी। आपकी पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता, तीसरी प्राथमिकता, आप देखेंगे तो कहीं इसमें बड़े उद्योगपति, कहीं बड़ी इंडस्ट्री, कहीं हवाई जहाज वाले, कहीं हैलिकॉप्टर वाले, कहीं हाईवेज, ये सारी बातें आपने लिखी, लेकिन मैं तो फिर भी धन्यवाद देता हूं कि आपने गरीब को 9वें नंबर पर रखा, गरीब को और 10वें नंबर पर जिसकी आवश्यकता आज पूरे राजस्थान को है और सबसे पहले अगर कहीं है तो भरतपुर को है, हमारी कानून व्यवस्था की, गुड गवर्नेंस की, उस गुड गवर्नेंस को आपने 10वें नंबर पर रखा है, वित्त मंत्री जी। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। जो आपका विजन है, वह 9वें और 10वें नंबर पर नजर आ गया। यही अंतर है आपकी सोच में और हमारी सोच में। हमारी सोच गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाली है। हमारी सोच किस प्रकार से गरीब का, मजदूर का भला हो, उस पर चलने वाली है और आपकी सोच, आपकी सोच किस प्रकार से अमीरों का भला हो, इसको लेकर चलने वाली है।

एक तरफ ये लोग कहते हैं कि ये जो टेम्पो में अड़ाणी, अम्बानी का धन जा रहा है, ये कांग्रेस के पास जा रहा है और मुझे बड़ा दु:ख है, अध्यक्ष जी, हमारे देश के प्रधान मंत्री जो अपने परिवार की शादी में शरीक नहीं होते हैं, इस देश के किसी गरीब के, विधवा की बच्ची के या किसी मजदूर के बच्चे की शादी में शामिल नहीं होते हैं, वह जिस पर आरोप लगाते हैं,

उसके बच्चे की शादी में शामिल होते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। ...(व्यवधान)... क्या विजन है? इन लोगों का विजन क्या है?

इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है,
तानों के शोर-शराबों में, सच कहने की ताकत है,
मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेकोगे,
तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।

मुझे बड़ा दु:ख हुआ कि सदन के अन्दर एक माननीय सदस्य ने गांधी जी को लेकर टिप्पणी की। मैं पूछना चाहता हूं कि गांधी जी की जीवनी में या सावरकर जी की जीवनी में, किस जीवनी में ये लिखा है कि गांधी जी की मुलाकात लंदन में 1909 के अन्दर सावरकर जी से हुई। किसी मुद्दे पर दोनों इकट्ठा हुए ...(व्यवधान)... दोनों के मत अलग-अलग थे।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। गोपाल जी, बैठिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सावरकर ने मांसाहार का समर्थन किया ...(व्यवधान)... और गांधी जी ने शाकाहार का समर्थन किया। किन बातों को लेकर आप चर्चा करते हैं? सिर्फ गांधी जी की फोटो लगाने से गांधी जी के विचार ग्रहण नहीं कर सकते। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। यह बात मैं कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिक्र करना चाहूंगा, हमारी सरकार के कामों की। याद दिलाना चाहूंगा जब माही डैम बन रहा था। जब माही डेम बनाने की कल्पना साकार हुई, उसमें मुख्य मंत्री जी का खुद का गांव, खुद का घर भी उस डैम के अन्दर आ रहा था, अपनी मिट्टी से, अपने मकान से, अपने गांव से किसे प्यार नहीं होता? कौन उसको छोड़ना चाहता है? लेकिन मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मेरे लिए प्रदेश जरूरी है। उन्होंने माही डैम बनवाया और आज माही डैम पूरे हमारे राजस्थान का एक हिस्सा, आज जो सबसे हरा-भरा है, उसकी अगर नींव कहीं से डली है तो वह हमारे समय से डली है।

मैं कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार से इंदिरा गांधी नहर हम लेकर आए। आज इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान को नया जीवन दिया है, राजस्थान को नयी उन्नति, नयी तरक्की दी है। आप ईआरसीपी की बात करते हैं, ईआरसीपी की बात किसने शुरू की? किसकी योजना है? किसकी घोषणा है? बीजेपी की, बीजेपी की घोषणा है?

Ans/rtm 16.40 3c 16.07.2024

मोदी जी दो बार अजमेर, जयपुर आकर घोषणा करके जाते हैं कि आप हमारे सांसदों को जिताइये, हमारी सरकार बनाइये, मैं ईआरसीपी लागू करुंगा। क्यों नहीं की? 25 के 25 सांसद, राजस्थान का जल शक्ति मंत्री और ईआरसीपी हमें नहीं मिली।

आप राजनीति की बात करते हो, हमें कहीं राजनीति से बाहर आना पड़ेगा। ईआरसीपी का प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। माननीया वित्त मंत्री जी, आपने 9 हजार 500 करोड़ की बात कही है, उसकी निविदा हमारे समय में निकली है। नवनेरा बांध बन चुका है, ईसरदा बनने वाला

है, एकदम कम्पलीट है। आपने किया है क्या, बता दीजिए। सिर्फ असत्य वाहवाही लेना, पीठ थपथपाना, उससे फायदा नहीं होगा।

अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि अलवर में हम लोगों ने गुलदस्ते लिए हैं। मैं समझता हूं, महाराज जी को जाना तो दिल्ली था, आप यहां ले आए, अब क्या करें। वह गुलदस्ते लेने सदन के नेता खुद रामगढ़ गए हैं। स्वागत करवाया कि हम ईआरसीपी पीकेसी लेकर आए हैं। अच्छी बात है लेकर आइये, मैंने भी अनुरोध किया। आप पूरा कीजिए, लेकिन हमें एमओयू तो बताइये। 6 महीने हो गए, एमओयू सदन में नहीं आया। आप एमओयू दिखाने से क्यों डरते हैं, ऐसा क्या है एमओयू के अन्दर कि आप राजस्थान की जनता के सामने लाने से डर रहे हैं। आप इसलिए डर रहे हैं कि आपने राजस्थान के हितो को मध्य प्रदेश के आगे गिरवी रख दिया। जो राजस्थान का पानी आना था, उससे आधे हिस्से में आप एमओयू करके आ गए, इसलिए आप एमओयू रखने से डर रहे हैं।

आप बात करते हो कि हम इंण्डस्ट्री को पानी देंगे, आप बात करते हो कि हम किसान को सिंचाई के लिए पानी देंगे। पीने के लिए भी पानी पूरा नहीं होगा, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। आप अपने जवाब के अन्दर बता देना, जब आप जवाब दें। हमें यह बात समझनी पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, रामगढ़ का बांध है, आपको पता होगा कि 1982 में जब एशियाई खेल हुए थे, इसके अन्दर नौकायान की प्रतियोगिता हुई थी। आज पूरे जयपुर की प्यास वह बांध बुझा सकता है। वित्त मंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि यह आपके पुरखों द्वारा बनाया हुआ है। क्या इस बांध के बारे में हमें नजर नहीं आता कि किस प्रकार से लोग इस बांध का दम घोंट रहे हैं? इसके अन्दर रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, प्लॉटिंग की जा रही है, इसके कैचमेंट एरिया को दबाया जा रहा है। हाईकोर्ट की कमेटी मानती है कि इस पर अतिक्रमण है, लेकिन हमारी सरकार नहीं मानती कि इस पर अतिक्रमण है।

मैं बजट पर कोई क्रिटिसाइज करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं बात कहना चाहूंगा। आज पूरे प्रदेश में लोगों की इस प्रकार की सोच है कि राजस्थान के अन्दर पानी की कमी है। हम सब भी यही मानते हैं। राजस्थान के अन्दर हर साल लगभग 170 बिलियन मिट्रिक क्यूबिक बरसात होती है। जितनी हमको जरूरत है, उससे डबल होती है। यह आश्चर्य का विषय है, हमारे पास पानी है,बरसात होती है लेकिन हम उसको सहेज नहीं पाते। हमारा पानी या तो अन्य प्रदेशों में बहकर चला जाता है या हमारे बांध है जिनमें हमने स्टोरेज किया है वहां से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। क्या हमने सोचा है कि इस पानी को किस प्रकार से बचाएं? क्योंकि राजस्थान के अन्दर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आज इंडस्ट्री हमारे यहां से क्यों जा रही है, क्योंकि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो क्यों नहीं हम इस पर सौलर पैनल लगाए। क्या हमारा इरादा इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि सौर ऊर्जा जो कि पूरे देश के अन्दर

भगवान ने गोड गिफ्ट दी है, उसका फायदा हम उठाएं। हम सौर ऊर्जा लगाएंगे, पानी का वाष्पीकरण बचेगा, अच्छी धूप आएगी, बिजली पैदा होगी और पानी बचेगा, इस पर अगर काम करना चाहे तो कर सकते हैं, मेरा सुझाव है बजट के अन्दर। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। मध्य प्रदेश में हो रहा है, आन्ध्र प्रदेश में हो रहा है। सरकार जितनी लागत लगाएगी, सरकार लगाए, कोई प्राइवेट देने की बात नहीं है, सरकार खुद लगाए, पांच साल में आपके पैसे की वापस पूर्ति हो जाएगी और प्रदेश की जनता को बिजली मिल जाएगी।

मुख्य मत्री जी, मैं कहना चाहता हूं, हम लोग एसी में बैठे हैं और गरीब की चर्चा कर रहे हैं। क्या हमने देखा है कि पिछले डेढ़-दो महीनों से लाइट कितनी आ रही है? सरकार बनने के बाद आप लोगों के सामने तीन चुनौतियां आई। पहली गर्मी की आई। आप बिजली नहीं दे पाए। गरीब का बच्चा आज भी झोंपड़ी में पढ़ाई के लिए तरस रहा है कि बिजली आएगी तो मैं पढ़ाई करुंगा। बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिला, बुजुर्ग किस परेशानी के अन्दर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमें नहीं दिखता? अगर हमें दिखता तो हमारे दिल के अन्दर से आवाज आती, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम लोगों को बिजली उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कांग्रेस ने गलत एमओयू कर दिया, कांग्रेस की गलत नीतियां रही। हम यहां एक दूसरे को कह सकते हैं। ठीक है, आप कांग्रेस का नाम ले दीजिए हम बीजेपी का नाम ले लेंगे, पर जनता की क्या गलती है, हम दोनों पक्षों को बराबर यहां बिठाया है, पिछले 30 वर्षों में, चाहे यह पक्ष हो या यह पक्ष हो। बनते तो हम ही आ रहे हैं, जनता की क्या गलती है? लेकिन फिर भी हम कोसते हैं, कांग्रेस आ गई तो बीजेपी को कोसती है और बीजेपी आ गई तो कांग्रेस को कोसती है। हम कोई ठोस निर्णय कब लेंगे? उन गांव में रहने वाले गरीब लोगों की क्या गलती है? उनको बिजली क्यों नहीं मिल रही। आप बिजली नहीं दे पाए। किसान को बिजली नहीं दे पाए, आप उद्योग को बिजली नहीं दे पाए, यह स्थिति आपकी बिजली की है। कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई मतलब नहीं। जनता परेशान है, पूछती है कि सरकार चला कौन रहा है?

बात डबल इंजन की थी, यहां तो ऐसा लग रहा है कि पूरी ट्रेन के अन्दर डिब्बे में होकर सारे इंजन ही इंजन लग गए हो। आधे इंजन इधर खींचते हैं, आधे इंजन इधर खींचते हैं। कोई कहता है मुख्य मंत्री जी चला रहे हैं। भले आदमी है, अच्छे आदमी है। मुझे खुशी है कि पहली बार जीतकर आने वाले व्यक्ति को मुख्य मंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन यह मौका बार-बार नहीं मिलता। आपको मौका मिला है, आपको अपनी परफोर्मेंस साबित करनी पड़ेगी। मुख्य मंत्री जी, आपके मंत्री जी कहते हैं कि हमारी नहीं चल रही।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): किसने कहा? नाम बताइये ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सब मत पूछो। एक-एक पूछो, मैं सबका जवाब दूंगा। यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई। यही जोगाराम जी, मुख्य मंत्री जी आप जोधपुर गए थे, आप इनसे मिले नहीं, इन्होंने कहा कि एक-एक लाख रुपये की थैली दे रहे हैं मिल रहे हैं ...(व्यवधान)... और कार्यकर्ता को नहीं मिलने दिया जा रहा। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): वह तो उधर है ...(व्यवधान)...रोज ही मिलते हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यही कह रहे थे कि मंत्रियों की नहीं चल रही। ...(व्यवधान)... और कौन कहेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। दैनिक भास्कर अख़बार, तारीख और बता दूंगा। ...(व्यवधान)... यही नहीं, ब्यूरोक्रेसी में भी चल रहा है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी चला रही है। अब ब्यूरोक्रेसी में भी कौन चला रहा है इस बात का भी बड़ा प्रसंग है आज प्रदेश में।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): यह बात तो डोटासरा जी कह चुके, कोई नई बात बताओ।...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): तो आपको यह पता है, यह देख लो। ...(व्यवधान)... आपके सब मंत्री एग्री हैं। आपके मंत्री एग्री हैं।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): नई बात बताओ, डोटासरा जी कह चुके ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपका कोई मंत्री इस्तीफा दे देता है। आप यह बता दीजिए कि किरोड़ी जी ने इस्तीफा क्यों दिया? दो-दो मंत्री आपके जा चुके हैं। एक तो अग्निवीर हो गए टी.टी. जी, पहले ही उसके अन्दर। दूसरे अग्निवीर किरोड़ी मीणा जी हो गए। चार साल भी नहीं पकड़ रहे। एक मंत्री की तो आपने गाड़ी ही छीन ली। ऐसा क्या हुआ, डिपार्टमेंट हलका दे दिया, क्या हुआ पता ही नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह बजट पर भाषण है? ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अब वह मंत्री जी क्या करते हैं, मंत्री जी जाकर ट्रैक्टर पकड़ लेते हैं कि अवैध खनन का ट्रैक्टर है। मुख्य मंत्री जी, इससे बुरी स्थिति क्या होगी, रिकार्ड निकलवाकर देख लेना, मंत्री ने जो ट्रैक्टर पकड़ा डीएफओ ने उसको अगले दिन छोड़ दिया ...(व्यवधान)... यह गलत है तो आप पूछ लेना।

VPS-RTM-16.07.2024-16.50-3d

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): आज भी वह थाने में जब्त है। आज भी वह थाने में जब्त है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्रीजी, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम कुछ अच्छा सोचे, कोई नया विजन हमारा होना चाहिए। मैं आप पर आरोप लगाऊं, आप मेरे पर आरोप लगाये तो इनसे काम चलने वाला नहीं है।

आज पेपर लीक की बहुत बात हुई है। पेपर लीक पर भी मैं आऊंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज मैं जो यहां पर हूं, मैं भी एक साधारण दलित परिवार से हूं, मेरे पिताजी भी मजदूरी करते थे, मजदूरी करते हुए सेना में गये, फिर वहां से आकर समाज सेवा में आये।

आपके पिताजी भी किसान हैं, आज भी है और मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं क्योंकि यह एक अजीब सहयोग है कि आपके पिताजी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमारे अध्यक्षजी की पत्नी भी एडमिट हैं, तो मैं पूरे सदन की तरफ से भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक यू-ट्यूब पर मैंने देखा था। कोचिंग में एक लड़की पढ़ती थी। वह लड़की बहुत ही इंटेलिजेंट थी और लगातार कोचिंग में आती थी लेकिन एक दिन वह जब बच्ची आयी तो उसके बाल कटे हुए थे क्योंकि हमारे समाज के अन्दर लड़कियां बाल नहीं कटवाती है। उसके टीचर ने पूछा कि बेटा, ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने बाल कटवा लिये? उस बच्ची ने यह कहा कि, सर, मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं कुछ बनना चाहती हूं, मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं और मैंने इसीलिए बाल कटवाये हैं ताकि कोई लड़का मुझसे शादी नहीं करे। यह जो हमारी बालिकाएं हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, जो हमारे युवा हैं, उनके अन्दर का जज्बा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस लेवल पर वे मेहनत करते हैं। यह समस्या आपके समय भी थी, हमारे समय में भी थी। मैं अभी यह पढ़ दूंगा। वसुन्धराजी के समय में हम से एक पेपर लीक ज्यादा हुआ था। आज गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, भारत सरकार के नीट का, कौनसा ऐसा पेपर है जो लीक नहीं हो रहा है? हम आपके लिए कह देते हैं और आप हमारे लिए कह देते हैं तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या हम सब लोग जो यहां पर चुन कर आते हैं, कोई इस प्रकार का प्लान नहीं बना सकते कि भविष्य में पेपर लीक नहीं हो? कानून चाहे हमने बनाया हो, देश के अन्दर सबसे मजबूत कानून राजस्थान ने बनाया है। पेपर लीक करने वालों को आजीवन कारावास, दस करोड़ रुपये का जुर्माना, सरकारी कर्मचारी यदि उसमें लिप्त हो तो नौकरी से बर्खास्त, पूरे देश में सबसे पहला कानून हमने बनाया है। भारत सरकार ने भी बनाया है पर वह राजस्थान के मुकाबले दस परसेंट ही है लेकिन हम इस चीज पर नहीं जाना चाहते कि कोई किसी पर आरोप लगा दे, कोई किसी पर आरोप लगा दे। हमने भी डेढ़ सौ लोगों को अरेस्ट किया, आपने भी सौ, डेढ़ सौ लोगों को अरेस्ट किया। यह जो माफिया है, अपन क्या है मछलियों को पकड़ रहे हैं और मगरमच्छ जो हैं वे खुले घूम रहे हैं। इस दिशा में अपने को काम करने की जरूरत है। हम सब लोग मिलकर काम करें। ...(व्यवधान)... यही विजन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और यही आपका ...(व्यवधान)...

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): ढाई हजार बीघा जमीन किसके राज में बेची गयी थी, किसके राज में आवंटन हुआ था? ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यही इस सरकार की नीतियां हैं। अब आपका डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: हो गया। आप क्यों खड़े हो? आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको एक दर्द यह हो गया कि इधर हारकर भी कैबिनेट हुई है और जीतकर भी इनको स्टेट का ही दर्जा मिला है, यह चक्कर पड़ रहा है इधर। इस चीज का समाधान या तो आप कर दो नहीं तो पंडितजी बहुत परेशान हैं, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, माननीय मंत्रीजी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बच्ची की कहानी भी इसीलिए बतायी कि आज समय की यह जरूरत है और यह पेपर लीक आज से नहीं हो रहा है, पता नहीं कितने समय से हो रहा है। जब एस.ओ.जी. गयी है, लोगों को उठाया है, पता नहीं कब-कब से कौन-कौन लोग इसके अन्दर शामिल रहे हैं और यह हम एक दूसरे पर आरोप लगा ले लेकिन पेपर लीक करने वाले लोग कौन हैं, यह पकड़ में आना बहुत ही जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा। एक सुझाव और है मेरा कि जो गरीब बच्चे हैं, आज इंटरनेट का प्रयोग बढ़ गया है, सारी चीजें इंटरनेट से जुड़ी है तो क्या हमने यह प्लान किया है कि हम गरीब बच्चों को भी इंटरनेट कैसे दे? हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना शुरू की, आप लोगों ने बीच में उसको बंद कर दी, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि गरीब को भी क्योंकि वह मोबाइल जो है, वह इंटरनेट फ्री के साथ दिया था तीन साल के लिए तो उन बच्चों तक, उस परिवार तक इंटरनेट कैसे पहुंचे? आज अमीर आदमी तो डाटा डलवा लेता है। अभी अम्बानी की एक शादी हुई है, एक शादी में ही 499 पार कर दिया और दूसरे बच्चे की शादी होगी तो हजार रुपये जायेगा, तो यह बोझ तो अपने पर ही आना है। यह वह ही जिओ है जो हमें फ्री दिया गया था। हमें फ्री दिया गया। जब फ्री लांच हुआ तो मैंने नहीं लिया, फिर छह महीने और बढ़ाया तब भी मैंने नहीं लिया, फिर छह महीने और बढ़ाया तो मैंने कहा कि अब तो लेना पड़ेगा क्योंकि सब लोगों ने ही जिओ ले लिया और उसके बाद जैसे ही छह महीने पूरे हुए फिर 99, फिर 199, फिर 299, फिर 399, अब 499, कुछ समय में 999 और पता नहीं कितने पैसे बढ़ेंगे और गरीब की जेब कटेगी और दिन भी घटा दिये, यह बात मैं कहना चाहता हूं। तो इसलिए इस विषय पर मैं समझता हूं कि कोई न कोई बात हमें समझनी पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कोटा के अन्दर जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं वे किसके बच्चे हैं? वे हमारे ही बच्चे हैं। एक मजदूर, एक किसान, एक समय का खाना नहीं खाता है ...(व्यवधान)...

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा में बच्चों की डेंसिटी देखी जाये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जिस प्रकार से रोजाना, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कोटा के अन्दर कोई न कोई बच्चा सुसाइड नहीं करता हो, तो हम किस दिशा की ओर

जा रहे हैं? आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): कोटा में दो लाख बच्चे पढ़ते हैं। आप कोटा को बदनाम न करें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आज जिस प्रकार से कोचिंग संस्थाओं ने उसको व्यवसाय बना लिया और व्यवसाय ही नहीं जब तक शरीर के अन्दर खून की आखिरी बूंद नहीं रह जाये तब तक वे उस बच्चे को निचोड़ना चाहते हैं, उसके अभिभावकों को निचोड़ना चाहते हैं। तो क्या सरकार इस पर कानून नहीं बना सकती कि जिस प्रकार से ये कोचिंग, मैं यह देख रहा था कि साउथ के अन्दर, तमिलनाडु के अन्दर बैन करने का इरादा सरकार ने कर लिया है तो क्या राजस्थान सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि खुद इस प्रकार का मॉडल बनाये कि ये जो मगरमच्छ बैठे हैं, ये जो लूट रहे हैं जनता को और बच्चों पर फालतू का जो लोड पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, उससे उन बच्चों को बाहर निकाला जा सके, इस दिशा में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए? हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि कुछ लोग मिले हुए हैं जो चाहते नहीं हैं कि यह धंधा बंद हो। गरीब का बच्चा किस प्रकार से अच्छी एजुकेशन ग्रहण कर सकता है? हमने यह तय किया, उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने दी है, हमने कॉलेज खोले हैं, हमने उन बच्चों को विदेश पढ़ने की व्यवस्था की है। आज किस प्रकार से जो व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं, हमें यह समझना पड़ेगा।

मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि-

मुझे रहज़नों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है।

तू इधर उधर की न बात कर ये बता कि क़ाफ़िला क्यूं लुटा।

आप 25 से 14 पर क्यों आये? 25 से 14 पर क्यों आये, इसका भी जवाब दे देना। यह जो बातें कर रहे हो न, यह जनता एक-एक दिन का हिसाब लेगी आप लोगों से कि किस प्रकार से यहां आकर आप जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई पर यहां पर ऐश कर रहे हैं और जनता की आवाज उठती है, जनता का जो मुद्दा उठता है, उसका आप समर्थन नहीं करते हैं। इस राजस्थान की जनता आप लोगों से यह पूछेगी।

मैं यह कहना चाहूंगा कि 9 Green Field Expressways की बात की गयी है। कालीचरणजी, यह जब पढ़ा गया तो मैं भी सन्न रह गया कि क्या है? इसके लिए बजट कितना है? 30 करोड़ रुपये। कब आयेगा? क्या ऐसा तो नहीं है कि इन हाईवे पर लोगों की जो जमीन है, उसकी रेट बढ़ाने के लिए घोषणा कर दी हो डी.पी.आर. बनाने की? इस पर पैसा कितना लगेगा और क्या राजस्थान के पास उतना पैसा है? यह बात मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि वे यह बता दें कि 2750 किलोमीटर का आप जो नेशनल हाईवे, जो आप ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हो, उतना पैसा आपके पास है या नहीं है? यह बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): है और बनाएंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। आप पहले यह कह रहे थे कि हम 70 हजार नौकरी देंगे, तो क्या दे दी? सात महीने में 70 हजार नौकरी की विज्ञप्ति जारी की हो और नौकरी का नियुक्ति लेटर दिया हो तो मुझे आप बता दीजिए। ...(व्यवधान)...

SSY/RTM/16.07.2024/17.00/3e

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नियुक्ति लेटर दे दिया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हां, वह हमारे वाले हैं। आपके ध्यान नहीं रहा। मेरा जो क्वेश्चन है वह आप समझ नहीं पाये। आपने विज्ञप्ति निकाली हो और नियुक्ति दी हो, मैं तो वह पूछ रहा हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम 3 हजार दे चुके हैं ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): विज्ञप्ति कब जारी हुई? विज्ञप्ति कब जारी हुई?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 43 हजार हम नवम्बर तक कर देंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): विज्ञप्ति कब जारी हुई? जोगाराम जी, मंत्री जी ने कोई बात कही है तो बड़ी जिम्मेदारी से कही होगी। मैं विज्ञप्ति जरूर चाहूंगा। लेकिन मैं एक सबसे बड़ी बात कह रहा हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): दे चुके हैं। लैब टेक्निशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर जोइन कर चुके हैं। प्लीज करेक्ट अपना पेपर।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): थैंक यू। थैंक यू मंत्री जी।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने 4 लाख भर्तियों की बात की है। 4 साल में 4 लाख पोस्ट खाली हैं क्या? जवाब दे देना मुख्य मंत्री जी। मंत्रियों की जरूरत नहीं है। आप जवाब दे देना, 4 लाख पोस्ट खाली हैं क्या? 8 लाख टोटल नौकरियां हैं राजस्थान के अन्दर। 4 लाख कहां से दे दोगे? युवाओं को क्यों गुमराह कर रहे हो? गुमराह करने की आदत हो गयी है। पहले कहा 70 हजार, फिर कहा 1 लाख दे देंगे, फिर कहा 4 लाख दे देंगे।

हमारे यहां गांवों के अन्दर एक कहावत है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): संकल्प लिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके नेता सक्षम हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा, ऐसे जो लोग काम करते हैं उनके लिए कहावत है। किसी से कोई 100 रुपये मांगने गया। तो उसने कहा कि कल आना 200 ले जाना। वह खुशी-खुशी से वापस आ गया। अगले दिन फिर गया कि 200 दे दो, तुम कल आना 500 ले जाना। वह फिर वापस आ गया। अगले दिन फिर गया तो कहा कि 500 क्या लेगा, तुम 1000 ले जाना। कल आ जाना। वह फिर वापिस आया, चौथे दिन फिर गया, तो कहा कि 1000 का क्या करेगा, तुम 5000 लेना, अगले सप्ताह आ जाना। वह अगले सप्ताह फिर गया तो कहा, 5000 का क्या करेगा तुम तो पूरा 10000 ले जाना।

अगले महीने आ जाना। अब वह बात हो रही है।

अध्यक्ष जी, 70 हजार नहीं, तुम एक लाख लेना। एक लाख नहीं, 4 लाख ले लेना।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बजट पर भाषण है या किस्से, कहानियां सुनाने की संध्या है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं बजट पर ही आ रहा हूं। अभी भूमिका है। बजट पर आऊंगा।

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब मिल जायेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जब बजट पर आऊंगा तो कान के कलिले झड़ जायेंगे। चिंता मत कीजिये। अब मैं बजट पर आ जाता हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अब बजट पर आ रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सबसे जरूरी जो दस्तावेज है वह बजट होता है। लक्ष्मी आने को हम बड़े सकारात्मक रूप से लेते हैं। लेकिन आपका जो पहला पन्ना है वह नकारात्मकता से भरा हुआ है। हम लोगों के प्रति, कांग्रेस के प्रति, पिछले शासन के प्रति जो आपके मन के अन्दर मैल है, वह सब पहले पन्ने पर आ गया। मैं समझता हूं कि अब यह जो आ गया तो आ गया, लेकिन आगे इस चीज पर ध्यान मत देना।

अगला जो बजट आये, ...(व्यवधान)... इनके कोई स्प्रिंग लग गई कि क्या चक्कर है? जोगाराम जी, बैठते ही नहीं हैं। पूरा दिन ही इतना बोलते हो। अब तो बैठ जाओ।

श्री अध्यक्ष: आपसे विशेष प्रेम है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं,यह प्रेम तो इनका सबसे है। सभी पर ही खड़े होते हैं। इन्होंने कहा कि पिछली जो विरासत हमें मिली, वह विरासत में हमें कर्जा, देनदारियां और पता नहीं क्या-क्या मिला। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारी नीतियां गलत थी, हमारा प्रबंधन गलत था तो आपने हमारी टीम को क्यों रखा है? जिस टीम ने हमारे समय में बजट बनाया, वही टीम अब बजट बना रही है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब आ जायेगा। हो गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप सुनिये,

मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है।
बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है।
मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशों से कब तक तोड़ोगे,
मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, बैठिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हमने हमारी अर्थव्यवस्था आपको सौंपी तो देश के अन्दर सैकण्ड नंबर की अर्थव्यवस्था राजस्थान की थी। आपको अगर आंकड़ों का ध्यान नहीं हो, पता नहीं हो तो विभाग से मंगवा लेना। वह आपको बता देंगे।

2018-19 में जो आपके बजट का साइज था वह 2,12,275 करोड़ रुपये का था। 2023-24 में जो हमारे समय का बजट था वह 3,90,856 करोड़ रुपये का बजट था। यानी की 84 परसेंट हमने बढ़ोतरी की थी। यह मैं आपको बताना चाहूंगा।

जीएसडीपी की हम बात करें तो 2018-19 में 9,11,519 करोड़ रुपये थी और 2023-24 में 15,28,385 करोड़ रुपये थी। यानी की 73 परसेंट की बढ़ोतरी जीएसडीपी के अन्दर हमने की है। जीएसडीपी की जो ग्रोथ रेट है, आर्थिक विकास दर, जो 2018-19 में 2.37 परसेंट थी और 2021-22 में जो मैं बता रहा हूं 11.04 परसेंट थी। जो कि देश में दूसरे स्थान पर थी। 2023-24 में 12.56 परसेंट है। यह आंकड़े आप चाहो तो दुरुस्त कर लेना।

प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो 98698 रुपये यानी की बढ़ोतरी वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर 2017-18 के अन्दर और 2023-24 के अन्दर 1,67,064 रुपये बढ़ोतरी वाले राज्यों में 9वें स्थान के अन्दर थी। यह अंतर था आपके समय में और हमारे समय में। आप बता देना। पिछले 5 सालों में देश की प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ी है, वह 6.08 परसेंट है, जबकि राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है वह 8.24 परसेंट है। अब बता दीजिये, आप जवाब दे देना।

2013 के अन्दर प्रदेश पर 1.47 लाख करोड़ का कर्जा छोड़कर हमारी सरकार गई थी। 5 साल में बीजेपी ने प्रदेश पर जो कर्ज है, उसको दुगुना करके 3.25 लाख करोड़ रुपये कर दिया था। हमारी सरकार में 2013 में स्टेट जीएसडीपी का केवल 23.5 परसेंट का कर्ज था। जिसे आपकी सरकार ने 2018 में बढ़ाकर 34.16 परसेंट कर दिया था।

अब बजट पर आ जाओ। बता रहा हूं। सुन लो। कोविड जैसी बीमारी, भयंकर बीमारी जिसका प्रबंधन राजस्थान में पूरे देश के अन्दर बेस्ट रहा। खुद प्रधान मंत्री मोदी जी ने राजस्थान के मुख्य मंत्री की पीठ थपथपाई। यह हमारा प्रबंधन था कोविड के अन्दर। भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश और दुनिया के अन्दर एक नजीर बना। वह भीलवाड़ा मॉडल कहां से आया? हम लोगों ने दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हो ना कर्जे की, केन्द्र सरकार पर 2014 में, 70 साल का जो कर्जा था वह 58 लाख करोड़ रुपये था। जैसे ही नॉन बायोलॉजिकल प्रधान मंत्री, +++ प्रकट हुए, तो 160 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा इस देश पर कर्जा कर दिया।

आपकी पिछली सरकार में 5 साल का पूंजीगत व्यय 80,629 करोड़ रुपये रहा। जबकि हमारी सरकार में पूंजीगत व्यय 1,20,500 करोड़ रुपये के लगभग रहा। यह आपकी और हमारी सरकार के अन्दर अंतर है। हमारी सरकार ने 2023-24 में पूंजीगत व्यय के लिए 38,061 करोड़ रुपये रखा। आपकी सरकार खर्च तक नहीं कर सकी। पूंजीगत व्यय में 8 परसेंट की कमी आई। पूंजीगत 34,844 करोड़ रुपये ही हुआ। इसका मतलब है कि आपकी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास में पूरे पैसे नहीं खर्च कर पायी।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा कि यह बजट पर जो घोषणा की है, वित्त

मंत्री जी जब आप रिप्लाई दो तो इनका बजट प्रावधान और बता देना। जितनी घोषणाएं आपने की हैं, उसमें बजट के अन्दर कितना पैसा रखा है? यह भी सदन की मेज पर आ जाये। यह मैं पूछना चाहूंगा।

हमारे कोविड रहा, ऐसी परिस्थितियां रहीं, उसमें समय में भी जो राजकोषीय घाटा था वह अधिकतम 61,515 करोड़ रुपये था। हमने परिस्थितियां सुधारी। आप तो होटल में नहीं जा रहे, आपका क्या हाल है? 2023-24 के बजट में 62,700 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा प्रस्तावित था। वह भी आप मैनेज नहीं कर पाये।

Spp/Rtm/16.7.2024/17.10/3f

आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। मुख्य मंत्रीजी पिछली बार पूछ रहे थे कि इतना बड़ा घाटा कर दिया। मुख्य मंत्रीजी, आपने तो 70 हजार करोड़ रुपये का प्रस्तावित किया है, 70 हजार करोड़,तो खुद भी पढ़ लिया करो इधर आरोप लगाने से पहले। आज तक के इतिहास में राजस्थान जब से बना है तब से लेकर आज के समय में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा है तो आज के इस बजट के अन्दर है। यह तो एस्टीमेट है। जब रिजल्ट आयेंगे न तब पता चलेगा कि यह घाटा कहां से है। यह आपकी आर्थिक नीति है। यह बात मैं कहना चाहूंगा।

आपने क्या दिया है, विभागों की बात कर लें। आपने सबसे पहले अगर किसी का नुकसान किया है तो इस किसान का किया है। ग्रामीण विकास के अन्दर आपने जो बजट काटा है वह किरोड़ी जी का क्यों काटा है? वह किरोड़ी का नहीं है, वह बजट इस राजस्थान की जनता का है। ग्रामीण विकास के अन्दर जो 2023-24 में बजट में था 10.79 प्रतिशत, आपने इस बजट में रखा है 9.65 प्रतिशत, तो किरोड़ी जी से दुश्मनी है तो राजस्थान की जनता से क्यों निकाल रहे हो? यह बात मैं आपको पूछना चाहता हूं।

उद्योग पर जो पिछला बजट था 1.12 प्रतिशत था और अब आपने रखा है 1.05 प्रतिशत। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर पहले 3.63 प्रतिशत था अब आपने रखा है 3.54 प्रतिशत, यह आपका बजट है। आर्थिक सेवाएं हमारे समय में बजट था 3.54 प्रतिशत, आपने रखा है 2.21 प्रतिशत, कहां तक बचाओगे, कहां तक छिपाओगे, कहीं भी नहीं बच सकते, आप किसी भी एरिये के अन्दर आ जाओ। आपने हर जगह कमी ही कमी की है। हमने पिछली बार सब विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर 10-10 करोड़ रुपये की सड़कें दीं। पहले साल में 5 करोड़, दूसरे साल में 10 करोड़, तीसरे में 10 करोड़ और चौथे में 10 करोड़ और आपने 10 करोड़ से घटाकर उसको 5 करोड़ कर दिया। ..(व्यवधान).. माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, बिराजें। ...(व्यवधान)..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात आज दसवीं बार कह रहा हूं कि इस सरकार के मंत्रियों का जो व्यवहार है, ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष के विधायक हों ऐसा व्यवहार यहां के मंत्रियों का है। ...(व्यवधान).. यह जवाब दे देंगी वित्त

मंत्रीजी और 29 तारीख को मुख्य मंत्रीजी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से उछलते हो न, यह उछलने से नंबर नहीं बढ़ेंगे। तथ्यों पर जवाब देना है, आप जवाब दे देना। एक भी पाइंट अगर गलत बोला हूं तो जवाब दे देना, यह बात मैं कहना चाहता हूं। हमें उम्मीद थी कि PWD की मंत्री वित्त मंत्री भी हैं। वित्त की सारी पॉवर हैं। पैसा भी सड़कों में खूब दिया है। अन्य विभागों से ज्यादा बजट सड़कों पर लिया है तो विधायकों को जो 10 करोड़ के काम दे रहे थे, हमें उम्मीद थी 20 की, आपने उल्टा 5 करोड़ कर दिया। मुख्य मंत्रीजी इसमें बढ़वाना, इसमें सिफारिश करना वित्त मंत्रीजी से। अब पता नहीं मानेंगी कि नहीं, यह तो आप जानो। बाहर बहुत चर्चाएं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा 2023-24 में जो कृषि विभाग का अपने बजट रखा है, यह कह रहे हैं न किसान की बात मैं करता हूं, 2023-24 में था 3,306.97 करोड़ और आपने जो प्रस्तावित किया है 3,203.39 करोड़। आपने कृषि का भी घटा दिया। कृषि विकास योजना का था 325 करोड़, आपने कर दिया 112.52 करोड़, कृषि विस्तार मिशन का था 180.20 करोड़, आपने कर दिया 142.28 करोड़, कृषि विकास योजना का 43.35 करोड़, आपने कर दिया 25 करोड़। कुसुम योजना का था 300.20 करोड़, आपने कर दिया 299.16 करोड़। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का था 124.30 करोड़, आपने कर दिया 114.76 करोड़। राज्य वित्त आयोग का जो पंचायती राज संस्थाओं का अनुदान जाता था, जो पंचायतों को कमजोर करने का काम कर रहे हो न, यह आने वाले समय में आप लोगों के लिये बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित होगा। आपने 5 हजार करोड़ को घटाकर 4 हजार करोड़ कर दिया। एक हजार करोड़ रुपया आप पंचायतों का खा गये, सरपंचों का आपने कम कर दिया। पांच कृषि विश्वविद्यालयों के लिये हमने 469.49 करोड़ रखा था, आपने 397.35 करोड़ कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गौशाला अनुदान हमने सबसे पहले हमारी सरकार ने शुरू किया था। उस समय गहलोत जी मुख्य मंत्री थे। हमने तीन महीने का अनुदान दिया था। वसुन्धरा जी आयीं तो उन्होंने छह महीने का अनुदान दिया। हम वापस सरकार में आये तो हमने नौ महीनों का अनुदान दिया। अब उम्मीद थी और आप तो गौमाता का बहुत जयकारा लगाते हो, नौ महीने के अनुदान को बारह महीनों तो करोगी। आपने नहीं किया। आपने यह क्यों नहीं किया? उम्मीद थी कि इसको आप बढ़ायेंगे। अभी भी आपके पास समय है, मौका है आप बढ़ाइये। गौमाता हम सबकी बहुत ही पूजनीय है।

आपने स्वच्छ भारत मिशन का जो बजट है, वह पहले हमारे समय में 1145.65 करोड़ था, उसको घटाकर आपने एक हजार करोड़ कर दिया। जिला परिषदों की जो सहायता हम 341.48 करोड़ देते थे, आपने 316.77 करोड़ कर दिया। मुख्य मंत्री मनरेगा के अन्दर हम 25 दिन एक्स्ट्रा देते थे। आपने 25 दिन का कोई जिक्र नहीं किया। आप नहीं देंगे उनको। गरीबों को इससे रोजगार मिल जाता था, पर गरीब तो आपके नवें पायदान पर हैं। मनरेगा का जो विशेष कार्यक्रम चलाया था, उसमें 200 दिन का था। हम उसमें 600 करोड़ दे रहे

थे, आपने 60 करोड़ रुपया दिया है।

बिजली की दरें नहीं बढ़ाने के लिये जो अनुदान था, वह 23,369 करोड़ रुपये हम देते थे। आपने 17,551 करोड़ रुपये रखे हैं। HPCL रिफाइनरी के लिये हमने 1244 करोड़ रुपये रखे थे, आपने 1086 करोड़ रखे हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिये हमने 1324 करोड़ रुपये रखे थे, आपने तो आधे से भी कम कर दिया और 608 करोड़ रुपये आपने रखे हैं।

विशेष योग्यजन निदेशालय को 228.23 करोड़ रुपया जो मिलता था, उसको भी आपने घटा दिया 187.15 करोड़ रुपये कर दिया। हम 5 हजार स्कूटी देते थे। आपने 2 हजार कर दी। जो दिव्यांगजन हैं, वह धन्यवाद देते थे मुख्य मंत्रीजी को, कि आपने स्कूटी नहीं हमें पैर दिये हैं। मुख्य मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है इस प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिये आप स्कूटी की संख्या 5 हजार से 2 हजार करने की जगह 5 हजार से 10 हजार कीजिये। आपको उस तबके की दुआएं मिलेंगी जिसको सहारे की जरूरत होती है। वह सहारा हम दे सकते हैं और हमें देना चाहिये। यह बात मैं आपसे कहना चाहूंगा।

अल्पसंख्यक विकास के लिये भी आपने 482.52 करोड़ था, उसको 463.52 करोड़ कर दिया। सूचना प्रौद्योगिकी, जिस आई टी की हम बात करते हैं, उसका बजट आपने कम कर दिया। हमारे समय में 5365 करोड़ रुपये था, आपने उसको घटाकर तीसरे हिस्से में ले आये 1748 करोड़ रुपये आपने इसके लिये रखा है, यह बात मैं कहना चाहूंगा। हमारी सरकार का जो मिशन था, जो 10 बिन्दु थे - किसान, महिला, जवान, नौकरीपेशा, इन सब लोगों के लिये रखे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप OPS को जारी रखेंगे कि नहीं रखेगे? एक सिम्पल सा सवाल है, आप जवाब दे दीजिये। आप OPS को जारी रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, सदन को क्यों गुमराह कर रहे हैं? माननीय सदस्य क्वेश्चन लगा रहे हैं पर सरकार की तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है। यह तो आप बता ही सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पर्ची आयेगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पर्ची नहीं आयेगी। इसकी पर्ची नहीं आयेगी, यह समझकर चलना। ऊपर वाले इस पर्ची के खिलाफ हैं। भारत सरकार की वित्त मंत्री OPS के खिलाफ हैं। वह नहीं चाहती कि OPS लागू हो। भारत सरकार नहीं चाहती कि OPS लागू हो और मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, यहां भी बैठे हैं, वह यह चाहते हैं कि OPS लागू हो। चाहते हो तो एक बार मुस्करा देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ में किसानों ने सहकारी बैंकों से जो कर्जा लिया, आप उनकी जमीन नीलाम करना चाहते हैं? क्यों चाहते हो? हमने 15 हजार करोड़ रुपये का किसानों का कर्जा माफ किया। नहीं किया हो तो वित्त मंत्रीजी बता देंगे। यह जिस प्रकार से आप लोग बोलते हो 6 हजार करोड़ रुपये आपके वसुन्धरा जी के समय के हमने दिये और 9 हजार करोड़ रुपये हमने हमारे समय के दिये। आप किसान की बात करते हो। आपने किसान की आमदनी दुगुनी करने की बात कही। किसान की आमदनी दुगुनी कर दी क्या? सुन लें पंडित जी-

अभी सूरज नहीं डूबा
जरा-सी शाम होने दो
मैं खुद लौट जाऊंगा,
मुझे नाकाम होने दो।
मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना,
मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम
पहले मेरा नाम तो होने दो।

Jyg/rtm/16.07.24/17.20/3g

पहले ही क्यों चिल्ला हो, बात तो पूरी होने दो। ..(व्यवधान)... हमारी सरकार में किसान ऋण राहत आयोग बना। आपने उसका आगे क्या किया, बता दीजिए। हम यह सोच रहे थे कि जो हमारी योजनाएं थीं, प्रदेश के लिए, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, आप कह रहे हो कि चिरंजीवी की जगह हम आयुष्मान भारत ले आए। चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपये का इलाज, 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्लस ऑर्गन ट्रांसप्लांट अलग से, यह हमारी योजना थी। ..(व्यवधान)...

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कितने लोगों के लिए किया?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान के लगभग सारे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज इसके अन्दर आते थे और पूरा राजस्थान का कोई भी व्यक्ति मात्र 850 रुपये देकर इस योजना के अन्दर शामिल हो सकता था। ..(व्यवधान)... आप लोग आयुष्मान योजना लेकर आ गए। 5 लाख का बीमा, कितने लोगों का बीमा कर दिया, कब से बीमा शुरू कर दिया, किन-किन हॉस्पिटलों में आपका कार्ड चल रहा है? लाइन लग रही है, वो गरीब बद्दुआएं दे रहा है आपको, जिसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, अपनी बीवी के गहने गिरवी रखने पड़ते थे, उसको सरकार ने इतना बड़ा तोहफा दिया था कि कम से कम इलाज के लिए तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। ..(व्यवधान)... भूल गए, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा, वो 15 लाख तो नहीं डले, हमने 25 लाख डाल दिए कि जा, तेरा 25 लाख तक का इलाज करा लेना, तेरे जेब से 1 पैसा नहीं लगेगा, यह हमने किया। हमने किया, जो कहा वो करके दिखाया। आपने, जो किट मिलते थे, अन्नपूर्णा किट, गरीब लोगों को, आपने किट बंद कर दिए, क्यों बंद दिए? 300-400-500 रुपये का सामान किसी गरीब को मिल जाता था, उसको दाल, तेल, मसाले मिल जाते थे तो आपके पेट में दर्द क्यों हो गया? ..(व्यवधान)...

मुख्य मंत्रीजी, आप भले इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं, ये लोग, जनता की जीवन की उपयोगी जो योजनाएं हैं, राजस्थान की जनता की जो लाइफ लाइन है, उसको बंद करवा कर, ये सारा पाप आपके सिर पर चढ़ाना चाहते हैं और ये सारे साफ बचना चाहते हैं। आपको इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। आपने खुद ने कहा था, मैंने सुना था, मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि मैं पिछली सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करूंगा, आपने कहते ही अगले

ही दिन आपने किट बंद कर दिया, आपने फोन बंद कर दिए, आपने चिरंजीवी बंद कर दी, आपने दुर्घटना बीमा योजना बंद कर दी, आपने राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया, आपने महात्मा गांधी प्रेरकों को हटा दिया, आपने नौजवान युवा साथियों का बेरोजगारी भत्ता रोक दिया, आपने डेढ़ सौ रुपये बढ़ाने के लिए जो कानून हमने बनाया, हमने कानून बनाया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर साल 15 परसेंट बढ़ेगी, आपने डेढ़ सौ रुपये बढ़ाने के लिए उन गरीबों को, विधवाओं को, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को 6 महीने तक लटकाए रखा, यह आपकी सरकार का निर्णय है। आप बढ़ा देते, 1 महीने में बढ़कर आ जाते, 6 महीने रोकने की क्या जरूरत थी? आपकी जो योजनाएं हैं, आप स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, आप किनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं? यह हालत प्रदेश के अन्दर हो रही है, ये ठीकरा इधर फोड़ दें, उधर फोड़ दें, इससे काम चलने वाला नहीं है। कोई ऐसा निर्णय निकले कोई समुद्र मंथन हो और जिस प्रकार से विष निकला, सबने कहा कि यह विष कौन पीयेगा, यह विष कौन पीयेगा, भगवान शंकर ने वो विषय पीया। तो आप भी कोई मंथन करो, और कोई विष निकलता है तो टीकाराम जूली पीने को तैयार है पर मंथन को करिये। ..(व्यवधान)... आप लोग शंकर भगवान के जो भक्त हैं, उन पर उँगली उठाते हो? उनकी बात करते हो, आपका जो मिशन है, वो इस चीज से पूरा होने वाला नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपने जिस प्रकार से इस बजट के अन्दर काम किया है उसका नतीजा आने वाला है। भगवान श्रीराम की जो आप बात कर रहे थे। भगवान श्रीराम ने आपको जो दर्शन है वो दे दिए हैं। ..(व्यवधान)... अब भी सब लो, क्योंकि भगवान श्रीराम ने जिस पुल को, सेतु को बनाया था, उसके अन्दर उस छोटी गिलहरी के योगदान को भी भगवान श्रीराम नहीं भूले थे। ..(व्यवधान)... उन्होंने शबरी को भी और उस गिलहरी को भी, ..(व्यवधान)... शबरी को भी और उस गिलहरी को भी पूरा सम्मान दिया था। यह समय-समय की बात है, ..(व्यवधान)... आप जिस प्रकार की बात कर रहे थे, वो नतीजा आपके सामने आ चुका है।

श्री अध्यक्षः समय का ध्यान रखें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): +++ ..(व्यवधान)... +++ अध्यक्षजी, +++ अध्यक्षजी, जब भगवान श्रीराम के मन्दिर का उद्घाटन करने गए, तो हमारे देश की आदिवासी दलित राष्ट्रपति को लेकर नहीं गए ताकि उनके प्रोटोकॉल की वजह से मोदीजी पीछे हो जाए। ..(व्यवधान)... जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था तो वहां आप राष्ट्रपतिजी को लेकर नहीं गए क्योंकि वो दलित थी, और प्रोटोकॉल में प्रधान मंत्री से ऊपर थी और यही कारण है ..(व्यवधान)... यही कारण है कि मोदीजी जब अयोध्या के स्टेशन का उद्घाटन करने गए तो आकाशवाणी हुई कि +++ उद्घाटन मत करो, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं करूंगा, उद्घाटन किया और स्टेशन की दीवार गिर गई। उसके बाद अयोध्या की सड़क, उसका उद्घाटन करने गए, फिर आकाशवाणी हुई कि +++ उद्घाटन मत करो, सड़क टूट जाएगी, नहीं, माने और उद्घाटन कर दिया, पूरी सड़क धंस गई। ..(व्यवधान)... उसके बाद हमारे शंकराचार्यों ने मना किया,

धर्माचार्यों ने मना किया कि मन्दिर अधूरा है, इसका उदघाटन मत करो, उद्घाटन कर दिया, आज वो सारी छत टपक रही है। ..(व्यवधान)... भगवान श्रीराम का श्राप इनको झेलना पड़ेगा। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: दो मिनट।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मेरा टाइम बचा हुआ है। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: दो मिनट बाकी हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जितना टाइम बचा हुआ है, उसी में पूरा करूंगा। ..(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्षजी, सुनिए। और यही नहीं, ये लोग, जो लोग भगवान श्रीराम की बात करते थे, वो अयोध्या में हारे, वो चित्रकूट में हारे, वो सीतापुर के अन्दर हारे, रामेश्वर में हारे, वो बद्रीनाथ में हारे, और मैं कह रहा हूं कि ये केदारनाथ में भी हारेंगे, सीट खाली हो गई है। ..(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्षजी, मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि वो कौन लोग थे जिनका बयान यह आया था कि हम राजस्थान में 25 की 25 सीट जीतेंगे। ..(व्यवधान)... आप बताइए कि किसने कहा कि 25 की 25 सीटें जीतेंगे और यह कहा कि हम 5 लाख से अधिक से जीतेंगे। अध्यक्षजी, कोई इनका अकाउंट खोल रखा है कि नहीं? जो मर्जी जो बोलेंगे, यह ऊपर वाले की लकड़ी है, ऊपर वाले की लकड़ी है जब टिकती है तो आवाज नहीं होती है, यह बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। ..(व्यवधान)... इसलिए प्रयागराज भी हारे, नासिक भी हारे, रामटेक भी हारे, यानी आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब लोगों ने खारिज कर दिया, क्या बात करते हो आप? ..(व्यवधान)... क्या बात करते हो, किस बात की दुहाई देते हो? ..(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्षजी, छल, बल, भ्रम और भ्रष्टाचार के दम पर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है, संविधान को कमजोर करने का काम किया ..(व्यवधान)... संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, राजस्थान के अन्दर उड़ा रहे हैं, 400 पार, ..(व्यवधान)... 400 पार, हो गया 400 पार? 200 भी, 200 पर अटक गए, ..(व्यवधान)... और में कहना चाहूंगा कि हमारी वित्त मंत्रीजी, कह रही थी, ..(व्यवधान)...हमारी वित्त मंत्रीजी कह रही थी कि संविधान में कुछ संशोधन की जरूरत है। मैं पूछना चाहूंगा कि जब रिप्लाई दें तो बता दें कि अब भी संविधान में संशोधन की जरूरत बच रही है या नहीं बच रही है, जवाब चाहूंगा। ..(व्यवधान)... इस देश का संविधान जो पूरी दुनिया के अन्दर सबसे मजबूत लोकतंत्र हमको देता है, हम इस सदन के अन्दर जो चर्चा कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप टोक रहे हो, आप रिप्लाई दोगे, यह इस संविधान के कारण है। ..(व्यवधान)... अब इस संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, इस संविधान में से गरीब को मारना चाहते हैं, अल्पसंख्यक को मारना चाहते हैं, नौजवान को, अग्निवीर बनाकर मारना चाहते हैं, आप चाहते क्या हैं? आप आरक्षण खतम

करना चाहते हैं।

MLS/RTM/16.07.2024/17:30/3h

आपकी मंशा आरक्षण को खत्म करने की है। यह बात मैं कहना चाहूंगा। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बातों से ऐसी क्या तकलीफ है? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः कैलाश जी, बैठिये। समय हो रहा है। ...(व्यवधान)... जवाब दे देंगे। आज उप-मुख्य मंत्री जी और 29 को मुख्य मंत्री जी दे देंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यहां जिस प्रकार से गुजरात के ठेकेदार आ रहे हैं, यह राजस्थान की जनता क्या काम करेगी?

श्री अध्यक्षः टाइम हो गया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मेरे पांच मिनट तो इन लोगों ने खराब कर दिये। गुजरात के ठेकेदार यहां भी आ रहे हैं। जैसे दिल्ली, जबलपुर, राजकोट जैसे एयरपोर्ट्स गिरे हैं, वैसे ही यहां के जो विकास कार्य होंगे, वे गिरेंगे, इसलिए मुख्य मंत्री जी, इन गुजरात के ठेकेदारों पर रोक लगाएं ताकि राजस्थान के लोगों को रोजगार मिल सके। यह बात मैं कहना चाहूंगा। अब आप लोगों को ज्यादा तकलीफ इसलिए भी है कि आने वाले समय में पांच उप-चुनाव हैं। आपको पूरा डर है। ...(व्यवधान)... आपको डर है। आप जितनी हमारी योजनाएं बन्द करेंगे, उतना आप लोगों को नुकसान होगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस सदन में पिछले एक सप्ताह से गतिरोध चल रहे हैं। मुझे बड़ा दु:ख होता है। हम नहीं चाहते, हम आपकी किसी बात पर टोका-टाकी करें। हम नहीं चाहते, आपके किसी मंत्री को बोलने से हम रोकें, लेकिन मुख्य मंत्री जी, आज आप इस सदन में बैठ रहे हैं तो मैं यह बात कहना चाहूंगा, आपके शिक्षा मंत्री, जो एक समाज विशेष के खिलाफ बयान देते हैं, यहां उस चीज को एग्री करते हैं, सदन में एग्री करते हैं कि मुझसे कुछ गलत शब्द निकले, लेकिन वे माफी नहीं मांगते। ...(व्यवधान)... माफी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता। आज राजस्थान के बच्चों का क्या भविष्य होगा, जिस राज्य के इस प्रकार के मंत्री होंगे जो पिछले सात महीनों में 170 बयान दे चुके। कोई जाति का, कोई धर्म का, कोई समुदाय का, लेकिन एक बयान ऐसा बता दें, जो इस राजस्थान के नौनिहालों के भविष्य के बारे में कहा गया हो।

जिस व्यक्ति पर खुद 14 मुकदमे दर्ज हों, वह दूसरों को जेल में डालने की बात कहे, यह नाइंसाफी है। बात पक्ष की हो या विपक्ष की हो, बात अगर कोई है तो कहनी चाहिये। आपके मंत्री बयान देते हैं, मुख्य मंत्री जी का कोई बयान नहीं आता, पार्टी का कोई बयान नहीं आता, इसलिए हम तो यह मानकर चलते हैं, आप सब लोगों की शह भी इस चीज में है। मैं चाहता हूं, इस सदन का गतिरोध टूटना चाहिये। अच्छे विषयों पर चर्चा हो। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं, अध्यक्ष जी ने कहा है कि एक दिन हम सारे विधायकों से पूछेंगे कि उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में क्या अच्छे काम किये। जो अच्छे काम एक विधायक ने किये हैं,

उनसे सीखकर दूसरा विधायक भी अपने क्षेत्र में करे। आज देश-दुनिया में क्या नवाचार हो रहे हैं, क्या हम आज भी उसी जगह पर खड़े रहें, आज भी हम आपस में एक-दूसरे पर छींटाकशी करते रहें?

रोजाना मैं देख रहा हूं आपके मंत्रियों के जो बयान आ रहे हैं, कोई दो बच्चों का कह रहा है, कोई हिन्दू का कह रहा है, कोई मुस्लिम का कह रहा है, कोई दलित का कह रहा है, कोई किसी को सर्टिफ़िकेट दे रहा है, तो हिन्दुओं के सर्टिफ़िकेट आप लोग बांट लें। आज शंकराचार्य जी ने क्या कहा, शंकराचार्य जी का बयान आया है।

मैं अन्त में यही कन्क्लूड करता हूं कि यह जो बजट है, यह एक प्रकार से दिशाहीन, निराशाजनक और जो आप लोगों ने मेज थपथपायी हैं न, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी जब जवाब दें तो जितनी भी घोषणाएं की हैं, उनका बजट में कितना प्रावधान है, यह जरूर बताएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। ...(व्यवधान)... उप-मुख्य मंत्री। माननीय वित्त मंत्री जी। ...(व्यवधान)... बैठिये माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, बैठिये। मैं कई दिनों से नोट कर रहा हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय कार्य सूची पूरी होने और वित्त मंत्री जी के जवाब तक बढ़ाया जाता है।

माननीय उप-मुख्य मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 पर सामान्य वाद विवाद

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों का बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान सार्थक विचार रखने पर आभार व्यक्त करती हूं। पक्ष का और विपक्ष का भी आभार व्यक्त करती हूं। माननीय सदस्यों के साथ-साथ आम जनता ने भी इस अभूतपूर्व बजट का खुले दिल से स्वागत किया है। उस पर मैं बाद में आऊंगी। साथ ही, मैं अपने विपक्ष के साथियों, विशेषकर राजाखेड़ा, चोमू, रानीवाड़ा तथा पाली से आने वाले माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बजट की प्रशंसा की है। मैं अपने उन विपक्ष के साथियों का भी आभार प्रकट करती हूं, जिन्होंने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं तथा सकारात्मक आलोचना की है।

अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सारे सुझाव दिये। ये सुझाव आप पहले ही दे देते जब

आपकी सरकार थी। शायद कुछ बदल जाता, कुछ अच्छा हो जाता। प्रदेश की जनता को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। यह वित्तीय स्थिति नहीं होती जो हमें मिली है। अब इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को विकास की नयी ऊंचाइयों पर ले जाने का भरपूर प्रयास करेंगे। बजट का मात्र विरोध करने वाले सदस्यों के लिए भी मैं कहना चाहूंगी,

मुखालफत से मेरी शख़्सियत संवरती है,

मैं विरोधियों का बड़ा एहतराम करती हूं।।

हमने प्रदेश के दीर्घकालीन लक्ष्यों (Long term goals) तथा विकसित राजस्थान @ 2047 को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया है। राज्य के विकास में आम नागरिकों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए तथा बजट को सभी वर्गों, क्षेत्रों के लिए समावेशी बनाने के लिए आमजन एवं संगठनों के सुझाव आमंत्रित किये गये थे। प्रदेशवासियों द्वारा बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाते हुए लगभग 1 लाख 67 हजार से अधिक सुझाव हमें दिये। साथ ही, हमारे द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न महत्त्वपूर्ण स्टेकहोल्डर्स यथा महिलाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, किसानों, उद्योगपतियों, व्यापार मण्डलों, कर्मचारियों आदि संगठनों के साथ Pre budget consultation meetings आयोजित की गयी थीं।

मुख्य रूप से रोजगार, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित सुझाव प्राप्त हुए। हमने इन सभी सुझावों का सम्बन्धित विभागों से परीक्षण कराकर इन सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई कर यथासम्भव बजट में समावेशित किये जाने का प्रयास किया है। हमें पूरी आशा है, सत्तापक्ष के साथ-साथ विपक्ष के साथियों का भी इसके क्रियान्वयन में हमें पूरा समर्थन प्राप्त होगा। बहुत आवश्यक है, आप बार-बार कह रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन, कैसे आप वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएंगे? हम करवाएंगे, डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में। आप चिन्ता न करें, हम पूरी तरह से प्रयास ही नहीं, करके दिखाएंगे। जो घोषणाएं की हैं, वायदे किये हैं, उन्हें पूरा करेंगे।

जिस भी कार्य का शिलान्यास होगा, जैसे हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी, शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं, यह सरकार वह करेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी करेंगे। वर्ष 2024-25 के लिए जो हमने 4 लाख 95 हजार 466 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, उसका आकार वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों से 1 लाख 4 हजार 611 करोड़ रुपये अधिक है। चर्चा के दौरान राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा बजट घोषणाएं किस प्रकार से धरातल पर आएंगी, इस पर चिन्ता व्यक्त की गयी है। वह चिन्ता तो बिलकुल सही है। आपने देखा होगा, आपके समय तो कोई काम ही नहीं हुआ। अब आप लोग सोच रहे हैं, ये लोग कैसे करेंगे, हमने इनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। पूरा सब-कुछ खजाना खाली करके चले गये, लेकिन जैसा मैंने कहा, वित्तीय प्रबन्धन पूर्ण रूप से होगा।

mkd/rtm/16.07.2024/17:40/3j

हमारी सरकार ने कार्यभार सम्भालते ही हमारे मुख्य मंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में अपने संकल्पों को पूर्ण करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम करना शुरू किया है। माननीय सदन को बजट भाषण के अन्तर्गत मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में प्रगति से अवगत कराया जा चुका है।

मैं यहां पुनः याद दिलाना चाहूंगी कि हमारे द्वारा यह त्वरित गति, चूंकि दो महीने से अधिक चुनावी आचार संहिता थी और दो महीने आचार संहिता में गये, उसके बावजूद भी यह गति हमने सुनिश्चित की है।

हम इसी प्रकार आगे भी पूर्ण तत्परता से निरन्तर कार्य करते रहेंगे। राजाखेड़ा, रानीवाड़ा, डूंगरपुर व लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की फिस्कल पॉजिशन जैसे आउटस्टेंडिंग लोन, फिस्कल डेफिसिट, कैपिटल आउट-ले, गवर्नमेंट गारंटी आदि के मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया। इस सम्बन्ध में, मैं राज्य के फिस्कल पोजीशन के इन बिन्दुओं पर वास्तविक स्थिति का विवरण भी सदन में प्रस्तुत करूंगी।

साथ ही, हमारे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य श्री रोहित बोहरा जी ने यह भी बिन्दु उठाया कि केन्द्र के बजट का इन्तजार क्यों नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये माननीय सदस्य काफी विद्वान हैं और मैं समझती हूं कि संविधान के लेखानुदान के प्रावधान से वाकिफ होंगे। फिर भी, मैं उन्हें यह याद दिला देती हूं कि हमारी सरकार द्वारा 8 फरवरी, 2024 को लेखानुदान विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। संविधान के प्रावधानों के अनुसरण में हमने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4 माह तक के खर्चे की अनुमति ली थी, जो 31 जुलाई, 2024 को समाप्त हो रही थी, अर्थात् 1 अगस्त, 2024 से वर्ष की शेष अवधि के लिए खर्चे की अनुमति, विकास कार्यों के लिये जी जानी आवश्यक थी।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात है कि केन्द्र सरकार द्वारा उनके लेखानुदान में राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं, केन्द्रीय करों में हिस्सा राशि इत्यादि के बजट अनुमान वर्ष 2024-25 के दर्शाये गये हैं, उस आधार पर ही इन आंकड़ों को राज्य के परिवर्तित बजट में शामिल किया है। अब तो माननीय सदस्य को उनके प्रश्न का उत्तर भली भांति मिल गया होगा। इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात का है कि गत सरकार में अपनी वरिष्ठता के कारण संसदीय कार्य को सम्भालने वाले कोटा (उत्तर) से आने वाले माननीय विधायक इस माननीय सदन में प्रश्नों के उत्तर सहित, विधायी कार्य के सम्बन्ध में सरकार एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के अधिकारों एवं दायित्वों के ऊपर बेमतलब की टिप्पणी करके अपने अनुभव का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि बहुत बार अधिकारियों पर और सब पर बिना किसी वजह के, हां उससे उनकी शायद इनएक्सपीरियंस दिखता है। असत्य कहने लगे, सच से बचने लगे, हौसले मिट गये, तजुर्बा रह गया।

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा इस चर्चा में बहुत समय तक केन्द्र सरकार पर टिप्पणी की जाती है। बहुत बार उन्होंने केन्द्र सरकार की बातें कहीं, न केवल उन्होंने, वैसे बहुतों ने कही पर विशेषकर उन्होंने कही। प्रदेश की जनता की बात करने के बजाय केन्द्र सरकार पर ही चर्चा, ...(व्यवधान)... इससे ऐसा लगता है कि शायद इनको सांसद बनना था। शायद इनको सांसद बनना था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। I say Mr. Rohit Bohra, नाम ले रहा हूं। यह बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आगे से यह बर्दाश्त नहीं करूंगा, ध्यान रखो। आप बोलिये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): मेरा विनम्र आग्रह है कि बजाय केन्द्र पर बेमतलब टिप्पणी के स्थान पर आप प्रदेश से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करें। माननीय सदस्य द्वारा यह बिन्दु भी उठाया गया कि केन्द्र सरकार से जो सीआरएफ पीएमजीएसवाई इत्यादि का पैसा राज्य की संचित निधि के माध्यम से प्राप्त होता है को राज्य बजट में दर्शाया गया है। उन्होंने टिप्पणी कर यह जानकारी चाही कि इस पैसे को परिवर्तित बजट में क्यों शामिल किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहूंगी कि केन्द्र हमारी सरकार होने पर भी क्या आपकी गत सरकार सीएसएस से सम्बन्धी घोषणाएं नहीं करती थीं। हमारी सरकार तो डबल इंजन की सरकार है, जो प्रदेश की जनता को पूर्ण रूप से समर्पित है। माननीय सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिए कि सदैव ही केन्द्र सरकार से विभिन्न केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं अथवा जो राशि संचित निधि के माध्यम से आती है, वह राज्य के आय-व्ययक अनुमानों में सम्मिलित रहती है। हमारे रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा यह टिप्पणी की गई कि यह बजट चुनावी बजट है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराती हूं कि इनके बजट जरूर चुनावी होते होंगे। शुरू के वर्षों में तो जनता के कल्याण के लिए धरातल पर कोई योजना का कार्य किया ही नहीं, परन्तु अन्तिम वर्ष में चुनाव को देखते हुए लोक-लुभावन योजनाओं की थोथी घोषणाएं कर वोट की राजनीति से प्रेरित होकर आमजन को गुमराह करने का जरूर इन्होंने काम किया।

हमने तो पहले बजट से ही दूरदर्शी सोच रखते हुए हर क्षेत्र के लिए प्लान बनाकर यह कार्य किया है, बजट बनाया है। यह एक लोंग टर्म बजट है। सिर्फ एक साल का बजट नहीं है, सिर्फ यह भी नहीं है कि यह पांच साल का बजट है। यह विकसित राजस्थान का बजट है, 2047 के राजस्थान का बजट है। एक विजनरी बजट है और इसके लिए हम सबको धन्यवाद देना चाहिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिलकर यह इतना अच्छा बजट बनाया है। जिसका पूरा लाभ प्रदेश की जनता को हमारे इसी कार्यकाल में मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि हमारे इसी कार्यकाल में शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी, सिर्फ घोषणाएं नहीं, जो आपने कीं।

अब मैं फिस्कल स्थिति के बारे में उल्लेख करना चाहूंगी, डेट एंड अदर लायबिलिटीज,

ऋण एवं अन्य उत्तरदायित्व, गत कांग्रेस सरकार द्वारा की गई इर्रेशनल एवं थोथी बजट घोषणाओं तथा अनप्रोडेक्टिव व्यय के फलस्वरूप वर्ष 2023-24 में राज्य के ऋण एवं अन्य दायित्व हमारी गत सरकार के कार्यकाल वर्ष 2017-18 के दुगने से अधिक बढ़कर 5 लाख 70 हजार 646 करोड़ रुपये पर पहुंच गये हैं।

माननीय सदस्यों को जानकार आश्चर्य होगा कि गत कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के प्रथम 6 से अधिक दशकों में लिए गये ऋण से भी अधिक ऋण केवल 5 वर्ष में ही लिया। सोचिये तो सही, इसके परिणामस्वरूप राज्य के ब्याज भुगतान में अत्यधिक वृद्धि हो गई और यह स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य को डेट के भंवर में फंसा दिया, क्या करें, बिलकुल अच्छा नहीं, प्रदेश की जनता के लिए तो बिलकुल अच्छा नहीं किया आपने।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भगवद् गीता तथा रैदास जी की कर्म प्रधान निष्काम कर्म की अवधारणा को आत्मसात करने वाली हमारी सरकार फिस्कल रिस्पोंसिबिलिटी को भली भांति समझती है। माननीय मुख्य मंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हम फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ पर अग्रसर हैं। जहां हमारी पिछली सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017-18 में डेट टू जीएसडीपी रेशो 33.77 परसेंट था, वहीं चार्वाक को अपना आदर्श मानकर ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत, ऋण लेकर घी पीओ की सोच एवं पांच सितारा होटल के बन्द कमरों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करने वाली गत सरकार के कार्यकाल में वित्तीय कुप्रबन्धन के फलस्वरूप वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल डेट टू जीएसडीपी रेशो 37.34 परसेंट तक पहुंचा दिया।

अब होटल रूम्स का खर्चा तो देना ही था ना, महीनों तक बन्द, कोरोना से जूझ रही थी, कोविड से जूझ रही थी, राजस्थान की जनता और आप होटलों में बन्द थे। क्या करें, अब सरकार को तो बचाना जरूरी था ना, आपके लिए। अब हमारे द्वारा अपने प्रथम पूर्ण बजट में ही डेट टू जीएसडीपी रेशो में कमी करते हुए इसे 35.97 परसेंट तक सीमित रखने का प्रयास किया है।

Bhs/Rtm/16.7.24/17.50/3k

तथा हम इसी पथ पर चलने के लिए कटिबद्ध हैं। मुझे अत्यधिक अचरज हुआ कि जिस पार्टी की सरकार के मुख्य मंत्री तथा उप मुख्य मंत्री में संवादहीनता हो, बात ही नहीं करते हों, उप मुख्य मंत्री को मंत्री मंडल छोड़ना पड़े उस पार्टी के अग्रणी नेता लक्ष्मणगढ़ से आने वाले हमारे माननीय विधायक हमारी सरकार में संवाद की स्थिति तथा को-आर्डिनेशन को लेकर असत्य चिन्ता व्यक्त करते हैं। आप हमारी चिन्ता न करें। आप तो अभी भी वो ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आप तो अभी भी सब लोग वो ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमें अपने काम पर छोड़ें, हम अच्छा काम करके दिखायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, उन्हें अभी से ही हमारी इस डबल इंजन की सरकार में राज्य एवं केन्द्र के अच्छे रिश्ते, आपको तो इससे भी समस्या हो रही है कि अब इनको तो कोई समस्या

होगी नहीं ये तो सारे ही वित्तीय संसाधन केन्द्र से भी ले आयेंगे, वहां से भी इनको बहुत सहयोग मिलेगा तो आपकी चिन्ता समझ में आती है, बिलकुल सही है। आप लोगों ने अपनी पार्टी के अन्दर बहुत संघर्ष किया अब क्या करें। हम लोग तो काम करने आये हैं राजस्थान की जनता ने अवसर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, उन सहित विपक्ष के सभी माननीय विधायकगण से अनुरोध व अपेक्षा करूंगी कि वे ऐसी निरर्थक बातों में समय जाया न करें। प्रदेश की जनता के कल्याण में हमारा सहयोग करने का प्रयास करें। अभी तो उन्हें लोकतंत्र में कई सालों तक जनता विपक्ष की ही भूमिका देने वाली है। बहुत सालों तक आप लोग तो अब इसी की आदत डाल लीजिये विपक्ष में बैठने की। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को भी कर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करने की दिशा में कहना चाहूंगी कि ज्ञान के प्रकाश में सत्य की राह पर धर्म की ध्वजा लिये कर्म का संकल्प लो। जीवन के संग्राम में इच्छाओं का दाह कर दृढ़ता का ढोल लिये कर्म का संकल्प लो। ...(व्यवधान)... आप अपनी बात कीजिये न। आपने क्या किया पांच साल? काश ये सारी बातें चिन्ताएं जो आपने सबने अपनी डिबेट में रखी वो ही चिन्ताएं जब आपकी सरकार थी तब रखते तब सुझाव देते। तब मानने वाला भी कोई नहीं था और सुनने वाला नहीं था, मानने वाला नहीं था क्या करें। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को पुनः अवगत कराना चाहती हूं कि हमारे द्वारा राज्य के टैक्स व नोन टैक्स रेवेन्यू में एफिसिएंसी बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण ऑटोमेशन के साथ ही फेसलेस मैनेजमेंट की व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने से ट्रांसपेरेंसी आने के साथ ही रेवेन्यू कलेक्शन में वृद्धि होनी सुनिश्चित है। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने राज्य में जीएसटी संग्रहण के बारे में भी संशय व्यक्त किया है। जैसे कि सर्वविदित है कि जीएसटी एक राष्ट्रीय कर प्रणाली पर आधारित इन्डाइरेक्ट टैक्स प्रणाली का सबसे बड़ा सुधार है। प्रारम्भिक वर्षों में केन्द्र द्वारा राज्य में राजस्व वृद्धि 14 प्रतिशत से कम होने की दशा में उसकी क्षतिपूर्ति भी की गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष अप्रैल में सम्पूर्ण देश के साथ ही हमारे विशेष प्रयासों से राज्य में भी जीएसटी का सर्वाधिक कलेक्शन हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही राज्य में हुए कुल उत्पादन से देश में प्राप्त जीएसटी की ग्रोथ भी सर्वाधिक रही है। साथ ही, प्रूडेन्ट फिस्कल मैनेजमेंट द्वारा राजस्व बढ़ाते हुए हम प्रदेश की जनता से किये अपने सभी वायदे पूरे करेंगे। हमारे द्वारा अल्प समय में इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। यथा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर स्पेशल ड्राइंग फैसेलिटी एवं वेज एंड मींस एडवांस के अतिरिक्त कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड को भी हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2024 में सब्सक्राइब किया गया। इसके फलस्वरूप राज्य को बाजार दर से 40 प्रतिशत कम ब्याज दर पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो पायेंगे। साथ ही ब्याज दर कम होने से राज्य सरकार पर ब्याज भुगतान का दायित्व भी कम रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे एक ओर राज्य के विकास के लिए संसाधनों की

उपलब्धता सुनिश्चित हुई वही दूसरी ओर ट्रेजरी बिल्स में निवेश से इंटरेस्ट के रूप में आय की प्राप्ति हो रही है। हमारे इस कुशल प्रबन्धन से वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 150 करोड़ रुपये की बचत अपेक्षित है। इस तरह हमारी सरकार दीर्घकालीन डेब्ट के सम्बन्ध में होलिस्टिक एवं पर्सपेक्टिव प्लानिंग के आधार पर समुचित कदम उठा रही है जबकि कांग्रेस सरकार के एड हॉक फिस्कल पॉलिसी मेजर्स के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग डेब्ट ट्रेप की स्थिति में आ गई थी। इन्होंने वो ही छोड़ा हमारे लिए लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ यह बजट भी तैयार किया गया है। वित्तीय संसाधन भी सारे उपलब्ध होंगे और काम भी बहुत अच्छा होगा।

माननीय सदस्यों को जान कर प्रसन्नता होगी कि डबल इंजन की हमारी सरकार के प्रयासों से प्रदेश को केन्द्र सरकार से इन्फ्रास्ट्रक्चर डवपलमेंट के लिए लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि गत वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त हो सकी। इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए हमको गत वित्तीय वर्ष में 2 हजार करोड़ रुपये केन्द्र से प्राप्त हुए हैं यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के साथ ही राज्य के विकास में भी तेजी आयेगी।

राजकोषीय घाटा - वर्ष 2017-18 में हम राजकोषीय घाटे को 3.4 प्रतिशत के स्तर पर छोड़ कर गये थे लेकिन कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में इसको अनियंत्रित रूप से बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जिसके फलस्वरूप 2023-24 में राजकोषीय घाटा बढ़ कर 4.26 प्रतिशत तक पहुंच गया। हमने हमारे परिवर्तित अनुमानों में राजकोषीय घाटे को पुन: कम करते हुए 3.93 प्रतिशत के स्तर पर लाने का प्रयास किया है। मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने इस वर्ष भी राजकोषीय घाटे को एफआरबीएम द्वारा निर्धारित सीमा में रखा है तथा भविष्य में भी हम इसे एफआरबीएम सीमा में ही रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

गवर्नमेंट गारंटीज - राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने गवर्नमेंट गारंटीज की स्थिति के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि कांग्रेस सरकार के 2013-14 के अन्त में कुल बकाया राजकीय आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट गारंटीज 85 हजार 911 करोड़ रुपये थी जो हमारी गत सरकार के प्रयासों से वर्ष 2018-19 में घट कर 70 हजार 430 करोड़ रुपये रह गई थी, परन्तु कांग्रेस सरकार द्वारा इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से राजकीय गारंटीज जारी की गई एवं 31 दिसम्बर, 2023 को बकाया राजकीय गारंटीज 5 साल में ही पचास प्रतिशत से भी अधिक बढ़ कर 1 लाख 8 हजार 328 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दोनों का सेम है लिखने वाला। हमारे भी वो ही लिख रहे थे और आपके भी वो ही।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): पर सोच अलग है। वीजन अलग है। हमारी सरकार राजकीय गारंटीज एफआरबीएम द्वारा निर्धारित सीमा में ही देने के साथ अल्टरनेट ऑप्शंस

भी एक्सप्लोर कर रही है। केन्द्र सरकार के सहयोग से इस सम्बन्ध में हम वर्ल्ड बैंक एवं एडीबी जैसे मल्टीलैटरल इंस्टिट्यूशंस के साथ इस दिशा में कार्य प्रारम्भ कर रहे हैं। ग्रो स्टेट राज्य सकल घरेलू उत्पाद ...(व्यवधान)...

Kas/rtm/16.07.2024/18.00/3l

राज्य सकल घरेलू उत्पाद

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारी सरकार के द्वारा अल्प अवधि में ही कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के फलस्वरूप गत सरकार के कार्यकाल में दिसम्बर, 2023 तक जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर जो कि 11.58 परसेंट थी, वह मार्च, 2024 में बढ़कर 12.56 प्रतिशत हो गई है।

इसी प्रकार मैं सदन के सामने यह तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में जी.एस.डी.पी. में औसत वृद्धि दर 11.02 प्रतिशत रही थी। यशस्वी प्रधान मंत्री जी के विजन एवं माननीय मुख्य मंत्री जी के एक्शन प्लान के दृष्टिगत हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में जी.एस.डी.पी. में वर्ष 2024-25 के लिये 16.53 प्रतिशत वृद्धि दर का रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। आप आंकड़ें बता रहे थे, तो मैं भी कुछ आंकड़ें आपके सामने रख दूं। ...(व्यवधान)...

पूंजीगत व्यय

यह सर्वविदित तथ्य है कि पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) पर अधिक राशि व्यय किये जाने से राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिलने, जी.एस.डी.पी. में वृद्धि होने, रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होने, परकेपिटा इनकम में वृद्धि होने के साथ ही प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा। हमारी सरकार के गत कार्यकाल में औसत पूंजीगत व्यय नैट बोरोइंग का 61.52 प्रतिशत था। लेकिन कांग्रेस सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमैंट एवं ऋण का उपयोग थोथी बजट घोषणाओं तथा अनप्रोडेक्टिव राजस्व व्यय में किये जाने के परिणाम स्वरूप औसतन पूंजीगत व्यय नैट बोरोइंग का 41.61 प्रतिशत तक गिर गया। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अब हम इसे 63.13 परसेंट तक लाकर गाड़ी को पटरी पर लेकर आयेंगे। हमारी गत सरकार के कार्यकाल में जहां एवरेज कैपिटल आउट ले जी.एस.डी.पी. का 2.54 परसेंट था, वहीं कांग्रेस की रेवड़ी कल्चर के चलते वर्ष 2023-24 तक यह 1.75 प्रतिशत के स्तर तक गिर गया। हमारी सरकार ने आधारभूत संरचनाओं एवं पूंजीगत कार्यों (कैपिटल आउट-ले) हेतु वर्ष 2024-25 में प्रावधान को बढ़ाकर 44216 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है, जो कि जी.एस.डी.पी. का 2.48 परसेंट है।

सैक्टर वाइज खर्च का विश्लेषण। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए समावेशी बजट प्रस्तुत किया है, जिससे हमारा प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में तो आयेगा ही, पर वंचित वर्गों के चेहरों पर भी मुस्कान आयेगी। माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान विभिन्न सैक्टर्स पर अपनी-अपनी राय दी है।

मानानीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मुख्य सैक्टर्स पर अपनी बात कहना चाहूंगी।

वर्ष 2018-19 में योजनाओं का कुल प्रावधान 107865 करोड़ रुपये रखा था, जो वर्ष 2023-24 में 184312 करोड़ हुआ। इस प्रकार पांच वर्षों में केवल 76 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। जबकि हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 में 209634 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस प्रकार हमारी सरकार ने केवल एक वर्ष में ही 25000 करोड़ की वृद्धि प्रस्तावित की है। हमारी सरकार ने सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं, जिसके अंतर्गत मूलभूत सेवाएं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं पेयजल इत्यादि आती हैं, में वर्ष 2024-25 में स्कीम एक्सपेंडिचर में 18 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की है।

मैं माननीय सदस्यों को कुछ प्रमुख क्षेत्रों में हमारे द्वारा की जा रही वृद्धि के बारे में अवगत कराना चाहूंगी।

1. सड़कें 1655 करोड़ रुपये,
2. पेयजल 3496 करोड़ रुपये,
3. सिंचाई 2277 करोड़ रुपये,
4. ऊर्जा 4490 करोड़ रुपये,
5. चिकित्सा 3687 करोड़ रुपये,
6. शिक्षा 7064 करोड़ रुपये,
7. सामाजिक सुरक्षा व अन्य 4581 करोड़ रुपये,
8.कृषि बजट 7600 करोड़ रुपये से अधिक।

कृषि एवं पशुपालन

हमारी सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं को समृद्ध बनाकर विकसित एवं खुशहाल राजस्थान का सपना साकार करेगी तथा हम उन्नत कृषि, खुशहाल किसान के लिये प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार कांग्रेस की तरह तथ्यहीन थोथी घोषणाओं की बजाय किसानों को सभी तरह से संबल देने का प्रयास कर रही है। हमारे द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें कृषि कल्याण एवं कृषि विकास हेतु 96787 करोड़ 27 लाख रुपये का प्रावधान रखा है, जो कि कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में किये गये प्रावधान से लगभग 7600 करोड़ रुपये अधिक है। ...(व्यवधान)... आप मुझे आंकड़ें गिना रहे थे, मैं भी आपको कुछ स्पष्टीकरण देना चाह रही हूं। आपके आंकड़ें पता नहीं कहां से आप लेकर आये। ...(व्यवधान)...

किसान साथियों को सिंचाई हेतु जल की पर्याप्त उपलब्धता रहे, इसके लिये हमने दीर्घकालीन योजना के तहत राजस्थान इंटीग्रेटेड वाटर ग्रिड मिशन प्रारम्भ कर 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य किये जाने का लक्ष्य लिया है। मैं यहां पिछली सरकार के बारे में कहना चाहूंगी कि कहीं भी पानी का नामों निशान नहीं, मगर बैठे-बैठे कश्तियां बनाते रहते थे।

जल जीवन जैसी केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना 'जल जीवन मिशन' आप यहां राजस्थान

में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाये और उसके बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बहुत कुछ कहने को है। आप बात करते हैं कि राजस्थान में पानी के बारे में सोचना चाहिये। हमारी सरकार ने कुछ ही महीनों में पानी में इतने बड़े काम किये, लेकिन आपको तो एक्सेप्ट करना नहीं है। ...(व्यवधान)...

लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जो कि परम्परा के विपरीत जाकर मेरे द्वारा पढ़े जा रहे बजट भाषण के दौरान कृषि बजट पर बोलने से पहले ही किसानों के मुद्दों पर टिप्पणी कर रहे थे। मैंने तो कृषि बजट शुरू ही नहीं किया था, पूरा कृषि बजट था, कई पेजेज का बजट था। किसानों के लिये हम सब संवेदनशील हैं। उन्हें मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगी कि वादे के अनुसार माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 30 जून, 2024 को टोंक से किसान सम्मान निधि की प्रथम किश्त के रूप में 66 लाख किसान भाइयों को डी.बी.टी. के माध्यम से किसान सम्मान निधि की अतिरिक्त राशि 650 करोड़ रुपये सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित की। राजस्थान के इतिहास में यह पहली बार है जब हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को राज्य सरकार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की गई।

msk/rtm/16.07.2024/1810/3m

हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसान कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू कीं, जिनका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 1 हजार 4 सौ करोड़ रुपये के बीमा क्लेम्स का निस्तारण किया गया तथा 9 हजार पीएम किसान समृद्धि केन्द्र स्थापित किये गये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): तीन साल से किसान तड़प रहा है, फसल बीमा का पैसा.. ...(व्यवधान)... आप किसान की बात करते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बैठ जायें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में डिस्टर्ब में नहीं।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): कांग्रेस सरकार द्वारा पशुपालकों को राहत देने के लिए पशुओं के बीमा के ढोल तो बहुत बजाये, लेकिन अपने कार्यकाल में एक भी पशु का बीमा नहीं करवाया। आप मानते हैं, माननीय सदस्य बिल्कुल एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ऐसे एक्सेप्ट करते जाइये, क्या करें?

हमने न केवल दुधारु पशुओं गाय, भैंस ही नहीं, बल्कि अन्य पशुओं भेड़, बकरी, ऊँट को शामिल करते हुए पशुधन बीमा का दायरा भी बढ़ाया है। भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा गरीब किसानों के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की, उस सम्बन्ध में मैंने, मेरे बजट भाषण में भी यही कहा कि आपके मिस-मैनेजमेंट के कारण किसान ठगा-सा महसूस कर रहा है। अच्छा है आपने अपनी नाकामी को स्वीकारा तो सही। अच्छी बात है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): आप कर रहे हैं ना, सपोर्ट। मेरी हर बार बात पर सहमति। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप के लोग कर रहे हैं। बैठिये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय सदस्य, सबसे ज्यादा तो आप मेरी हर बात पर सहमति प्रदान कर रहे हैं। हर बात को एग्री कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। इन्होंने भी सुना है, आप भी सुनिये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अच्छा है, आपने अपनी नाकामी को स्वीकारा तो।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। नो, बैठिये। माननीय सदस्य, आप सीमा क्रोस कर रहे हैं।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): लेकिन यह स्वीकारोक्ति बहुत ही विलम्ब से आयी, लेकिन चलो आयी तो सही।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सीमाओं का उल्लंघन मत करो। माननीय सदस्य, सीमाओं का उल्लंघन करेंगे तो मैं नाम लूंगा।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किसानों को जो फसली ऋण मुफ्त ब्याज पर दिया जाता था, हमने तो उसमें भी कटौती कर दी। माननीय सदस्य का यह सरासर असत्य तथ्य है, यह बिल्कुल सही नहीं है। आपने यह जो बात रखी है, वह तथ्यों के विपरीत है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। हमने पिछले वर्ष से अल्पकालीन फसली ऋण की राशि में 1 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए अनुदान का भी प्रावधान किया है। साथ ही, हमने पशुपालक साथियों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी प्रारंभ की है। इसी प्रकार पूर्ववर्ती सरकार ने पानी के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हुए ईआरसीपी सहित प्रदेश की प्रमुख पेयजल परियोजनाओं को अटकाने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार ने अल्प समय में ही, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्य मंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में ईआरसीपी के लिए केन्द्र सरकार एवं मध्य प्रदेश के साथ एमओयू कर प्रथम चरण हेतु कार्यादेश भी जारी कर दिये हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रामकेश (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बहुत हो गया। बैठिये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): साथ ही, शेखावाटी अंचल के लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए यमुना जल समझौते के तहत केन्द्र सरकार, हरियाणा सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया जा चुका है।

ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार एवं सुधार

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा केवल बिजली की खरीद पर ध्यान दिया गया। राज्य में स्वयं के प्लांट्स की उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग करने पर

कोई ध्यान नहीं दिया गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह तो आप भी मानेंगे कि आपकी सरकार के पांच साल के कार्यकाल में एक भी पॉवर जनरेशन प्लांट की स्थापना नहीं हुई और आप सोलर ऊर्जा की बात करते हैं और यह भी सबको विदित है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के विशेष प्रयासों से अब राज्य 33 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने प्रधान मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को राज़ी करने में इस बजट का सत्यानाश कर दिया ...(व्यवधान)...

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): इसके साथ ही, गत सरकार के समय पूर्व से संचालित प्लांट्स का पीएलएफ भी मात्र 55.10 परसेंट रहा। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही राज्य के प्लांट्स की क्षमता के उपयोग पर पूर्ण ध्यान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पीएलएफ 70.32 प्रतिशत हो गया है। हमारी गत भाजपा सरकार ने केन्द्र सरकार की उदय योजना को राज्य में वर्ष 2015 से लागू कर विद्युत कंपनियों के बकाया ऋणों की 75 परसेंट, राशि 62 हजार 422 करोड़ रुपये अधिग्रहीत (टेकओवर) कर विद्युत कंपनियों का ऑपरेशनल और फाइनेंशियल टर्नअराउंड किया गया था, इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2018-19 में डिस्कॉम राशि 2 हजार 607 करोड़ रुपये के प्राफिट में थी। तत्पश्चात कांग्रेस सरकार की ऊर्जा क्षेत्र में अदूरदर्शी नीतियों के फलस्वरूप प्रदेश की डिस्कॉम्स एवं ऊर्जा क्षेत्र को अत्यन्त दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। इसी का परिणाम रहा कि वर्ष 2020-21 से डिस्कॉम्स पुन: घाटे की स्थिति में आ गये थे और दिसम्बर, 2023 तक डिस्कॉम का एक्यूमलेटेड लॉस राशि 1 लाख 1 हजार 215 करोड़ रुपये व बकाया ऋण राशि 91 हजार 767 करोड़ हमें विरासत में मिले। इतना घाटा।

हमारी सरकार ऊर्जा क्षेत्र में निरन्तर नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार द्वारा विगत कुछ समय में ही इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के विभिन्न पीएसयूज से एमओयूज किये जाकर उनको धरातल पर लाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे राज्य में सबको निर्बाध बिजली मिल सकेगी और साथ ही, डिस्कॉम्स की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा तथ्यों को तोड़-मरोड़कर रखने की श्रृंखला में बायतू से आने वाले सदस्य ने कहा कि कैप्टिव पॉवर प्लांट्स पर लगने वाला विद्युत शुल्क (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) समाप्त कर दी गयी। यहां मैं पुन: स्पष्ट करती हूं कि इसमें कैप्टिव पॉवर प्लांट्स पर लगने वाले विद्युत शुल्क को समाप्त नहीं किया गया है। मात्र कैप्टिव पॉवर प्लांट्स के ओक्सीलेरी एनर्जी कंजम्प्सन वाले भाग पर लगने वाले विद्युत शुल्क (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) को ही समाप्त किया गया है। लगता है, माननीय सदस्य ने पूर्व में ध्यान से पूरी बात नहीं सुनी। आप लोगों ने सुनी भी नहीं, पढ़ी भी नहीं। जो मर्जी आया, आप बोलते गये। बोलने के लिए बोलना पड़ता है, समझ में आता है, बोलना ही है, आप विपक्ष हैं, बोलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को दिन के समय दो बार बिजली ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठें। माननीय, यह उछल कर बोलने की जरूरत नहीं है। I will name you. आज मुझे मजबूरन बाहर निकालने के लिए कहना पड़ेगा। Mr. Bohra, Mind you. तीसरी बात कह रहा हूं, अब की बार यदि इस तरह किया तो मैं तुरन्त बाहर भेजने के लिए मजबूर होऊंगा।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को दिन के समय दो बार बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी, परन्तु उस पर अमल नहीं किया गया और वह कागजी घोषणा बनकर रह गयी। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि हम 2027 तक किसान भाइयों को दिन के समय भी बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

mdp/rtm/16.07.2024/18:20/3n

साथ ही जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

रिसर्जेंट राजस्थान

कांग्रेस सरकार द्वारा हमारे द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किये गये रिसर्जेंट राजस्थान की नकल करते हुए इंवेस्टमेंट राजस्थान समिट, 2022 आयोजित की गयी, जिसमें केवल थोथी चर्चाएं की गयीं। कुछ ग्रुप्स, कंपनीज से एमओयू किये गये, परंतु इन एमओयूज पर केवल कागजी कार्यवाही हुई। कोई एमओयू धरातल पर नहीं आया। कांग्रेस की सरकार सदा से ही मुंगेरी लाल के सपने दिखाने का काम करती है। आप बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, बहुत की हैं आपने, सपने भी दिखाए, समिट्स के नाटक भी किये, लेकिन काम क्या किया? यही कारण है कि आज सब लोग रो रहे हैं, सड़कों की हालत तो मैंने देखी है। क्या हालत करके छोड़ गये आप? फायनेंशियल स्थिति के बारे में बोलेंगे तो पता नहीं क्या आप लोगों ने कर दिया? जाते-जाते तो आपने कुछ भी नहीं छोड़ा।

हमारी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए नयी लैंड पॉलिसी लागू की है, जिससे राज्य की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी होने के साथ ही पर्यावरण में भी सुधार होगा। साथ ही हमने प्रदेश में बड़े उद्योगों के साथ ही एमएसएमई को बढ़ावा देने का कार्य प्रारम्भ से ही शुरु कर दिया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जैसे आम जनता के जीवन से जुड़े संवेदनशील विषय पर भी विपक्ष द्वारा जनता को यह कह कर गुमराह किया जा रहा है कि हमारे द्वारा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चलायी गयी स्वास्थ्य योजनाओं को बंद किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी हैल्थ फॉर ऑल के सिद्धांत पर कार्य करते हुए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाओं को और अधिक बेहतर कर मुख्य मंत्री आरोग्य योजना, (MAA योजना) में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के

लिए आईपीडी के साथ-साथ डे-केयर पैकेज, बच्चों के लिए पेड्रियाट्रिक पैकेज एवं अन्य पैकेजेज का रेशनालाइजेशन किया जा रहा है।

इसी क्रम में हम पब्लिक हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही विस्तार के लिए भी प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप हमने चिकित्सा एंव स्वास्थ्य के आधारभूत ढ़ांचे के विकास के लिए पहले पूर्ण बजट में ही नेशनल हैल्थ पॉलिसी, 2017 के निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक कुल व्यय का 8.26 परसेंट राशि 27 हजार 660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो गत सरकार के पांच वर्षो के औसत से लगभग 1.5 प्रतिशत अधिक है।

जनजाति क्षेत्र विकास (टीएसपी एरिया डवलपमेंट)

डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा जनजाति क्षेत्र (टीएसपी एरिया) में निवासरत हमारे जनजाति के भाई-बहिनों के लिए चिंता करते हुए कहा कि नरेगा में टीएसपी एरिया में हमारी सरकार ने 125 दिन मजदूरी के दिए थे, लेकिन आपकी सरकार के बनते ही उसको आपने 100 दिन कर दिया। मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि यह बिलकुल तथ्यहीन बात है। आज भी राज्य के एसटी बाहुल्य 8 जिलों की 47 पंचायत समितियों के जॉबकार्ड होल्डर परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा में 100 दिवस पूर्ण करने के उपरांत 50 अतिरिक्त दिवसों का रोजगार राज्य मद से उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी सरकार जनजाति क्षेत्र के विकास तथा वहां निवास करने वाले परिवारों की खुशहाली के लिए संवेदनशील है। इसी क्रम में हमारे द्वारा गोविन्द गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना भी प्रारम्भ की जा रही है।

पॉलिसीज एंड स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबको यह विदित है कि2014 में माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के आने से पहले पूरा देश पॉलिसी पेरालिसिस से जूझ रहा था। यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा विभिन्न स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स उदाहरणस्वरूप टैक्स रिफॉर्म्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनोमी आदि लाने के फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था को नयी दिशा प्राप्त हुई है। हमारी सरकार द्वारा भी इस नीति का अनुसरण करते हुए इस बजट में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी, एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, यूथ पॉलिसी, स्टेट स्किल पॉलिसी, राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी, राज निवेश पॉलिसी इत्यादि नई नीतियां लाकर सुधार सुनिश्चित कर रहे हैं।

हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था 'हमे जल्द से जल्द गुलामी की मानसिकता और गुलामी के प्रतीक चिन्हों को समाप्त कर, नये आत्म विश्वास से भरे, नये भारत की स्थापना करनी है। इसके अनुसरण में उन्होंने आज के समय में अनुपयोगी हो चुके पुराने आपराधिक कानूनों को हटाकर, उनके स्थान पर नवीन न्यायिक विधियों को लागू करवाया है। हम जो कहते हैं, वह करके भी दिखाते हैं। नये कानूनों में

पीड़ित को जल्दी न्याय उपलब्ध कराने और दोषी के स्थान पर पुनर्वास की भावना को प्रधानता दी गयी है। साथ ही महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के हितों को बढ़ावा देने के प्रावधानों को भी शामिल किया है।

बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी नकारात्मक सोच तो रखते ही है, साथ ही आमजन की श्रद्धा से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते। बजट पर बहस के दौरान कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी आदत के अनुसार धार्मिक स्थानों पर विकास कार्य करवाने की गत सरकार की कागजी घोषणा का ढोल बजाते हुए हमारे द्वारा वास्तव में जनता की आस्था को मूर्त रूप देने के प्रयासों पर भी बेमतलब की टिप्पणी की है। जैसा मैं बहुत बार कह चुकी हूं आप लोगों ने घोषणाएं की हैं, चाहे हम मंदिरों की बात करें, चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम किसी भी चीज की बात करें, घोषणाएं कीं, बहुत सारी बातें कीं, लेकिन अगेन धरातल पर कुछ नहीं उतरा। मंदिरों की बात की। इस मन्दिर में इतना क्यों दिया जा रहा है, इस मन्दिर में क्यों दिया जा रहा है और हमने इतना दिया था। वास्तविकता यह है कि आपने दिया पता नहीं क्या था, आपने सिर्फ बोला था, लेकिन काम धरातल पर बिलकुल नहीं हुआ। नाममात्र काम हुआ था। कई जगह पर तो कुछ भी काम नहीं हुआ।

मैं माननीय सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को उनकी खुशहाली के साथ ही उनके श्रद्धा स्थलों के विकास के लिए भी आश्वस्त करती हूं। हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रथम पूर्ण बजट राज्य को विकसित राज्य बनाने की दूरगामी सोच के साथ प्रस्तुत किया गया है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी की सरकार पहले साल से ही धरातल पर प्रदेश हित में काम कर रही है। मैं प्रदेश की जनता को सदन के माध्यम से यह आश्वस्त करती हूं कि हम यहां सेवा के लिए है और सर्वजन हिताय के भाव को केन्द्र बिंदु मानकर 12 दिसम्बर, 2023 अर्थात सरकार गठन के पहले दिन से ही राज्य के विकास में जी-जान से जुट गये हैं। हमारा यह ध्येय है कि प्रदेश के विकास में कोई कमी, कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जितने वायदे किए हैं, घोषणाएं की हैं, उससे अधिक काम होगा।

घोषणाएं:

1. माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं नवीन घोषणाएं प्रस्तावित कर रही हूं।

आधारभूत संरचना (Infrastructure) :

सड़क:

2. जनगणना 2011 के आधार पर निर्धारित आबादी के एक हजार से अधिक राजस्व गांवों को डामर सड़क से Connectivity उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

3. प्रदेश में सड़कों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की राशि से विभिन्न सड़क निर्माण कार्य 2 वर्षों में करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन सड़क कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हू। लंबी सूची है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

Ans/rtm 18.30 3o 16.07.2024

4. बाड़मेर जिले में अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित मुख्य सड़कों से वंचित सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 34 सैनिक चौकियों तक सुगम पहुंच बनाने एवं सैनिकों की सुविधा के लिए चरणबद्ध रूप से 48 करोड़ (अड़तालीस करोड़) रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण किया जायेगा। प्रथम चरण में, इस वर्ष 9 सैनिक चौकियों हेतु सड़क निर्माण का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

नगरीय विकास:

5. भिवाड़ी के सुनियोजित विकास के लिए Master Drainage Plan तैयार किया जाकर तथा अजमेर शहर में आनासागर के पास के क्षेत्र में नालों एवं Drainage सम्बन्धी कार्य हाथ में लिये जायेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्रीमती दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): 6.खींवसर-नागौर, डीग व शाहपुरा में रोडवेज बस स्टैण्ड सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे। ...(व्यवधान)...

पेयजल:

7. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 33 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य चरणबद्ध रूप से करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

इन कार्यों का विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

ऊर्जा :

8. विद्युत प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ एवं विकसित करने हेतु 132 केवी या उससे अधिक की High Tension Line के निर्माण हेतु आवश्यक टावर एवं Transmission Lines से किसानों की जमीन प्रभावित होती है। किसानों को ऐसी स्थिति में मैं, ऐसे Transmission Tower Base के साथ चारों तरफ एक मीटर तक अतिरिक्त क्षेत्रफल की गणना कर DLC दर का दुगुना तथा Transmission Line के नीचे आने वाले क्षेत्रफल के पेटे DLC की 30 प्रतिशत की दर से मुआवजा दिया जाने की घोषणा करती हूं।

9. Energy Audit के लिए 3 वर्षों में 4 लाख 34 हजार (चार लाख चौंतीस हजार) Distribution Transformers पर चरणबद्ध रूप से smart meters लगाये जायेंगे। इस वर्ष एक लाख से अधिक smart meters लगाये जाने प्रस्तावित हैं।

10. विद्युत प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमता के GSS स्थापित किये जायेंगे। ये GSS हैं-

इनका विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तत कर रही हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

औद्योगिक विकास:

11. प्रदेश में उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से नवीन RIPS योजना लाया जाना प्रस्तावित है। इसी के साथ उद्यमियों को समयबद्ध रूप से सहायता प्राप्त हो सके, इस हेतु RIPS Fund गठित कर आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे।

12. MSME उद्यमियों को common sampling एवं monitoring की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध रूप से संभाग मुख्यालयों सहित 20 स्थानों पर regional laboratories स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

13.राजस्थान वित्त निगम के वित्तीय सुदृढीकरण हेतु वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार एवं RIICO द्वारा 50-50 करोड़ रुपये की अंशपूंजी का सहयोग प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति:

14. भर्तृहरि धाम अलवर, अर्बुदा माता एवं अचलेश्वर महादेव मंदिर-माउंट आबू, द्वारिकाधीश जी मन्दिर-राजसमंद, नसियां जी विराटनगर-कोटपूतली बहरोड़, दिल्ली बाइपास स्थित तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा-जयपुर तथा बुड्डा जोहड़ गुरुद्वारा-अनूपगढ़ में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं विकास कार्य करवाये जायेंगे।

15. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 15 हजार यात्रियों को Special Train द्वारा अयोध्या स्थित राममंदिर के दर्शन करवाये जाना प्रस्तावित है।

16. देश के नवनिर्माण में हमारे महापुरुषों द्वारा दिये गये योगदान एवं उनके कार्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने हेतु उनकी जीवनी को प्रकाशित कराया जायेगा। प्रथम चरण में स्वामी विवेकानन्द एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के monographs प्रकाशित किये जायेंगे।

वन एवं पर्यावरण:

17.ब्राह्मणी नदी (बेगूं)-चित्तौड़गढ़ के River Front एवं सौन्दर्याकरण का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, अजमेर शहर में पार्क व आदर्शनगर में मातृवन विकसित किये जायेंगे।

शिक्षा एवं खेल:

18. प्रदेश में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए विभिन्न महाविद्यालयों की स्थापना व क्रमोन्नयन किये जाने, नवीन संकाय/विषय खोले जाने तथा विभिन्न छात्रावासों के निर्माण सम्बन्धी कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

इन कार्यों का विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

19. बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पॉलिटेक्निक/तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर उच्च शिक्षा की तर्ज पर इस वर्ष योग्यता/मेरिट के आधार पर 500 Scooty वितरित की जायेंगी।

20. महाविद्यालय तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठित कम्पनियों के माध्यम से Corporate Certification Programmes संचालित करने हेतु प्रदेश के सभी संभागों में Rajasthan Finishing School Centers की स्थापना किये जाने की घोषणा

करती हूं। इसके अन्तर्गत 3 वर्षों में लगभग 50 हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 60 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का व्यय होगा।

21. प्रदेश के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने तथा स्कूली शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से विभिन्न पाठ्यक्रम, विषय शुरू करने तथा स्कूलों व ICT Labs की स्थापना किये जाने सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे।

इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

22. विद्यार्थियों तथा आम जन में विज्ञान के प्रति रूचि व जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से-

I. अलवर एवं भरतपुर में विज्ञान केन्द्र की स्थापना का कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। इन पर लगभग 45 करोड़ (पैंतालीस करोड़) रुपये का व्यय होगा।

II. भरतपुर में 13 करोड़ रुपये की लागत से Digital Planetarium स्थापित किया जायेगा।

III. जयपुर में State Remote Sensing Application Centre (SRSAC) का उपकेन्द्र खोला जायेगा।

23. प्रदेश में NCC Cadets की संख्या में लगभग 11 हजार की वृद्धि की जाकर नागौर, जैसलमेर एवं बांसवाड़ा में NCC कार्यालय स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही, प्रदेश में Scouting को बढ़ावा देने के लिए Hindustan Scouts हेतु नियम बनाते हुए 4 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

24. शाहबाद-बारां में सहरिया जनजाति वर्ग हेतु तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी तथा अजमेर जिला मुख्यालय पर Athletics खेल अकादमी की स्थापना की जायेगी। साथ ही, कपासन-चित्तौड़गढ़ में Indoor Stadium बनाया जाना प्रस्तावित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

25. दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए 'मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना' प्रारम्भ कर 5 हजार रुपये मासिक सहायता दिये जाने की घोषणा करती हूं।

26. थैलेसीमिया (Thalassemia) से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार हेतु Haemotological Centre की स्थापना के साथ ही, मरीजों को बिना Replacement रक्त संचरण की सुविधा उपलबध कराये जाने हेतु 10 नये रक्त संग्रहण एवं परिहन उपलब्ध करवाये जायेंगे।

VPS-RTM-16.07.2024-18.40-3p

27. अजमेर, भरतपुर, केलवाड़ा-बारां, उदयपुर की औषधि निर्माण रसायन शालाओं का automation करते हुए नवीन मशीनें स्थापित की जायेंगी। इन पर 15 करोड़ रुपये का व्यय होना प्रस्तावित है। साथ ही, आयुर्वेद दवाइयों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जायेगा।

28. Breast Cancer (स्तन कैंसर) की जांच हेतु Mobile Vans की संख्या बढ़ाते हुए चरणबद्ध रूप से प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय पर उपलब्ध करवायी जायेगी। साथ ही, प्राथमिक स्तर की जांच के लिए समस्त ANM एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी training दी जानी प्रस्तावित है।

29. प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए चिकित्सा संस्थानों के upgradation, स्थापना, भवन निर्माण एवं repair व maintenance तथा आयुष चिकित्सा सुविधा कार्य करवाये जायेंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

सामाजिक सुरक्षा :

30. 'प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना' के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को देय राशि 6 हजार 500 रुपये को बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

31. राजीविका के अंतर्गत संचालित संकुल स्तरीय संगठनों के लिए कार्यालय भवन निर्माण, मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।

32. प्रदेश में Open Borewell के अन्दर गिरकर किसी शिशु/बालक को अपने प्राण न गंवाने पड़े, इस दृष्टि से समस्त पुराने तथा नये खुदने वाले Borewell की entry, Online Portal पर किया जाना अनिवार्य किया जायेगा तथा प्रत्येक Borewell के लिए जिम्मेदारी भी निर्धारित की जानी प्रस्तावित है।

33. माननीय सदस्यों को विदित है कि आज भी हमारे सफाई कर्मचारी किन विषम परिस्थितियों में कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में उनके स्वास्थ्य का समुचित ध्यान रखने की दृष्टि से RGHS के अन्तर्गत Lungs, Kidney एवं Skin आदि से सम्बन्धित बीमारियों के विशेष पैकेज निःशुल्क उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँ।

कृषि :

34. प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इन सिंचाई कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

35. 20 हजार किसानों को भूमि सुधार हेतु निःशुल्क जिप्सम उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

36. प्रदेश में कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक का प्रयोग बढ़ाने की दृष्टि से Centre of Excellence for Tissue Culture एवं State Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management (SIFTEM) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

37. प्रदेश में बापिणी (लोहावट)- फलौदी तथा कोटखावदा-जयपुर में कृषि उपज मण्डी स्थापित की जायेंगी।

38. प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधा के लिए विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले व क्रमोन्नत किये जायेंगे। इन संस्थानों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

39. प्रदेश की 100 गौशालाओं को रियायती दरों पर गौ काष्ठ मशीन उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँ।

40. साथ ही, डेयरी सेवाओं के विस्तार एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से-

1. 2 वर्षों में 2 हजार नये डेयरी बूथ खोले जायेंगे।

II. सरस दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की घर-घर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष शहरी क्षेत्रों में एक हजार सरस मित्र बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

III. अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के दुग्ध उत्पादकों को सहकारिता से जोड़ने के लिए 2 वर्षों में 1 हजार 500 नई दुग्ध सहकारी समितियां चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

सुशासन :

41. राजस्व न्यायालयों के न्यायिक कार्य हेतु Online Portal- Rajasthan Revenue Court Modernization System (RRCMS) लागू किया जायेगा। इस पर 5 वर्षों में लगभग 50 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, भूमि सीमाज्ञान, सहमति विभाजन, नामान्तकरण, गैर-खातेदारी से खातेदारी, भूमि की लीज आदि नामान्तकरण के Auto/Deemed निस्तारण हेतु Online Platform लागू किया जायेगा।

42. क्षेत्रीय कार्यालयों के coverage के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस इकाइयों एवं न्यायालयों की स्थापना व क्रमोन्नयन किया जायेगा। इन इकाइयों/ न्यायालयों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

43. युवाओं को नशे की लत लगे ही नहीं, इसके लिए जरूरी है कि नशीले पदार्थों के स्रोत व अवैध कारोबार को रोका जाये। इस दृष्टि से मैं, नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए Anti-Narcotics Task Force का गठन करने की घोषणा करती हूँ।

44. राजस्थान पुलिस को बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र का upgradation एवं विस्तार कर राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में स्थापना की जायेगी। साथ ही, पुलिस थानों में FIR से लेकर investigation तक का कार्य online सुचारु रूप से हो सके, इस हेतु शेष रहे 202 पुलिस थानों में भी Internet Connectivity सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

कार्मिक कल्याण :

45. केन्द्र के पेंशन नियमों के अनुरूप ही राज्य सरकार के कार्मिक की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य के नहीं होने पर स्थायी रूप से Specially Abled बच्चे और बच्चों, आश्रित माता-पिता और Specially Abled भाई बहन का नाम PPO में अंकित किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ।

46. Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत-

I. राजकीय उपक्रमों (स्वायत्तशासी संस्थाओं/बोर्ड/निगम/विश्वविद्यालय आदि) के RGHS कार्ड धारक कार्मिकों एवं पेंशनरों की Out Door चिकित्सा सुविधा व्यय की प्रतिवर्ष सीमा को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की घोषणा करती हूँ।

II. साथ ही, इन उपक्रमों के RGHS कार्ड धारक पेंशनरों की मृत्यु उपरान्त उनके पात्र आश्रितों को RGHS के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

III. वृद्ध पेंशनर्स को RGHS के अन्तर्गत Vitamins, Minerals एवं Anti-oxidants को अनुमत किया जाना प्रस्तावित है।

47. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को पुनः विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन व माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लालजी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश को विकास की ऊँचाइयों तक ले जाने में कोई कसर नहीं रखेगी। जनसामान्य के कल्याण के लिए शुरू की गई हमारी योजनाओं के माध्यम से अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का हम अथक प्रयास करेंगे। मैं, यहाँ आह्वान करना चाहूँगी-

"रूको न तुम, थको न तुम, राह से भटको न तुम
अपने अडिग विश्वास से, एक राह का संकल्प लो
ज्ञान से झुके रहो, विश्वास से डटे रहो
जीवन साकार जो करे, उस ज्ञान का संकल्प लो।।"

जय हिन्द।

श्री अध्यक्षः सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई 2024 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.48 बजे गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

...

परिशिष्ट 1

पैरा संख्या 03 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	सड़कें	लागत
1.	हरनावदाशाहजी से छीपाबड़ौद सड़क (23 किमी.) (छबड़ा)-बारां	40 करोड़ रुपये
2.	जायल उपखण्ड में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य-नागौर	11 करोड़ रुपये
3.	भदेसर व चित्तौड़गढ़ बाईपास निर्माण	88 करोड़ 50 लाख रुपये
4.	राजनौता (MDR-228) संतोषी माता मंदिर से बीलवाड़ी (NH-248A) धौलीकोठी तक वाया प्रेमनगर, सितोपसिंहपुरा, कैमरिया, टोरडा ब्राह्मण, रघुनाथपुरा (तालुकाबास), खरबूजी, सुरजपुरा, लुहाकना खुर्द, लुहाकना कलां (विराटनगर) -कोटपूतली बहरोड़ एवं NH-52 (ज्ञानपुरा) से सीकर जिला सीमा वाया काकराना, राजनौता, रघुनाथपुरा, भैसलाना, सुजातनगर, मीरापुर फार्म, दांतिल, तालवा रोड, सिरसोडी सीकर सीमा तक (MDR-228) (विराटनगर)-कोटपूतली बहरोड़ (30 किमी.)	45 करोड़ रुपये
5.	नारेला से भोपालसागर वाया भीमगढ़-राशमी-हरनाथपुरा सड़क के शेष कार्य भीमगढ़ बाईपास व हरनाथपुरा बाईपास (कपासन)- चित्तौड़गढ़ कपासन से दरिबा माईन्स वाया मालीखेड़ा- कानाखेड़ा -उसरोल-लुणेरा-कोटड़ी सड़क (30 किमी.) -चित्तौड़गढ़	22 करोड़ 40 लाख रुपये
6.	जमवारामगढ़ SH-55 से चौमुखा वाया पापड़ होते हुए: बैनाड़ा मोड/आगरा रोड तक सड़क निर्माण कार्य -जयपुर	30 करोड़ रुपये
7.	चाकसू, पुराने नेशनल हाईवे-12 का मय डिवाईडर सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण तथा कोटखावदा मोड़ से बाईपास एवं गरूड़वासी तिराहा से बाईपास निर्माण कार्य (21 किमी.) -जयपुर	38 करोड़ 52 लाख रुपये
8.	कपासन से दरिबा माईन्स वाया मालीखेड़ा- कानाखेड़ा -उसरोल-लुणेरा-कोटड़ी सड़क (30 किमी.) -चित्तौड़गढ़	50 करोड़ रुपये
9.	नगर में बाईपास निर्माण (7 किमी.) - डीग	60 करोड़ रुपये
10.	ढिगाल मुख्य बस स्टैण्ड से कुल्हरियों की ढाणी-रघुनाथपुरा सीमा, बीबासर सड़क से प्राथमिक स्कूल-भैरिवाला जोहड़, माण्डासी-चौराड़ी, कुल्हरियों घर-राजपूतों की ढाणी, जांटवाली आम चौक-भींवसरी, बालाजी मंदिर, चुड़ी, घोड़ीवारा खुर्द-मोहब्बतसरी, सोटवारा सीमा, सेंसवास सीमा, रेलवे फाटक (27.35 किमी.) (नवलगढ़)-झुंझुनूं	8 करोड़ 30 लाख रुपये
11.	मुकुन्दगढ़ वार्ड नं. 08/09-सीकर बॉर्डर, कसेरू सड़क-रेलवे	3 करोड़ 89

	प्लेटफार्म, नाईयों की फैक्टरी, गुंवारियों का मोहल्ला, चेजारों का मोहल्ला, डुण्डलोद फाटक- माताजी की ढाणी, कुमावास मुख्य सड़क-कब्रिस्तान, दुदाना का बास-बजरंग दतुसलिया के घर, देवगांव नुआँ-डुमरा, बलरिया-नाहरसिंघानी, तोगड़ा कलां से शिशियां, डाबड़ी बलौदा (12.35 किमी.) (नवलगढ़)- झुंझुनूं	लाख रुपये
12.	ब्यावर रोड डीएवी हॉस्टल से आनासागर एस्केप चैनल तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य (वाया रामगंज से गढ़ीमालियान)-अजमेर	11 करोड़ 50 लाख रुपये
13.	श्रीनगर रोड से टैम्पू स्टैण्ड तक जे.पी. नगर मुख्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर सुदृढ़ीकरण एवं नाली व फुटपाथ का कार्य-अजमेर	10 करोड़ रुपये
14.	खैराबाद से गोयन्दा सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (7.50 किमी.) (रामगंजमण्डी)-कोटा	18 करोड़ 75 लाख रुपये
15.	खींवसर-महेशपुरा-कांटिया-आचीणा-देऊ गांव से दांतीणा सड़क (32 किमी.) (खींवसर)-नागौर	16 करोड़ रुपये
16.	जोरावरपुरा-गुड़िया-हमीराणा-आकला (15 किमी.) (खींवसर)-नागौर	7 करोड़ 50 लाख रुपये
17.	मोठियापुरा से जगर वाया हरिरामपुरा सड़क चौड़ाईकरण (17 किमी.)-करौली	22 करोड़ रुपये
18.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-113 मुख्य सड़क से गांव महुड़िया-बागदरी तक सड़क निर्माण (5.20 किमी.) (निम्बाहेड़ा)-चित्तौड़गढ़	5 करोड़ रुपये
19.	सीकर रोड पर जैतपुरा से जयसिंहपुरा बाईपास निर्माण (16 किमी.) (चौमूं)- जयपुर	130 करोड़ रुपये
20.	दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस हाईवे से मालाखेड़ा तक (25 किमी.)-अलवर	18 करोड़ रुपये
21.	रावतसर के प्रेमनगर से थालडका तक सड़क (9 किमी.) (पीलीबंगा)-हनुमानगढ़	4 करोड़ 50 लाख रुपये
22.	पीलीबंगा से गोलूवाला वाया लोंगवाला-अयालकी सड़क (18 किमी.) (पीलीबंगा)-हनुमानगढ़	26 करोड़ 50 लाख रुपये
23.	SH-24 से NH-11AE वाया नांगल मोड, देवली रोड 6 (लालसोट बाईपास) नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण (6. ल 1 किमी.)- दौसा	6 करोड़ 10 लाख रुपये
24.	हनुमानगढ़-पदमपुर सड़क (ग्राम बींझबायला) में सीसी 7 सड़क मय नाली निर्माण कार्य (2 किमी.)	7 करोड़ रुपये

25.	बांदीकुई बाईपास निर्माण कार्य नन्देरा SH-78 से 2 अनन्तवाडा, भाण्डेडा सीमा-दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे से होते हुए कांच की ढाणी SH-25 (सिकन्दरा-अलवर मेगा हाईवे) पीचूपाडा तक सड़क-दौसा (8 किमी.)	25 करोड़ रुपये
26.	आगरा फाटक-सैनी स्कूल सरस्वती शिक्षा निकेतन से 6 पंचमुखी रेलवे फाटक तक वाया झालानी बगीची (शहरी सड़क)(4 किमी.)-दौसा	6 करोड़ 50 लाख रुपये
27.	रूदावल से बंशी पहाड़पुर (8.60 किमी.), (बयाना)-भरतपुर	10 करोड़ रुपये
28.	नसीराबाद-सरवाड-केकड़ी-देवली सड़क को 4 लेन बनाना (96 किमी.) - अजमेर, केकड़ी, टोंक	650 करोड़ रुपये
29.	कुश्तला-सवाई माधोपुर सड़क का चौड़ाईकरण (8 किमी.)	90 करोड़ रुपये
30.	निम्बाहेड़ा से मंगलवाड फोर लेन सड़क निर्माण कार्य (41 किमी.) (निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़)	325 करोड़ रुपये
31.	देवली को बीसलपुर व टोडारायसिंह होते हुए जयपुर को जोड़ने वाली सड़क पर बनास नदी पर पुलिया निर्माण-टोंक	147 करोड़ रुपये
32.	फतेहपुर से गोडियाबड़ा से ठेड़ी लावंडा ताखलसर-रामगढ़ (21 किमी.) (फतेहपुर)-सीकर	16 करोड़ 80 लाख रुपये
33.	देवरी क्षेत्र की सड़कों का डामरीकरण (7 किमी.) (किशनगंज)-बारां	10 करोड़ रुपये
34.	श्रीमाधोपुर-नीमकाथाना की विभिन्न नॉनपेचेबल सड़कों का नवीनीकरण	7 करोड़ रुपये
35.	अमरपुरा चौराहे से बांसी होते हुए जिला सीमा तक (12 किमी.) - चित्तौड़गढ़	10 करोड़ रुपये
36.	मीठियावास-टपूकड़ा से जनकसिंहपुरा (नीमराणा) (भिवाड़ी-नीमराणा लिंक रोड) की DPR (खैरथल से तिजारा)	10 करोड़ रुपये
37.	आदर्श बस्ती नांद सड़क से बिशाला आगौर सरहद तक (5 किमी.) - बाड़मेर	2 करोड़ रुपये
38.	सोनड़ी रोड से पुरसिंह पुरा (बिशाला तक) (5 किमी.) - बाड़मेर	2 करोड़ रुपये

परिशिष्ट 2

पैरा संख्या 7 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	पेयजल सम्बन्धी कार्य	लागत
1.	लूणकरणसर के ग्रामों-कतरियासर, मालासर लाडेरा, मोलानिया एवं करणीसर बीकान में पेयजल योजना के सुदृढीकरण एवं पुनरुद्धार कार्य	16 करोड़ 50 लाख रुपये
2.	जैतारण-ब्यावर में कलालिया, बगड़ी, कोटकिराणा, काणुजा ग्रामी पंचायतों को भोमादा बांध पेयजल स्कीम से जोडने सम्बन्धी कार्य की DPR	50 लाख रुपये
3.	सोजत, मारवाड़ जंक्शन एवं जैतारण क्षेत्र के 175 ग्रामों की पेयजल आपूर्ति निर्बाध करने हेतु बागावास तालाब में आरडब्ल्यूआर मय पम्प हाउस निर्माण कार्य-पाली	14 करोड़ 60 लाख रुपये
4.	सुथारों की ढाणी, इन्द्रनगर फतेहसागर, डुडियों की ढाणी (सदरी) तथा पुनियों की ढाणी (नौसर) (लोहावट)-फलौदी में टंकी निर्माण कार्य	1 करोड़ 50 लाख रुपये

परिशिष्ट 3
पैरा संख्या 10 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	जीएसएस
1.	33 केवी जीएसएस- रसिया-डीग, पुंदलोता (डेगाना)-नागौर, मियाला (भीम)-राजसमंद, पांचोली (सिकराय)-दौसा, अटारी (नदबई)-भरतपुर, दरीबा, शिवरती (सहाड़ा)-भीलवाड़ा, नेतरा एवं रोजड़ा के मध्य (सुमेरपुर)-पाली
2.	132 केवी जीएसएस- हरनावदाशाहजी (छीपाबड़ौद)-बारां, सायरा (गोगुन्दा)-उदयपुर, भादसोडा (कपासन)-चित्तौड़गढ़, अंजारी डंगीका-डीग, खुडियाला (शेरगढ़)-जोधपुर, बान्दनवाड़ा (भिनाय)-केकड़ी, बहरावण्डा खुर्द (खंडार) सवाई माधोपुर

परिशिष्ट 4

पैरा संख्या 18 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक
1.	नवीन महाविद्यालय-भदेसर-चित्तौड़गढ़, किठाना (चिड़ावा)-झुंझुनूं
2.	नवीन कन्या महाविद्यालय-बालेसर-जोधपुर, भगवतगढ़ (खंडार)-सवाई माधोपुर
3.	UG से PG में क्रमोन्नयन-कन्या महाविद्यालय, लालसोट-दौसा
4.	नवीन विषय/संकाय- पुष्कर-अजमेर में दर्शनशास्त्र एवं विज्ञान संकाय, बालोतरा में स्नातकोत्तर स्तर पर लोक प्रशासन विषय भरतपुर महाविद्यालय में नवीन विषय
5.	पॉलिटेक्निक महाविद्यालय-भिवाड़ी
6.	विभिन्न छात्रावास- नसीराबाद-अजमेर में देवनारायण बालिका छात्रावास; नदबई-भरतपुर में EWS छात्रावास; निम्बोल (जैतारण)-ब्यावर में अनुसूचित जाति छात्रावास

परिशिष्ट 5

पैरा संख्या 21 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	कार्य विवरण
1.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में BBA एवं संभाग स्तर पर MBA Course
2.	समस्त संभाग मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों (उदयपुर में कन्या महाविद्यालय) में BCA एवं चरणबद्ध रूप से MCA Course
3.	सभी जिला मुख्यालय पर स्थित महाविद्यालयों में Computer Science विषय
4.	जिला स्तर पर Foreign Language Communication Skill Scheme के तहत French, German, Spanish, Japanese, Italian, Russian आदि भाषाओं में Certificate Courses करवाये जाने की सुविधा
5.	राज्य में संचालित 134 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में प्राइमरी कक्षाओं का संचालन
6.	प्रदेश के 591 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऐच्छिक विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान विषय
7.	राज्य में नये 46 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु 25 करोड़ 52 लाख रुपये का व्यय
8.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 200 से अधिक नामांकन होने पर चरणबद्ध रूप से ICT Labs की स्थापना

परिशिष्ट 6

पैरा संख्या 29 में उल्लिखित सूची

क्र सं.	चिकित्सा संस्थान/कार्य
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन- खींवसर-नागौर
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन- छोटी सादड़ी-प्रतापगढ़, देचू-फलौदी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नयन- अकलेरा (मनोहरथाना)- झालावाड़ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नयन-कोटड़ा-अजमेर नवीन सैटेलाइट-करौली
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन- गुन्दोज-पाली, ढीगाल (नवलगढ़) झुंझुनूं, देवरी-बारां, भाड़ौती- सवाई माधोपुर
4.	नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- चान्दारुण (डेगाना)-नागौर, अनन्तपुरा-जैतपुरा (चौमूं)-जयपुर
5.	उप स्वास्थ्य केन्द्रों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन- भीमगढ़ (राशमी), आक्या-चित्तौड़गढ़, नेगडिया खेड़ा (सहाड़ा)- भीलवाड़ा, चन्दीपुर (मनोहरथाना)- झालावाड़, राजमथाई (पोकरण)- जैसलमेर, बगड़ी (लक्ष्मणगढ़) सीकर, नकोंर (धमोतर)-प्रतापगढ़
6.	नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र- आछोजाई (डेगाना)-नागौर, शिवनाथसिंह नगर (पोकरण)-जैसलमेर, मुले का तला-बाड़मेर
7.	बेड क्षमता एवं भवन निर्माण- सामुदायिक चिकित्सालय भिनाय-केकड़ी की बेड क्षमता 50 करना; जिला चिकित्सालय-बारां के आईपीडी ब्लॉक का जीर्णोद्धार कार्य
8.	ट्रोमा सेंटर-शाहपुरा; सिकराय दौसा, फतहनगर व मावली- चित्तौड़गढ़ के मध्य
9.	आयुर्वेद औषधालय, भीम-राजसमंद का चिकित्सालय में क्रमोन्नयन

परिशिष्ट 7
पैरा संख्या 34 में उल्लिखित सूची

क्र सं.	सिंचाई कार्य	लागत
1.	बागोलिया बांध फीडर निर्माण कार्य(मावली)-चित्तौड़गढ़	190 करोड़ रुपये
2.	निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़ में निम्बोदा लघु सिंचाई परियोजना का कार्य	20 करोड़ रुपये
3.	रामगंजमण्डी के कुण्डाल क्षेत्र में सिंचाई परियोजना बनाकर 24 गांवों की कुल 8 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु डीपीआर	40 लाख रुपये
4.	पाटली नदी (रामगंजमण्डी) कोटा की डिसिल्टिंग का कार्य	5 करोड़ रुपये
5.	चम्बल दांयी मुख्य नहर की शेष रही लगभग 56 किलोमीटर लम्बाई में पक्की लाइनिंग के कार्य चरणबद्ध रूप से आगामी 4 वर्षों में करवाया जाना प्रस्तावित है। जिससे दांयी मुख्य नहर के कमाण्ड क्षेत्र में आने वाले राजस्थान के कोटा एवं बारां जिलों के 473 गांवों की एक लाख 27 हजार हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र के लगभग एक लाख 80 हजार किसान लाभान्वित होंगे।	862 करोड़ रुपये
6.	चम्बल कमाण्ड क्षेत्र-कोटा, बूंदी एवं बारां के सिंचित क्षेत्र की दक्षता सुधार हेतु वितरिकाओं एवं माईनरों में शेष रही लगभग 167 किलोमीटर लम्बाई में पक्की लाईनिंग एवं 11 हजार 746 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में खेत सुधार कार्य चरणबद्ध रूप से आगामी 3 वर्षों में करवाये जाना प्रस्तावित है। जिससे इन जिलों के 685 गांवों के लगभग 70 हजार 341 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र के लगभग 2 लाख 90 हजार किसान लाभान्वित होंगे।	353 करोड़ 37 लाख रुपये

परिशिष्ट 8

पैरा संख्या 38 में उल्लिखित सूची

क्र सं.	पशु चिकित्सा संस्थान/कार्य
1.	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन- बायतु-बालोतरा, आहोर-जालोर, बड़ी सादड़ी-चित्तौड़गढ़, मेड़ता-नागौर, सुमेरपुर, बाली-पाली, नवलगढ़-झुंझुनूं एवं केकड़ी सहित 25 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय
2.	पशु चिकित्सालयों का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन- कडैल, बूबानी (पुष्कर) अजमेर, सालोड़ी, मोगडा (लूणी), खारिया मीठापुर (बिलाड़ा), नेवरा रोड (ओंसिया)-जोधपुर, निम्बाज (जैतारण)-ब्यावर, हेलक-डीग, हिराता (दोवडा)- डूंगरपुर, गन्धेली (रावतसर)- हनुमानगढ़, हाडेचा, हजरी (आहोर)-जालोर, खिरोड (नवलगढ़)-झुंझुनूं, लखा पस फतेहगढ़-जैसलमेर, देवली मांझी (सांगोद)-कोटा, कुडगांव (सपोटरा) - करौली, चिकारडा (बड़ी सादड़ी)-चित्तौड़गढ़, सोरडा (रेवदर) - सिरोही, हरसाणी (शिव)- बाड़मेर, डांगावास (मेड़ता) - नागौर, बहरावण्डा (खण्डार)- सवाई माधोपुर, भोजपुर (ब्रहसिंहपुरा) (खंडेला) - सीकर, भारजा, जावाल- सिरोही, बीरमाना (सूरतगढ़) - श्रीगंगानगर एवं रूपावास (सुमेरपुर), देवलीकलां (सोजत)-पाली सहित 50 पशु चिकित्सालय

परिशिष्ट 9
पैरा संख्या 42 में उल्लिखित सूची

क्र सं.	इकाइयों/कार्यालयों की स्थापना/क्रमोन्नयन
1.	ऊर्जा विभाग- गोल्याणा (नवलगढ़) - झुंझुनूं में नया सहायक अभियंता (ग्रामीण) (विद्युत) का कार्यालय
2.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग- नाथडाऊ में सहायक अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) एवं सिवाना-बालोतरा में अधिशाषी अभियंता (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) का कार्यालय
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग- तिजारा में उपखण्ड कार्यालय (सार्वजनिक निर्माण) का खण्ड कार्यालय में क्रमोन्नयन
4.	नवीन नगर पालिका- टांटोटी-केकड़ी, तिंवरी (ओसियां)- जोधपुर, धौरीमन्ना-बाड़मेर नगर पालिका का उच्च श्रेणी में क्रमोन्नयन- नगर-डीग नगर पालिका
5.	पुलिस थाना-अजमेर (दक्षिण), भिवाड़ी (साइबर थाना), बंध बरेठा (बयाना)-भरतपुर पुलिस चौकी जैरोली-भिवाड़ी का पुलिस थाने में क्रमोन्नयन
6.	पुलिस चौकी- बासबुर्जा-डीग नई सड़क दरगाह अजमेर अस्थायी पुलिस चौकी को स्थायी पुलिस चौकी
7.	अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय- छोटी सादड़ी-प्रतापगढ़